epaper.dehatsandesh.com

3 लद्दाख में स्वदेशी,स्वावलंबन और संस्कृति का तीन दिवसीय उत्सव

5 सरकार को फोकस युवाओं के कौशल, नेतृत्व और मानसिक स्वास्थ्य पर: मांडविया

8 भूमि का मृदा परीक्षण

न्यूनतम 9 मौसम जम्मू अधिकतम 17

E-mail: dehatsandesh@gmail.com

देहात संदेश

जम्मू-कश्मीर का एकमात्र ग्रामीण दैनिक

वर्ष-22, जम्मू तवी, अंक-302 | जम्मू तवी, बुधवार 10 दिसम्बर, 2025 | मूल्य-3 रूपये- (लेह) 4 रूपये | पृष्ठ -8

व्यवस्था सुधारने के नाम पर लोगों को अनावश्यक रूप से परेशान नहीं किया जाना चाहिएः मोदी

नयी दिल्ली, 09 दिसंबर । प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मंगलवार को कहा कि व्यवस्था सुधारने के नाम पर लोगों को अनावश्यक रूप से परेशान नहीं किया जाना चाहिये ।श्री मोदी ने संसद परिसर में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) की संसदीय दल की बैठक में कहा कि नियम और कानून जरूरी है लेकिन व्यवस्था को सुधारने के नाम पर जनता को असुविधा देना उचित नहीं है। किसी भी हाल में लोगों को परेशान नहीं किया जाना चाहिए। किसी भी कानून या नियम में ऐसा प्रावधान नहीं होना चाहिए जिससे आम आदमी को परेशानी हो।

प्रधानमंत्री ने कहा कि देश अब पूरी तरह रिफॉर्म एक्सप्रेस के चरण में है, जहाँ सुधार तेज, स्पष्ट और नागरिक-केंद्रित हैं। उनका कहना था कि सरकार का लक्ष्य लोगों की रोजमर्रा की परेशानियों को दूर करना है, ताकि वे अपनी पूरी क्षमता के साथ आगे बढ़ सकें।

बैठक के बाद श्री संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू ने बताया कि प्रधानमंत्री ने तीसरी पारी में सुधारों पर जोर दिया है और ॉ अब मोदीजी की रिफॉर्म एक्सप्रेस चल चुकी है और से रूकने वाली नहीं है। सभी हर स्तर पर इसी दिशा में काम करेंगे। श्री मोदी ने बैठक के बाद एक्स हैंडल पर एक पोस्ट में लिखा कि संसद में राजग सांसदों के साथ हुयी बैठक में सुशासन को मजबूत करने और विकसित भारत के लक्ष्य पर सकारात्मक चर्चा हुयी। बैठक को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार का उद्देश्य अनावश्यक पेपरवर्क और लंबे फार्म की व्यवस्था को समाप्त करना है। उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि नागरिकों को उनके द्वार पर सेवा मिले और उन्हें बार-बार अपना अपने कागज जमा न करना पड़े। उन्होंने कहा कि सरकार नागरिकों की जिंदगी आसान बनाने के लिए तेज गति से सुधार कर रही है।

बैठक में प्रधानमंत्री ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सराहना करते हुये उन्हें बिहार जीत का शिल्पकार बताया। श्री मोदी ने श्री कुमार के दसवीं बार मुख्यमंत्री बनने को उन्होंने एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया।

उन्होंने यह भी कहा कि सरकार ने नागरिकों पर भरोसा दिखाते हुए स्व प्रमाणन की सुविधा दी और यह व्यवस्था पिछले दस वर्षों से बिना किसी समस्या के काम कर रही है ।संसदीय दल की बैठक में बिहार में गठबंधन की प्रचंड जीत पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को माला पहनाकर सांसदों ने स्वागत किया। यह बैठक संसद के पुस्तकालय भवन में आयोजित हुयी।

इंडिगो पर सरकार सख्त, उड़ानों में 10 फीसदी की कटौती, रिफंड, लगेज और यात्री सुविधा को लेकर सख्त आदेश

नई दिल्ली, 09 दिसंबर। इंडिगो संकट पर सरकार ने सख्त कार्रवाई की है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने एयरलाइन को उड़ानों में 10 फीसदी की कटौती करने का आदेश दिया है। इसके साथ ही कंपनी को ये कहा गया है कि वो यात्रियों सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए रिफंड और लगेज जल्द से जल्द वापस लौटाए।

केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री के राम मोहन नायडू ने मंगलवार को 'एक्स' पोस्ट पर जारी एक बयान में कहा कि देशभर में बड़े पैमाने पर फ्लाइट कैंसिल की अफरा-तफरी के बीच ऑपरेशन को स्थिर करने के लिए केंद्र ने इंडिगो के रूट्स में 10 फीसदी की कटौती की है। इससे पहले इंडिगो के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) पीटर एल्बर्स ने राम मोहन नायडू से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान पीटर एल्बर्स नागरिक उड्डयन मंत्री के सामने हाथ जोड़े नजर आए।

राम मोहन नायडू ने आगे लिखा, नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने इंडिगो को अपने कुल रूट्स में 10 फीसदी की कटौती करने का ऑर्डर दिया है। उन्होंने कहा कि इससे एयरलाइन के ऑपरेशन्स को स्टेबल करने और आगे कैंसिलेशन कम करने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि पिछले हफ्ते इंडिगो के क्रू-मेंबर रोस्टर, फ्लाइट शेड्यूल और कम्युनिकेशन की कमी के कारण कई यात्रियों को बहुत परेशानी हुई। इसको लेकर जहां जांच और जरूरी कार्रवाई चल रही है, वहीं, एयरलाइन के टॉप मैनेजमेंट के साथ स्टेबिलाइजेशन उपायों का रिव्यू करने के लिए एक और बैठक हुई।

मंत्री ने बताया कि इंडिगो के सीईओ पीटर एल्बर्स को अपडेट देने के लिए मंत्रालय में बुलाया गया था। उन्होंने कन्फर्म किया कि 06 दिसंबर तक जिन फ्लाइट्स पर असर पड़ा था, उनके 100 फीसदी रिफंड पूरे हो गए हैं। इसके बाद बाकी रिफंड और बैगेज हैंडओवर को तेजी से पूरा करने का सख्त निर्देश दिया गया।

इंडिगो की 1800 से ज्यादा उड़ानों का संचालन बहाल

नई दिल्ली, 09 दिसंबर। कई दिनों के संकट के बाद एयरलाइन इंडिगो ने कहा है कि नेटवर्क में लगातार कई दिनों से सुधार के बाद उसकी सभी उड़ान सेवाएं अब सामान्य हो चुकी हैं। वेबसाइट पर प्रकाशित सभी उड़ानें अब समायोजित नेटवर्क के तहत नियमित रूप से संचालित होंगी।

कंपनी के मुताबिक मंगलवार को 1800 से अधिक उड़ानें संचालित कर रही है, जो नेटवर्क में मौजूद सभी 138 स्टेशनों को जोड़ती हैं। बुधवार को लगभग 1900 उड़ानें संचालित करने की योजना है। कंपनी ने बताया कि हवाई अड्डों पर फंसे लगभग सभी बैग यात्रियों को लौटा दिए गए हैं। बचे हुए बैग जल्द पहुंचाने का काम तेजी से जारी है। इंडिगो ने रद्दीकरण पर बिना किसी सवाल के पूरी रकम वापसी की प्रक्रिया भी आसान कर दी है।

चार ड्रग पेडलर्स गिरफ्तार, प्रतिबंधित पदार्थ बरामद

श्रीनगर, 09 दिसंबर । समाज से ड्रग्स की बुराई को खत्म करने की अपनी कोशिशों को जारी रखते हुए जम्मू और कश्मीर पुलिस ने बारामूला और अवंतीपोरा में चार ड्रग पेडलर्स को गिरफ्तार किया है और उनके पास से प्रतिबंधित पदार्थ बरामद किया है।

बारामूला में एसएसपी बारामूला, एडिशनल एसपी हेडक्वार्टर बारामूला और एसएचओ पुलिस स्टेशन बारामूला की कड़ी निगरानी में एक पुलिस पार्टी ने जीएमसी बारामूला पार्किंग एरिया के पास एक टारगेटेड ऑपरेशन किया। ऑपरेशन के दौरान टीम ने दो संदिग्ध लोगों को पकड़ा जिनकी पहचान ताहिर अहमद खान बेटे अमर ज़मान खान और एक महिला के रूप में हुई, दोनों त्रिकांजन बोनियार के रहने वाले थे।

उनकी तलाशी के दौरान पुलिस को कुल 964 ग्राम हेरोइन जैसा पदार्थ मिला जो दो पैकेट में पैक था जिनका वज़न क्रमशः 424 ग्राम और 540 ग्राम था। इस प्रतिबंधित पदार्थ की कीमत गैर-कानूनी बाज़ार में लगभग 1 करोड़ रुपये है। इसके अलावा उनके पास से दो मोबाइल फ़ोन और एक गाड़ी (टाटा पंच रजिस्ट्रेशन नंबर जेके05एल-7844) ज़ब्त की गई।

पुलिस के बयान में कहा गया है कि इसके अनुसार पुलिस स्टेशन बारामूला में कानून की संबंधित धाराओं के तहत एफआईआर नंबर 214/2025 के तहत मामला दर्ज किया गया है और आगे की जांच चल रही है।

अवंतीपोरा में एसएचओ पुलिस थाना पंपोर की लीडरशिप में पुलिस स्टेशन पंपोर की एक पुलिस पार्टी ने कदलाबल पंपोर चौक पर नाका चेकिंग के दौरान एक गाड़ी (केयूवी100 एनएक्सटी के2 (ब्लैक)) को रोका जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर जेके04एफ-4498 था और उसमें दो लोग सवार थे। तलाशी के दौरान उनके पास से 37.740 भूक्की बरामद हुई। दोनों आरोपियों की पहचान जहांगीर अहमद डार बेटे अब्दुल राशिद डार निवासी कंदौर खानसाहब बडगाम; और मुश्ताक अहमद डार बेटे अब्दुल रजाक डार निवासी पालपोरा बडगाम के रूप में हुई है, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है और पुलिस स्टेशन ले जाया गया है

जलवायु परिवर्तन से कृषि पर आए संकट से निपटने के उपाय कर रही है सरकार : शिवराज चौहान

नयी दिल्ली, 09 दिसंबर । केंद्र सरकार ने कहा है कि जलवायु परिवर्तन के कारण कृषि को होने वाले नुकसान को लेकर सरकार जरूरी कदम उठा रही है और इसके लिए जो वैज्ञानिक उपाय हो सकते हैं उनके जरिए किसानों की मदद की जा रही है ।लोकसभा में कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार को एक पूरक प्रश्न के जवाब में कहा कि सरकार को नारियल किसानों की चिंता है और उन्हें हर तरह से मदद देने का काम किया जा रहा है।

यदि चक्रवात जैसे कारण से नारियल के पेड़ उखड़ते हैं तो वहां नारियल के पेड़ लगाने की व्यवस्था की जा रही है और इसमें राज्य सरकार को जो भी जरूरत होती है उसे उपलब्ध कराया जाएगा।

मुख्य सचिव ने जम्मू-कश्मीर के सभी जीएमसी में एमबीबीएस और पीजी सीटों के विस्तार पर दिया ज़ोर

जम्मू, 9 दिसंबर । मुख्य सचिव अटल डुल्लू ने आज जम्मू-कश्मीर में हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन (एचएंडएमई) डिपार्टमेंट द्वारा सरकारी मेडिकल कॉलेजों (जीएमसी), डेंटल कॉलेजों, आयुर्वेदिक और यूनानी कॉलेजों में अंडरग्रेजुएट और पोस्टग्रेजुएट सीटों को बढ़ाने के काम की समीक्षा करने के लिए एक बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी; स्कीम्स के डायरेक्टर; सरकारी मेडिकल कॉलेजों के प्रिंसिपल; कोऑर्डिनेशन के डायरेक्टर; और डिपार्टमेंट के दूसरे सीनियर अधिकारी शामिल हुए। बैठक के दौरान मुख्य सचिव ने पिछले एकेडमिक ईयर में बढ़ाई गई एमडी/एमएस डीएम/एमसीएच, डीएनबी और एमडीएस सीटों का डिटेल में मूल्यांकन किया और आने वाले सेशन में और बढ़ाने के लिए मेडिकल कॉलेजों द्वारा तैयार किए गए रोडमैप की समीक्षा की। जम्मू-कश्मीर में सुपर-स्पेशियलिटी हेल्थ केयर को मजबूत करने की ज़रूरत पर ज़ोर देते हुए उन्होंने दो सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल और स्कीम्स मेडिकल कॉलेज को अगले एकेडमिक सेशन से डीएम और एमसीएच सीटों का अलॉटमेंट पक्का करने का निर्देश दिया।

जम्मू-कश्मीर में ट्रांसपोर्टरों ने 15 दिसंबर को टोकन हड़ताल का ऐलान किया

जम्मू, 9 दिसंबर। जम्मू-कश्मीर में परिवहन क्षेत्र के लोग सरकार की अनदेखी के खिलाफ एक बार फिर आवाज उठा रहे हैं। जम्मू-कश्मीर ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन ने 15 दिसंबर को अपने लंबित मांगों को लेकर एक दिवसीय टोकन हड़ताल का ऐलान किया है।

शेख मोहम्मद यूसुफ, महासचिव जम्मू-कश्मीर ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन ने श्रीनगर में प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि जम्मू और कश्मीर दोनों डिवीजनों के ट्रांसपोर्टर एकमत होकर 15 दिसंबर को हड़ताल करेंगे। उन्होंने कहा कि ई-बसों का अव्यवस्थित संचालन, फिटनेस और ग्रीन टैक्स में भारी वृद्धि, और मनमाने ई-चालान के चलते परिवहन क्षेत्र ॉसंकट के कगारॉ पर है। सरकार की चुप्पी और इन समस्याओं पर कोई कार्रवाई न करना ट्रांसपोर्टरों को हड़ताल पर मजबूर कर रहा है।

यूसुफ ने कहा कि हड़ताल के बाद सरकार को सात दिन की अल्टीमेटम दी जाएगी। यदि इस अवधि में उनकी मांगें पूरी नहीं की गईं, तो ट्रांसपोर्टर महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए मजबूर हो सकते हैं।

उमर ने शहरी विकास परियोजनाओं की समीक्षा की

जम्मू तवी, 9 दिसंबर। जम्मू और कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने मंगलवार को शहरी विकास प्रोजेक्ट्स का रिव्यू किया और निर्देश दिया कि प्लानिंग और लागू करने के स्टेज पर स्थानीय विधायकों और स्टेकहोल्डर्स को शामिल किया जाए ताकि काम आसानी से हो सके।

उन्होंने निर्देश दिया कि समय-समय पर प्रोग्रेस रिपोर्ट उनके ऑफिस में जमा की जाए और किसी भी रुकावट को मार्क किया जाए और समय पर हल किया जाए।

अब्दुल्ला ने हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के उन प्रोजेक्ट्स का रिव्यू किया जो स्पेशल असिस्टेंस टू स्टेट्स फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट (ﬕस्ष्ढ्ढ) स्कीम के तहत लागू किए जा रहे हैं। प्रपोज़ल्स का असेसमेंट करते हुए, उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि सभी काम लोगों पर केंद्रित, पर्यावरण के हिसाब से सस्टेनेबल और लंबे समय के शहरी प्लानिंग लक्ष्यों के साथ जुड़े होने चाहिए। इससे पहले, जम्मू स्मार्ट सिटी लिमिटेड और श्रीनगर स्मार्ट सिटी लिमिटेड के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स ने केंद्र सरकार द्वारा फंडेड स्कीम के तहत शुरू किए जा रहे प्रोजेक्ट्स पर अपडेट पेश किए।

कठुआ में आपराधिक, असामाजिक गतिविधियों के आरोपी व्यक्ति को पीएसए के तहत हिरासत में लिया गया

जम्मू, 9 दिसंबर। विभिन्न आपराधिक और असामाजिक गतिविधियों में कथित संलिप्तता के लिए वांछित एक व्यक्ति को मंगलवार को जम्मू-कश्मीर के कठुआ जिले में कड़े सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम (पीएसए) के तहत हिरासत में लिया गया। पुलिस ने यह जानकारी दी। एक पुलिस प्रवक्ता ने कहा कि प्रदीप अंबेडकरिया, जिनका नाम पिछले दो वर्षों में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज चार एफआईआर में दर्ज किया गया । पुलिस की एक टीम ने भड़काऊ भाषण देकर और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाकर कानून-व्यवस्था को बिगाड़ने के प्रयासों सहित विभिन्न अवैध गतिविधियों में शामिल आदतन अपराधी को हिरासत में लिया। चार एफआईआर में आरोपी पर धारा 299 (जानबूझकर किसी भी वर्ग की धार्मिक भावनाओं को उनके धर्म या विश्वास का अपमान करके अपमानित करना) धारा 126 (2) (गलत तरीके से रोकना) और धारा 191 (2) (दंगा), धारा 270 (सार्वजनिक उपद्रव), धारा 351 (2) (धमकी देना), और धारा 352 (शांति भंग करने के लिए जानबूझकर अपमान करना) सहित विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। प्रवक्ता ने कहा कि चार मामलों के अलावा उनके खिलाफ पुलिस स्टेशन कठुआ में कुछ प्रतिकूल रिपोर्ट भी दर्ज हैं। प्रवक्ता ने कहा कि उसकी अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए एक डोजियर तैयार किया गया और जिला मजिस्ट्रेट कठुआ को भेजा गया जिन्होंने बाद में पीएसए के तहत उसके खिलाफ हिरासत वारंट जारी किया।

डोडा में मदरसा शिक्षक नाबालिग से दुष्कर्म के आरोप में गिरफ्तार

जम्मू,, 9 दिसंबर । जम्मू-कश्मीर के डोडा जिले में एक मदरसे के शिक्षक को नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के अनुसार आरोपी की पहचान नासिर मजीद निवासी चल्लेर के रूप में हुई है।

मदरसा दार-उल-कुरान, गंदोह में हुई घटना की शिकायत मिलते ही पुलिस ने तीन घंटे के भीतर आरोपी को पकड़ने के लिए विशेष टीम गठित की और तकनीकी सुरागों के आधार पर उसकी तलाशी शुरू की। अपराध के बाद आरोपी फरार हो गया था लेकिन टीम वर्क और सतर्कता के चलते उसे जल्द ही गिरफ्तार कर लिया गया। पीड़िता का मेडिकल परीक्षण जीएमसी डोडा में कराया गया है और कानूनी कार्रवाई जारी है। पुलिस ने बताया कि मामला बीएनएस और पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज किया गया है और आगे की जांच प्रक्रिया जारी है।

जम्मू क्षेत्र में भारत-पाकिस्तान सीमा पर सुरक्षाबलों ने चलाया संयुक्त तलाशी अभियान

जम्मू, 09 दिसंबर । स्निफर डॉग यूनिट्स के साथ जम्मू-कश्मीर पुलिस, सेना और सीआरपीएफ की टीमों ने कठुआ, सांबा और जम्मू जिलों में अंतरराष्ट्रीय सीमा (आईबी) के पास आगे के इलाकों में संयुक्त तलाशी अभियान चलाया है।

अभियान से जुड़े अधिकारियों ने बताया कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स (बीएसएफ) के जवानों ने स्निफर डॉग्स और पुलिस स्पेशल ऑपरेशन्स ग्रुप (एसओजी) के साथ मिलकर आईबी के पास के इलाकों में तलाशी अभियान चलाया है, जिसमें जम्मू में गंजनसू, मढ़ और दोमाना, सांबा में नडाला, रीगल, पंगदौर और गलार और कठुआ जिले में खानपुर और पंसार शामिल हैं।

सुरक्षाबलों ने सीमा के पास अलग-अलग माइग्रेंट बस्तियों में तलाशी ली। उन्होंने बताया कि कुछ इलाकों में बम निरोधक दस्ता भी संयुक्त टीमों का हिस्सा था। इसके अलावा डायरेक्टर जनरल ऑफ़ पुलिस नलिन प्रभात और पुलिस, सेना और बीएसएफ के सीनियर अधिकारियों समेत वरिष्ठ अधिकारियों ने सिक्योरिटी सेटअप और ऑपरेशनल तैयारियों की समीक्षा करने के लिए भारत-पाकिस्तान बॉर्डर पर आगे के इलाकों का दौरा किया है।

आने वाले महीनों में कोहरे का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे पाकिस्तान के आतंकवादियों की घुसपैठ की कोशिशों का मुकाबला करने के लिए सुरक्षाबलों ने पूरे आईबी सेक्टर के लिए सर्दियों की रणनीति बनाई है

सबको साथ लेकर चलने वाले विकास का एक नया अध्याय लिखा गया : एलजी सिन्हा

जम्मू तवी, 9 दिसंबर। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने मंगलवार को कहा कि बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, समान अवसर और सामाजिक न्याय हमेशा से सरकार की प्राथमिकताएं रही हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में हर तरह के और सबको साथ लेकर चलने वाले विकास का एक नया अध्याय लिखा गया है।

सांबा में हाल ही में आई अचानक आई बाढ़ में क्षतिग्रस्त हुए 105 घरों की आधारशिला रखने के बाद रिपोर्टरों से बात करते हुए स्न्न सिन्हा ने कहा, ॉक्रूमोदी के मार्गदर्शन में, हमने हर तरह के और सबको साथ लेकर चलने वाले विकास के साथ एक नया इतिहास लिखा है ।ॉ

लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कठुआ का भी दौरा किया और 344 घरों की आधारशिला रखी जो पूरी तरह से तबाह हो गए थे। इन घरों को 34 करोड़ रुपये की लागत से बनाया जाएगा। सांबा में, हाल ही में आई अचानक आई बाढ़ में क्षतिग्रस्त हुए 105 घरों को 10.50 करोड़ रुपये की लागत से फिर से बनाया जाएगा। इन 3-बेडरूम वाले घरों को बनाने का खर्च एक NGO, हाई-रेंज रूरल डेवलपमेंट सोसाइटी (HRDS इंडिया) उठाएगी, जो घर के मालिकों के लिए मॉडर्न सुविधाएँ और सुविधाएँ भी पक्का करेगी। वहाँ मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए, लेफ्टिनेंट गवर्नर ने HRDS इंडिया की इस नेक कोशिश और जम्मू-कश्मीर में प्रभावित परिवारों के लिए सम्मानजनक और सुरक्षित घर पक्का करने में UT एडमिनिस्ट्रेशन को दिए गए सपोर्ट की तारीफ़ की।

कहा कि मिलकर काम करने से चुनौतियों का सामना किया जा सकता है

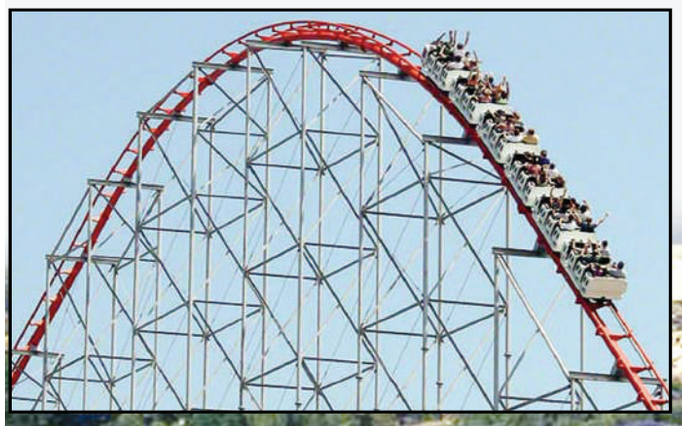

दुनिया के सबसे रोमांचक एडवेंचर
सीडार प्वाइंट

अमेरिका में ओहियो राज्य के सेंडस्की स्थित लेक ऐली प्रायद्वीप में सीडार प्वॉइंट 364 एकड़ में बना विशाल अम्यू जमेंट पार्क है। तरह-तरह की मनोरंजक विशेषताएं लिए यह पार्क वर्ष 1870 में खुला था। यह दुनिया का दूसरा सबसे पुराना अम्यूजमेंट पार्क है। इससे पहला पार्क लेक कंपाउंस है। इसका निर्माण सीडार फेयर इंटरटेनमेंट कंपनी द्वारा किया गया जो इसका संचालन करती है। यही कंपनी इसकी मालिक भी है।

सीडार प्वाइंट को अमेरिका का रोलर कोस्ट भी कहा जाता है क्योंकि यहीं दुनिया के सबसे ज्यादा रोलर कोस्टर और झूले (राइड्स) हैं। इनकी संख्या 72 है जो कि एक विश्व कीर्तिमान है। इसमें 17 रोलर कोस्टर्स भी शामिल हैं जो इसे दुनिया का सबसे ज्यादा रोलर कोस्टर्स वाला तीसरा पार्क बनाता है। चार रोलर कोस्टर्स की ऊंचाई 200 फुट से भी ज्यादा है।

मुख्य सीडार प्वाइंट को देखने के लिए एक पूरा दिन चाहिए। यदि यहां मौजूद सभी आकर्षणों को देखना हो तो कम से कम दो दिन जरूरी हैं। हर साल सीडार पहुंचने वाले पर्यटकों की संख्या करोड़ से भी ऊपर है।

सीडार प्वाइंट में दुनिया के कई सबसे ऊंचे और तेज झूले भी हैं जैसे कि टॉप थ्रिल ड्रैगस्टर और मिलेनियम फोर्स। इनके बारे में कहा जाता है कि इनसे मिलने वाला अनुभव और कहीं नहीं मिलता। जो लोग रोमांच और एडवेंचर की तलाश में रहते हैं, उनके लिए सीडार प्वाइंट से बेहतर जगह और कोई नहीं।

सीडार प्वाइंट को अकसर दुनिया का सबसे बड़ा अम्यूजमेंट पार्क भी कहा जाता है। वर्ष 2008 में इसे लगातार 11वें वर्ष भी दुनिया का सर्वश्रेष्ठ अम्यूजमेंट पार्क का खिताब दिया गया। हालांकि सीडार प्वाइंट का मुख्य आकर्षण यहां मौजूद रोलर कोस्टर्स का विशाल संकलन है। बावजूद इसके, यहां झूले और अन्य आकर्षण भी कम नहीं है जैसे कि किड्डी राइड्स, वाटर राइड, म्यूजिकल शोज, आइस स्केटिंग शो आदि। इस पार्क का एक विशेष आकर्षण ऐरी झील का 1.6 किलोमीटर लंबा शानदार तट है जो यहां शुरू से ही पर्यटकों को आकर्षित करता रहा है।

पी-50 खिलौने जैसी कार

पील पी50, पुराने जमाने के डिजाइन वाली कार है। इसमें छोटे-छोटे पहिए हैं, एक हेडलाइट, एक दरवाजा और यहां तक कि इसमें खिड़की के शीशे को साफ करने वाला एक वाइपर भी है। यह महज 54 इंच लंबी है। यह पहली सबसे छोटी कार है, जो सड़कों पर दौड़ी। पी50 कार इतनी छोटी है कि अगर इसे पीछे ले जाना हो तो दरवाजा खोलकर बाहर आना पड़ता है और इसे हाथ से खींचकर पीछे कर सकते हैं। इसे कोवेंट्री यूनिवर्सिटी के छात्रों ने मिलकर बनाया। पील पी50 कार और पील ट्राइडेंट कार, बिल्कुल बच्चों के खिलौने की तरह दिखती है। यह भरोसा करना मुश्किल होता है कि यह सडम्क पर भी चलती है। ब्रिटेन और अमेरिका में इसे सड़क पर देखा जा सकता है। जब पी50 को पहली बार 1960 के दशक में पेश किया गया था तो तब किसी ने यह नही सोचा था कि कभी यह लोगों के आकर्षण का केंद्र होगी। पी50 कार को दुनिया की कुछ अनोखी कारों में शामिल किया गया है। इसे बनाने वाली पील इंजीनियरिंग लिमिटेड नामक कंपनी ने फाइबर ग्लास की नाव (बोट) और मोटरसाइकिल भी बनाई हैं। कंपनी ने वर्ष 1962 में पहली पील पी50 कार पेश की थी। इसे इसलिए बनाया गया था ताकि एक आदमी खरीदारी बैग को लेकर कहीं भी आसानी से आ-जा सके।

एंटीक सोवियत वाहनों का विशाल संग्रह

जर्मनी की राजधानी बर्लिन में सोवियत दौर में बने पुराने वक्त के वाहनों का अनोखा संग्रह मौजूद है जिन्हें अब एंटीक कारों तथा अन्य प्रकार के वाहनों का दर्जा मिल चुका है। वहां ब्रनर परिवार के पास ऐसे वाहनों का सबसे बड़ा संग्रह है जो चाहता है कि उनके संग्रह को किसी विशिष्ट संग्रहालय में स्थान मिले। उनके संग्रह में छोटी कारों से लेकर सोवियत सेना द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले बड़े ट्रक भी शामिल हैं। इसमें 75 कारें तथा 90 मोटरसाइकिल भी शामिल हैं। खास बात है कि उनके पास मौजूद सभी एंटीक वाहन चालू हालत में हैं। फिलहाल इन्हें एक पूर्व सोवियत बंकर के प्रांगण में रखा गया है। इस संग्रह की शुरूआत लोथर ब्रनर ने की थी। 1990 में पश्चिम तथा पूर्व जर्मनी के एकीकरण तथा सोवियत संघ के खात्मे के बाद वह इन्हें खरीदने लगे। उनकी मौत के बाद अब उनका परिवार उनके संग्रह की देखभाल कर रहा है। वे चाहते हैं कि इन वाहनों के लिए एक खास संग्रहालय तैयार करवाया जाए जहां लोग इन्हें देख सकें तथा इनका संरक्षण भी सम्भव हो सके।

खून का प्यासा पिस्सू

पिस्सू बिना पंखवाले छोटे कीट हैं जिनकी औसत लंबाई 2 मिलीमीटर होती है। पिस्सू गरम खूनवाले जीवों में परजीवी के रूप में रहकर उनका खून चूसते हैं। मनुष्यों के अलावा वे चूहों, पक्षियों, सूअरों, कुत्तों तथा अन्य जानवरों पर अपनी कृपा दृष्टि बरसाते हैं। उनके शरीर की रचना इस भूमिका के लिए खास उपयुक्त होती है। मेजबान जीव की खाल अथवा परों के बीच से आने-जाने में सहूलियत के लिए उनका शरीर दोनों बग़लों से चपटा होता है, यानी लंबाई और ऊंचाई की तुलना में उनकी चौड़ाई बहुत ही कम होती है। बहादुर से बहादुर आदमी भी मामूली-सा पिस्सू देखकर पसीना-पसीना हो जाएगा क्योंकि प्लेग महामारी इसी तुच्छ कीट की सवारी पर चढ़कर मनुष्यों में तांडव मचाती है। पिस्सू की सैंकड़ों जातियां ज्ञात हैं। ये बिना पंखवाले छोटे कीट हैं जिनकी औसत लंबाई 2 मिलीमीटर होती है। पिस्सू गरम खूनवाले जीवों में परजीवी के रूप में रहकर उनका खून चूसते हैं। मनुष्यों के अलावा वे चूहों, पक्षियों, सूअरों, कुत्तों तथा अन्य जानवरों पर अपनी कृपा दृष्टि बरसाते हैं। उनके शरीर की रचना इस भूमिका के लिए खास उपयुक्त होती है। मेजबान जीव की खाल अथवा परों के बीच से आने-जाने में सहूलियत के लिए उनका शरीर दोनों बग़लों से चपटा होता है, यानी लंबाई और ऊंचाई की तुलना में उनकी चौड़ाई बहुत ही कम होती है। इस कारण वे दो बालों के बीच के कम फासले में से भी आसानी से गुजर सकते हैं। उनके शरीर पर बहुत से कांटे होते हैं जो बालों अथवा परों में उलझकर पिस्सू को मेजबान जीव के शरीर से गिरने नहीं देते। उनका चपटा शरीर अत्यंत कठोर होता है जो उन्हें मेजबान जीव द्वारा काटे या खुजलाए जाने से बचाता है। उनका मुंह त्वचा को भेदने और खून चूसने के लिए बना होता है। पिस्सुओं का जीवन-चक्र काफी रोचक होता है। मादा पिस्सू मेजबान जीव के मल-मूत्र या उसकी मांद में इकट्ठी गंदगी में अंडे देती है। ये अंडे दो-चार दिनों में फूट जाते हैं। उनसे निकले डिंभक अंधे होते हैं। वे मल-मूत्र और गंदगी खाकर बढ़ते हैं। मौका मिलने पर अन्य छोटे कीटों का भी वे शिकार कर लेते हैं। समय आने पर ये डिंभक रेशम जैसे धागे से एक कोष बुनकर उसमें प्रविष्ट हो जाते हैं। इस निष्क्रिय अवस्था में उनका आगे का विकास होता है। वयस्क कीट कोष से बाहर तभी निकलते हैं जब उन्हें कोई जीवित प्राणी का संकेत मिले। यह संकेत है उस प्राणी के चलने-फिरने से होनेवाले कंपन। इसे सुनते ही पिस्सू झट से कोष से निकल आते हैं और उस अभागे प्राणी का खून चूसने लगते हैं। इसी कारण से बहुत दिनों से खाली पड़े मकान में घुसने पर एकाएक पिस्सू निकल आते हैं। आप सोचते होंगे कि खाली मकान में पिस्सू कहां से आए। वास्तव में पिस्सू अपने कोषों में आपके ही इंतजार में बैठे थे!

पिस्सुओं की सबसे अधिक वीभत्स पहलू प्लेग जैसी भयंकर महामारियां फैलाने में उनकी भूमिका है। प्लेग महामारी से मनुष्य बड़ी तादाद में मरे हैं। चौदहवीं सदी में यूरोप में प्लेग ने ढाई करोड़ लोगों की जान ली थी। परंतु प्लेग मनुष्य पर आश्रित पिस्सुओं के कारण नहीं फैलता। प्लेग के लिए जिम्मेदार हैं चूहों के पिस्सू। प्लेग बीमारी सबसे पहले चूहों में फैलती है। इस बीमारी से जब चूहे बड़ी संख्या में मर जाते हैं, तब उनके पिस्सुओं को मजबूरन अन्य प्राणियों का खून चूसना पड़ता है। इन अन्य प्राणियों में मनुष्य भी होता है, क्योंकि मनुष्यों के मकानों में चूहे अनिवार्यत: पाए जाते हैं। पिस्सुओं की एक खासियत है कूदने की उनकी अद्भुत क्षमता। दो मिलीमीटर लंबा पिस्सू 35 सेंटीमीटर लंबी और 20 सेंटीमीटर ऊंची कूद लगा सकता है, यानी अपनी लंबाई से 125 गुना दूर अथवा 100 गुना ऊंचा कूद सकता है। इसीलिए प्लेग के समय लोगों को दो फुट ऊंचे पलंग पर सोने की सलाह दी जाती है, ताकि पिस्सू उन तक न पहुंच पाएं। अपनी लंबी-लंबी टांगों और नदारद पंखों की मांसपेशियों की सहायता से पिस्सू यह आश्चर्यजनक कलाबाजी करता है। अधिकांश विकसित देशों में पिस्सुओं का सफाया कम-से-कम घरों में से लगभग पूर्णत: हो गया है।

बर्फ में बर्फ-सा खरगोश

बच्चों, जब हम आर्कटिक की बात करते हैं तो हमारे के जेहन में दूर-दूर तक फैला बर्फ और पेंगुइन, ध्रुवीय भालू और डॉलफिन जैसे पानी और समतल दोनों पर रहनेवाले जीवों के नाम याद आते हैं, पर क्या आपने कभी सोचा है कि माइनस 40 डिग्री की ठंड में कोई प्यारा-सा, छोटा खरगोश भी रह सकता है। चौंक गये न कि बर्फ में खरगोश! आओ, हम तुम्हें बताते हैं खरगोश की ऐसी ही प्रजाति के बारे में, जो आर्कटिक के ध्रुवीय प्रदेश में रहता है। यह ध्रुवीय खरगोश देखने में तो अन्य खरगोशों की तरह ही दिखता है, पर शरीर की बनावट और इसका रहन-सहन इसे विपरीत परिस्थितियों में भी आसानी से जीवित रखता है। ध्रुवीय खरगोश के बाल काफी मोटे और घने होते हैं, जो इसके लिए कंबल का काम करते हैं।

साथ रहने की कला

ध्रुवीय खरगोश बर्फ के अंदर गड्ढा खोद कर रहते हैं। सर्दी से बचने के लिए, ये एक-दूसरे से सटकर रहते हैं, जिससे इनका शरीर एक दूसरे को ताप दे सके। इनके कान अन्य खरगोशों की अपेक्षा छोटे होने के कारण बर्फीली हवाओं से ये बच जाते हैं। ऐसे तो ये आपको अकेले मिल जाएंगे, पर आप इन्हें दर्जन या सैकड़ों के झुंड में देख सकते हैं। इनका झुंड कुछ आपके स्कूल की सुबह के प्रार्थना के जैसा ही होता है। एक नर खरगोश एक से अधिक मादाओं के साथ रहता है। मादा खरगोश साल में एक बार लगभग 6-8 बच्चों को जन्म देती है। वसंत ऋतु या गर्मी के शुरुआती दिनों में ये बच्चे देती हैं। सितंबर के महीने तक 2-8 बच्चे बड़े होकर फिर से अगले नस्ल को तैयार करने लायक हो जाते हैं।

क्या खाते हैं ध्रुवीय खरगोश

ध्रुवीय खरगोश ज्यादातर कोंपल, पेड़ों के पत्ते, काई और बेर खाते हैं। सर्दियों में जब खाने की कमी होती है, तो ये समुद्री शैवाल, पेड़ की मुलायम छाल और जड़ भी खा जाते हैं। बच्चों यह बड़े अफसोस की बात है कि बहुत ही कम संख्या में पाए जाने वाले इस प्यारे से जीव का शिकार इंसान इसके गोश्त के लिए करते हैं। अगर इनका शिकार इसी तरह जारी रहा, तो वह दिन दूर नहीं जब यह प्यारा जीव विलुप्त हो जाएगा।

स्वामी, प्रकाशक एवं मुद्रक - नीलम सिंह गिल द्वारा देहात संदेश, गुरूद्वारा सुंदर सिंह रोड, जम्मू से प्रकाशित एवं नार्थलाईनस पबलिशर्स, 18-B, Phase- II, Industrial Estate, Gangyal, Jammu से मुद्रित। संपादक- नीलम सिंह गिल। फोन नंबर:- (95)191- 2574109 2548103 RNI Regd. No.: JKBIL/2004/13144 *Email: dehatsandesh@gmail.com, dehatsandesh@yahoo.com, dehatsandesh@rediffmail.com*

औकिब नबी आईपीएल 2026 नीलामी के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए 8 जेके क्रिकेटरों में शामिल

श्रीनगर, 09 दिसंबर हि.स.। जम्मू और कश्मीर क्रिकेट के लिए एक बड़ी खबर है शानदार तेज गेंदबाज औकिब नबी जम्मू और कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन (जेकेसीए) के आठ खिलाड़ियों के ग्रुप में शामिल हैं जिन्हें आईपीएल 2026 प्लेयर नीलामी के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है जो 16 दिसंबर को अबू धाबी में होने वाली है।भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) द्वारा जारी अंतिम सूची के अनुसार, जेके के जिन खिलाड़ियों को चुना गया है उनमें औकिब नबी, नासिर मुजफ्फर, आतिफ मुश्ताक, वसीम खांडे, विवरांत शर्मा, आबिद मुश्ताक, कमरन इकबाल और अश्विन मुरुगन शामिल हैं।

बारामूला के 28 वर्षीय स्विंग गेंदबाज औकिब नबी, खासकर सबसे होनहार घरेलू प्रतिभाओं में से एक के रूप में उभरे हैं।

दोनों तरफ गेंद को स्विंग कराने की अपनी क्षमता के लिए जाने जाने वाले वह जेके के सबसे लगातार प्रदर्शन करने वालों में से एक रहे हैं। उनके शानदार 44 विकेट के रणजी ट्रॉफी अभियान ने उन्हें देश के सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजों में से एक के रूप में स्थापित किया। उन्होंने दिलीप ट्रॉफी के इतिहास में चार गेंदों में चार विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बनकर इतिहास भी रचा।

नीलामी से पहले नबी के मुंबई इंडियंस के साथ हालिया ट्रायल ने उम्मीदों को और बढ़ा दिया है।

बीसीसीआइ की अंतिम नीलामी सूची में 350 खिलाड़ी शामिल हैं जिन्हें फ्रेंचाइजी मूल्यांकन और प्रदर्शन-आधारित फिल्टरिंग के बाद लगभग 1,390 पंजीकरणों में से छांटा गया है।

लद्दाख में स्वदेशी,स्वावलंबन और संस्कृति का तीन दिवसीय उत्सव

जम्मू,9 दिसंबर (हि.स.)। लद्दाख में स्वदेशी, स्वावलंबन और संस्कृति का तीन दिवसीय उत्सव होगा।लद्दाख जम्मू कश्मीर इकोनॉदिक ग्रोथ एंड डेवलपिंट डायलॉग ने आज घोषणा की। यह वार्षिक उत्सव 19 से 21 दिसंबर 2025 तक जीजीएम साइंस कॉलेज ग्राउंड, जम्मू में आयोजित किया जाएगा।

हर वर्ष बढ़ती भागीदारी और लोगों की रुचि को देखते हुए, इस बार महोत्सव तीन दिनों का होगा। लद्दाख जम्मू और कश्मीर की संस्कृति और उद्यमशीलता की झलक दिलेगी।

प्रेस वार्ता के दोहरन हरिंद्र गुप्ता, संयोजक लीड ने बताया दक होत्सव 120 से अदिक स्टॉल लगाए जाएंगे जिनमें स्थानीय हस्तशिल्प पारंपररक व्यंजन और नई स्टाटिअप पहलों को प्रदर्शित किया जाएगा।

जम्मू-कश्मीर खेल परिषद ने चार अधिकारियों की नियुक्ति, समायोजन का आदेश दिया

जम्मू, 9 दिसंबर(हि.स.)। जम्मू एवं कश्मीर खेल परिषद ने प्रशासन के हित में चार अधिकारियों की तत्काल नियुक्ति और समायोजन की घोषणा की है। आदेश के अनुसार, सीनियर बॉक्सिंग कोच अनिल कुमार वाधेरे को ओल्ड इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, जम्मू से एम.ए. स्टेडियम जम्मू में स्थानांतरित कर दिया गया है जहां वह नियमित कोचिंग कक्षाएं भी संचालित करेंगे।

स्पोर्ट्स स्टेडियम कठुआ के हेड असिस्टेंट जोगिंदर कुमार को डिवीजनल स्पोर्ट्स ऑफिस, जम्मू में स्थानांतरित किया गया है।

सकीना इटू ने श्रीनगर सचिवालय में पब्लिक आउटरीच सेशन किया आयोजित

श्रीनगर, 9 दिसंबर (हि.स.)। स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा, समाज कल्याण और शिक्षा मंत्री सकीना इटू ने आज श्रीनगर के सचिवालय में एक बड़ा पब्लिक आउटरीच सेशन किया जिसमें अलग-अलग विधायक, जन प्रतिनिधि मंडल, कर्मचारी संघ और व्यक्तिगत लोगों ने मंत्री के सामने कई मुद्दे उठाए। सेशन के दौरान जम्मू कश्मीर टीचर्स जॉइंट एक्शन कमेटी के एक डेलीगेशन ने मंत्री से मुलाकात की और टीचिंग कम्युनिटी के कई मुद्दे उठाए। डेलीगेशन ने आरईटी लिए ट्रांसफर पॉलिसी बनाने के लिए कमेटी बनाने के लिए मंत्री का शुक्रिया अदा किया। इसी तरह रहबर-ए-खेल टीचर्स के एक डेलीगेशन ने मंत्री से मुलाकात की और उन रहबर-ए-खेल टीचर्स को रेगुलर करने की मांग की जिन्होंने सात साल

की अच्छी सर्विस पूरी कर ली है। इसी तरह जम्मू और कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के अधिकारियों के एक डेलीगेशन ने मंत्री से मुलाकात की और उनके के सामने करियर प्रोग्रेस से जुड़े कई मुद्दे उठाए। आउटरीच सेशन के दौरान बारामूला, कुपवाड़ा, अनंतनाग, गांदरबल, बांदीपोरा, कुलगाम और दूसरे ज़िलों के अलग-अलग इलाकों से कई पब्लिक डेलीगेशन ने भी मिनिस्टर से मुलाकात की और हेल्थ सेक्टर, एजुकेशन, पीने के पानी की अवेलेबिलिटी, बिजली और सर्दियों के महीनों को देखते हुए राशन की अवेलेबिलिटी जैसी ज़रूरी सप्लाई से जुड़े कई मुद्दे उठाए।

कश्मीर की हस्तशिल्प विरासत को पहचान मिली, भारत सरकार ने चार कारीगरों को सम्मानित किया

श्रीनगर, 09 दिसंबर हि.स.। कश्मीर की प्रसिद्ध हस्तशिल्प परंपरा को एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय बढ़ावा मिला क्योंकि घाटी के चार मास्टर कारीगरों को भारत सरकार द्वारा प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित किया गया जो पारंपरिक कला रूपों में उनके असाधारण योगदान को मान्यता देता है। ये सम्मान 9 दिसंबर 2025 को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में भारत के राष्ट्रपति की अध्यक्षता में आयोजित एक समारोह में प्रदान किए गए। ख्वाजा नज़ीर अली और मंज़ूर अहमद खान को क्रमश सोज़नी शॉल बुनाई और हस्तनिर्मित कालीनों में राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए गए जबकि मश्कूरा हमीद और मीर अरशद को क्रमशः सोज़नी शॉल और पेपर मैशे में उत्कृष्टता प्रमाण पत्र मिला। ये सम्मान वार्षिक शिल्प गुरु पुरस्कार और राष्ट्रीय पुरस्कारों का हिस्सा हैं। वस्त्र मंत्रालय के विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) की एक प्रतिष्ठित पहल जिसका उद्देश्य उत्कृष्ट शिल्प कौशल का जश्न मनाना और भारत की कालातीत कारीगरी विरासत को संरक्षित करना है।

हस्तशिल्प सेवा केंद्र एचएससी श्रीनगर के सहायक निदेशक राजा राहिल राशिद ने कहा कि इस साल श्रीनगर बडगाम और गांदरबल के 49 कारीगरों ने प्रविष्टियां भेजी थीं। उन्होंने कहा कि उनमें से कश्मीर के चार कारीगरों को राष्ट्रीय मान्यता के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया जो सोज़नी कढ़ाई, कालीन बुनाई और पेपर-मैशे में घाटी की स्थायी महारत को उजागर करता है। उन्होंने कहा कि ये अवॉर्ड कश्मीरी कारीगरों के असाधारण कौशल, लगन और कलात्मक विरासत की पुष्टि करते हैं जिनके हाथ से बने कामों की तारीफ़ देश और दुनिया भर में होती रहती है।

विधायक ने दो दिवसीय जिला किसान मेला कार्यशाला का उद्घाटन किया

रामगढ़,9 दिसंबर (हि.स.)। रामगढ़ विधायक और जम्मू-कश्मीर के पूर्व स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री डॉ. देविंदर कुमार मन्याल ने आज मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित होकर केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर के कृषि उत्पादन एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा आयोजित दो दिवसीय जिला किसान मेला कार्यशाला का उद्घाटन किया।

यह कार्यक्रम वित्त वर्ष 2025-26 के लिए एकीकृत बागवानी विकास मिशन के तहत आयोजित किया जा रहा है और एसडीएओ सांबा द्वारा आयोजित किया जा रहा है। मुख्य अतिथि का स्वागत करते हुए सांबा के मुख्य कृषि अधिकारी राकेश खजूरिया ने क्षेत्र में कृषि क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए डॉ. मन्याल के निरंतर सहयोग की सराहना की। उन्होंने आधुनिक बागवानी तकनीकों को बढ़ावा देने और किसान-केंद्रित योजनाओं के बारे में जागरूकता पैदा करने में किसान मेले के महत्व पर प्रकाश डाला। उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए, डॉ. देविंदर कुमार मन्याल ने कहा कि सरकार प्रौद्योगिकी नवाचार और विभागीय पहलों तक समय पर पहुँच के माध्यम से किसानों को सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने ऐसे ज्ञान-आधारित कार्यक्रम आयोजित करने के लिए कृषि विभाग के प्रयासों की सराहना की।

जो किसानों को वैज्ञानिक पद्धतियाँ अपनाने और अपनी आय क्षमता बढ़ाने में मदद करते हैं। कार्यक्रम के दौरान कृषि और बागवानी विभागों के विशेषज्ञों ने किसानों के साथ बातचीत की और तकनीकी प्रदर्शन किए।

भारत-पाक अंतरराष्ट्रीय सीमा से सटे आर.एस. पुरा सेक्टर से गुबारा बरामद

आर.एस. पुरा, 9 दिसंबर (हि.स.)। भारत-पाक अंतरराष्ट्रीय सीमा से सटे आर.एस. पुरा सेक्टर के गांव कोटली मीरदियां में मंगलवार को खेतों से एक संदिग्ध पाकिस्तानी गुब्बारा बरामद होने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। जानकारी के अनुसार किसान जगतार सिंह के खेतों में स्थानीय लोगों की नजर एक बड़े गुब्बारे पर पड़ी, जिसके बाद तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस पोस्ट बासपुर की टीम मौके पर पहुंची और सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करते हुए गुब्बारे को कब्जे में लेकर सील कर दिया। पुलिस ने आसपास के पूरे क्षेत्र की तलाशी भी ली ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कहीं कोई अन्य संदिग्ध सामान मौजूद न हो पुलिस अधिकारियों ने बताया कि शुरुआती जांच में यह आशंका जताई जा रही है कि गुब्बारा सीमा पार से उड़कर भारतीय क्षेत्र में आ गया है। गुब्बारे पर कुछ लिखावट और निशान भी पाए गए हैं जिनकी जांच सुरक्षा एजेंसियां विशेषज्ञों की मदद से करेंगी। इधर ग्रामीणों ने ऐसे मामलों को गंभीर बताते हुए सुरक्षा एजेंसियों से इलाके में सतर्कता बढ़ाने की मांग की है

महिला मोर्चा ने रेहाड़ी गर्ल्स स्कूल में आत्मनिर्भर भारत अभियान का नेतृत्व किया

जम्मू, 9 दिसंबर (हि.स.)। भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा जम्मू और कश्मीर ने रेहारी गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल में आत्मनिर्भर भारत पर एक विशेष जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसके बाद देशभक्ति से ओतप्रोत स्वदेशीसंकल्प शपथ ली गई। यह कार्यक्रम भाजपा महिला मोर्चा जम्मू-कश्मीर की अध्यक्ष एडवोकेट नेहा महाजन के नेतृत्व में आयोजित किया गया, जिन्होंने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। इस पहल का उद्देश्य युवा लड़कियों को आत्मनिर्भरता अपनाने स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने और राष्ट्र निर्माण में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए सशक्त बनाना था। छात्राओं को संबोधित करते हुए, एडवोकेट नेहा महाजन ने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व पर प्रकाश डाला और आत्मनिर्भर भारत के मिशन को आगे बढ़ाने में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित किया।

भद्रवाह में व्यापार मंडल-नगर पालिका समिति की बैठक, स्थानीय रोजगार व बाजार व्यवस्था पर जोर

अमीर इक़बाल ख़ान

भद्रवाह, 9 दिसंबर। भद्रवाह व्यापार मंडल की ओर से मंगलवार को आयोजित संवाद बैठक में स्थानीय व्यापारियों ने नगर के नागरिक व व्यापारिक मुद्दों को प्रमुखता से उठाया। बैठक में भद्रवाह नगर पालिका समिति (बीएमसी) का प्रतिनिधित्व कार्यकारी अधिकारी ने किया। बैठक की अध्यक्षता व्यापार मंडल के अध्यक्ष नसीर महबूब ने की।बैठक में उपाध्यक्ष ऋषि कोटवाल, संरक्षक सुरेश गुप्ता, सचिव जीवत कोटवाल सहित मिंटू मुगल, मनोज कोटवाल, मुश्ताक चुन्ना सहित कई व्यापारी उपस्थित रहे। विचार-विमर्श के दौरान व्यापारियों ने वेंडिंग अनुमति जारी करते समय स्थानीय बेरोजगार युवाओं को प्राथमिकता देने तथा स्वरोजगार को बढ़ावा देने की मांग उठाई।व्यापार मंडल के सदस्यों ने प्रमुख बाजार क्षेत्रों और व्यावसायिक केंद्रों में गैर-स्थानीय विक्रेताओं को अनुमति न देने की अपील की। हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया कि बाहर से आने वाले पर्यटकों व आगंतुकों का भद्रवाह में सदैव स्वागत है। सदस्यों ने सुझाव दिया कि न्यू बस स्टैंड कोटली के समीप एक निश्चित क्षेत्र गैर-स्थानीय विक्रेताओं के लिए चिन्हित किया जाए, ताकि बाजार व्यवस्था सुव्यवस्थित बनी रहे।

आर्मी पब्लिक स्कूल सुंजवां ने वार्षिकोत्सव मनाया

जम्मू, 9 दिसंबर (हि.स.)। आर्मी पब्लिक स्कूल सुंजवां ने अपना वार्षिकोत्सव साथ मिलकर बड़े उत्साह के साथ मनाया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य स्कूल की सभी उपलब्धियों के प्रति छात्रों शिक्षकों और गौरवान्वित अभिभावकों के प्रयासों उत्साह और ईमानदारी को मान्यता देना और उनका सम्मान करना था। समारोह की शुरुआत एक मधुर संगीतमय प्रस्तुति से हुई। जिसने शाम को एक जीवंत और मनमोहक माहौल प्रदान किया। आर्मी पब्लिक स्कूल सुंजवां की प्रधानाचार्या ने वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें शैक्षणिक उपलब्धियों बुनियादी ढाँचे की प्रगति और पूरे वर्ष स्कूल द्वारा की गई प्रमुख पहलों पर प्रकाश डाला गया। विभिन्न कक्षाओं के छात्रों ने नृत्य, संगीत, विषयगत प्रस्तुतियों से लेकर विकास और सीखने की यात्रा के आयु-वार चित्रण तक सुव्यवस्थित सांस्कृतिक प्रस्तुतियों की एक श्रृंखला प्रस्तुत की।

UNION TERRITORY OF Jammu & Kashmir
OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER, JAL SHAKTI DEPARTMENT
MECHANICAL DIVISION RTIC, JAMMU
Ph. 0191-2956288

EXTENSION NOTICE

Due to poor response of E-Nit 37 of 2025-26 dated 28-11-2025 for P/F of new components by way of replacement of old damaged components like bearings, carbon brushes, brush holders assemblies, terminal leads, slip rings and other works 1 No motor at TPH, Jammu is hereby extended upto 12.12.25.

NEW DATES

Bid submission end date	**12/12/2025 (03:00 PM)**
Bid submission opening date	**13/12/2025 (11:00 AM)**

No. : - MDJ/RTIC/1293-96
Dated: -08-12-2025

Sd/-
Executive Engineer
Mechanical Division
RTIC, Jammu

DIP/J-8826/25
Dtd:9-12-2025

जिला स्तरीय शतरंज चैंपियनशिप संपन्न

जम्मू, 9 दिसंबर (हि.स.)। जिला ओलंपिक एसोसिएशन बारामूला द्वारा जेएंडके स्पोर्ट्स काउंसिल के सहयोग से आयोजित जिला स्तरीय शतरंज चैंपियनशिप मंगलवार को यहां वेल्किन एजुकेशनल ट्रस्ट सोपोर में सफलतापूर्वक संपन्न हुई। इस ओपन चैंपियनशिप में जिले के विभिन्न स्कूलों और क्लबों के लड़के-लड़कियों ने उत्साहपूर्ण भागीदारी करते हुए अपनी रणनीति, कौशल और मानसिक फुर्ती का शानदार प्रदर्शन किया।

चैंपियनशिप का लक्ष्य जमीनी स्तर पर शतरंज प्रतिभाओं को निखारना तथा ऐसे खिलाड़ियों की पहचान करना था जो आगे यूटी-स्तरीय शतरंज प्रतियोगिता में जिले का प्रतिनिधित्व कर सकें। बड़ी संख्या में प्रतिभागियों की उपस्थिति ने जिले में शतरंज के बढ़ते आकर्षण और बच्चों में खेल के प्रति जागरूकता को स्पष्ट रूप से दर्शाया। समापन समारोह के मुख्य अतिथि एसआरएम वेल्किन एजुकेशनल ट्रस्ट के चेयरमैन हाजी अनायत उल्लाह हाजिनी थे, जिन्होंने विजेता और उपविजेता खिलाड़ियों को ट्रॉफी एवं मेडल प्रदान कर उनका उत्साह बढ़ाया। आयोजकों ने सभी खिलाड़ियों, अधिकारियों और मेहमानों को सहयोग के लिए धन्यवाद देते हुए कहा कि इसी तरह की सहभागिता से ही प्रतिभाओं को आगे बढ़ने का मंच मिलता है।

इस अवसर पर सोपोर क्रिकेट एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष माजिद बशीर, जेएंडके स्पोर्ट्स काउंसिल के पूर्व मुख्य खेल अधिकारी पीरजादा अब्दुल कयूम, एकेएफआई के तकनीकी अधिकारी खजीर मोहम्मद गनई, पीईटी स्मार्ट स्कूल सिस्टम के जहूर अहमद सहित कई छात्र, खेल प्रेमी और गणमान्य लोग उपस्थित रहे

केवीके कठुआ ने तिलहन प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी पर किसानों के दो ट्रेनिंग प्रोग्राम पूरे किए

कठुआ, 9 दिसंबर। कृषि विज्ञान केंद्र कठुआ ने ICAR-ATARI लुधियाना द्वारा दी गई क्लस्टर फ्रंटलाइन डेमोंस्ट्रेशन स्कीम के तहत तिलहन फसलों (रबी) में बेहतर प्रोडक्शन और मैनेजमेंट के तरीके पर दो ट्रेनिंग प्रोग्राम पूरे किए। इस प्रोग्राम का मकसद कठुआ जिले में फसल डायवर्सिफिकेशन को बढ़ावा देना और तिलहन की प्रोडक्टिविटी बढ़ाना था। यह इवेंट शेर-ए-कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ़ एग्रीकल्चरल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी ऑफ़ जम्मू के एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में, माननीय वाइस चांसलर डॉ. बी.एन. त्रिपाठी की शानदार लीडरशिप में हुआ था, और इसका कॉन्सेप्ट स्न्न्स्क्ष-जम्मू के डायरेक्टर एक्सटेंशन डॉ. अमरीश वैद के बेहतरीन गाइडेंस में तैयार किया गया था। दो दिन के ट्रेनिंग प्रोग्राम में 105 से ज़्यादा किसानों और खेती करने वाली महिलाओं ने हिस्सा लिया। KVK कठुआ के चीफ साइंटिस्ट और हेड डॉ. विशाल महाजन ने प्रोग्राम की शुरुआत की और पार्टिसिपेंट्स का स्वागत किया। उन्होंने न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी पक्का करने, इम्पोर्ट पर डिपेंडेंसी कम करने और क्रॉप रोटेशन और इंटरक्रॉपिंग के ज़रिए मिट्टी की हेल्थ को बेहतर बनाने में तिलहन फसलों की ज़रूरी भूमिका पर ज़ोर दिया। उन्होंने किसानों से साइंटिफिक प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी अपनाने और तिलहन को बढ़ावा देने के लिए सरकारी स्कीमों का इस्तेमाल करने की अपील की।

लोगों को संबोधित करते हुए, चीफ साइंटिस्ट (एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन) और नोडल ऑफिसर डॉ. बर्जेश अजरावत ने खाने के तेल के प्रोडक्शन में भारत को आत्मनिर्भर बनाने की ज़रूरत पर ज़ोर दिया, यह देखते हुए कि भारत बड़ी मात्रा में खाने के तेल इम्पोर्ट करता रहता है, जिससे देश की इकॉनमी पर दबाव पड़ता है। उन्होंने किसानों को नेशनल फ़ूड सिक्योरिटी मिशन (तिलहन) और नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल्स समेत केंद्र और राज्य सरकार की अलग-अलग स्कीमों के बारे में भी बताया।

लद्दाख के एलजी से कई प्रतिनिधिमंडल मिले

लेह, 9 दिसंबर। लद्दाख के माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर, श्री कविंदर गुप्ता ने LG सेक्रेटेरिएट में कई डेलीगेशन से मुलाकात की और महिला सशक्तिकरण, हेल्थकेयर, स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर और युवाओं के विकास से जुड़े खास लोकल मुद्दों पर चर्चा की।

लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन की वाइस प्रेसिडेंट कुंजेस डोल्मा ने लद्दाख में महिलाओं के सामने आने वाली चुनौतियों को असरदार तरीके से हल करने के लिए दूसरे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की तरह ही अ लेवल का महिला आयोग बनाने के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर से दखल देने की मांग की। नंबरदार स्कर्बुचन, श्री पलदान के नेतृत्व में एक डेलीगेशन ने भी लेफ्टिनेंट गवर्नर से मुलाकात की और इलाके की जनता की अलग-अलग मांगों को बताते हुए एक मेमोरेंडम सौंपा। खाल्टसे के एक और डेलीगेशन, जिसका नेतृत्व वेन. पद्मा थिनलेस कर रही थीं, ने लेफ्टिनेंट गवर्नर से उनके गांव में चल रहे क्रिकेट मैदान के कंस्ट्रक्शन को दूसरी जगह ले जाने पर विचार करने की रिक्वेस्ट की।लेफ्टिनेंट गवर्नर ने सभी डेलीगेशन को भरोसा दिलाया कि अ एडमिनिस्ट्रेशन उनकी चिंताओं को प्राथमिकता के साथ देखेगा और पूरे लद्दाख में सबको साथ लेकर चलने वाले और कम्युनिटी पर फोकस करने वाले डेवलपमेंट को पक्का करने के लिए ज़रूरी कदम उठाएगा।

GOVERNMENTOFJAMMU AND KASHMIR
Office of the District Development Commissioner Samba
Corrigendum to Advertisement No:06 of DECCSAMBA
Dated:28.11.2025
Join Mission YUVA-Build the Future of Entrepreneur ship inJ&K

This is to inform all prospective applicants that with reference to this office Advertisement No:06ofDECC SAMBA Dated:28-11-2025 for various Contractual posts under Mission YUVA, the online link applying for the postsis revised asbelow: https://forms.gle/xK7NN53MDn8KM9DbA

Consequently, the last date for applying for the posts is extended upto31st December,2025.Candidates who have already applied through the earlier link are informed to apply afresh through the above link.
The details of the posts advertised remains the same as below

Name of Posts	Monthly Remuneration (Rs.)
SBDU Lead (01post)	50,000
SBDU Coordinator (02posts)	35,000
SBDU Enterprise development expert (01 post)	35,000
SBDU Marketing expert (01post)	35,000
BHD Lead (03posts)	40,000
BHD Coordinator (06posts)	35,000

Eligibility:
- Age:21-45years as on the date of notification.
- Domicile of Jammu&Kashmir
- Minimum 3 years Graduate degree in Business Administration, Management, Commerce, Accounting, Finance, Economics, Chartered Accountant (CA) with least 50% marks or equivalent CGPA from a UGC-recognized university/institute.
- Work Experience: Candidate must have full time, Paid, post qualification work experience in domains such as entrepreneurship development, MSME promotion, Start up Incubation, livelihood, market linkage, skill development or programme management in the development or government sector

Guidelines for detailed selection process,evaluation criteria, and role descriptions: -
https://drive.google.com/file/d/108QkyrJNrcmPxcAIgR-YUeQASfnSGCN7/view?usp=sharing
Yuva Sapne,Nayi Ummedein-MissionYUVA

Note:Thisisapublicserviceadvertisement. No fee is required for the application-process & the detailed advertisement is also available on district administration website i.e. samba.nic.in/samba.gov.in

DIP/J-8844/25
Dtd:9-12-2025

Sd/-
District Development Commissioner
Samba

संपादकीय

ड्रग के खिलाफ़ उपायों को मज़बूत करना

यह काफ़ी तारीफ़ के काबिल है कि J&K में पुलिस ड्रग के खतरे को रोकने के लिए पूरी तरह तैयार है। बॉर्डर पार से नारकोटिक्स लाने और उन्हें युवाओं समेत समाज के कमज़ोर तबके को बेचने और इस पैसे का इस्तेमाल आतंकवाद को बढ़ावा देने के इस बुरे चक्कर को खत्म करने के लिए कई तरह की स्ट्रेटेजी अपनाई गई है।

इसी सिलसिले में, उधमपुर शहर से एक कथित ड्रग पेडलर के खिलाफ़ ताज़ा कार्रवाई की खबर आई है, जिसमें पुलिस ने पुलिस स्टेशन रहमबल में FIR नंबर 180/2025 /S 8/21/22 NDPS एक्ट के सिलसिले में NDPS एक्ट के सेक्शन 68(स्र) के तहत उसकी 60 लाख रुपये की अचल प्रॉपर्टी अटैच की है। अटैच की गई प्रॉपर्टी में उधमपुर के करण नगर, वार्ड नंबर 6 में एक दो मंज़िला रिहायशी घर शामिल है।

UT में यह पहला ऐसा मामला नहीं है, क्योंकि हाल के दिनों में ऐसे कई मामले सामने आए हैं, जिनमें कानून की इन धाराओं के तहत ड्रग तस्करी में शामिल लोगों की प्रॉपर्टी ज़ब्त की गई है।

इस इलाके में नार्को-टेरर नेटवर्क का बढ़ता लेवल लगातार निगरानी, मज़बूत इंटर-एजेंसी कोऑर्डिनेशन और कम्युनिटी की भागीदारी की तुरंत ज़रूरत को और दिखाता है। ड्रग तस्कर कानून लागू होने से बचने के लिए लगातार नए तरीके अपना रहे हैं, इसलिए एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस और लोकल स्टेकहोल्डर्स के लिए हॉटस्पॉट की पहचान करने, संदिग्ध गतिविधियों पर नज़र रखने और युवाओं में जागरूकता बढ़ाने के लिए मिलकर काम करना ज़रूरी हो जाता है, ताकि वे इस खतरनाक जाल का शिकार न बनें।

इसी संदर्भ में, जम्मू और कश्मीर में ड्रग-तस्करी के इकोसिस्टम को खत्म करने के लिए काम कर रही पुलिस ने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बारामूला के पार्किंग एरिया में एक गाड़ी से एक किलोग्राम हेरोइन बरामद की है और गाड़ी में सवार लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें एक महिला भी शामिल है। जिन मामलों में महिलाएं ड्रग तस्करी में शामिल पाई जाती हैं, उनसे कानून लागू करने वाली एजेंसियों के लिए यह ज़रूरी हो जाता है कि वे ड्रग्स और आतंकवाद के मामले में जांच करते समय किसी को न बख्शें, क्योंकि महिलाएं, बच्चे, बूढ़े और दूसरे लोग ऐसे अपराधों में शामिल हो सकते हैं ताकि पुलिस के शक से बचा जा सके।

इस वजह से पुलिस के लिए यह ज़रूरी हो जाता है कि वे ड्रग कंसाइनमेंट की जांच करते समय किसी को न बख्शें, क्योंकि इस गैर-कानूनी धंधे को करने के लिए किसी को भी फंसाया जा सकता है, जो बहुत फायदेमंद है क्योंकि कई ड्रग पेडलर ने नशीले पदार्थों का यह धंधा करने के बाद बहुत सारी प्रॉपर्टी बना ली हैं। चूंकि केंद्र शासित प्रदेश में पुलिस ड्रग तस्करों और नशीली दवाओं का सेवन करने वालों के पीछे लगी हुई है, इसलिए सभी संभावित गलत काम करने वालों पर नज़र रखना ज़रूरी हो जाता है, चाहे उनकी उम्र या जेंडर कुछ भी हो, क्योंकि ड्रग तस्कर अपने गैर-कानूनी लेन-देन को अंजाम देने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं।

यह अच्छी बात है कि एक महिला को गैर-कानूनी ड्रग्स के धंधे में शामिल होने के आरोप में हिरासत में लिया गया है, पुलिस को यह पक्का करना चाहिए कि हर संदिग्ध की जगह-जगह कड़ी चेकिंग और फ़िस्किंग हो ताकि कोई भी पुलिस को चकमा देकर ड्रग्स की तस्करी न कर सके, जो समाज की पूरी सेहत के लिए खतरनाक है।

वंदे मातरम - भारतीय चेतना को ऊर्जा से भर देनेवाला अमर गीत

समय बदला, सत्ता बदली, बहसें बदलीं, पर मानसिकता वही रही। आज भी कुछ राजनेता और संगठन इस गीत का विरोध केवल राजनीतिक या सांप्रदायिक पहचान के नाम पर सेक्युलकर चश्मे से करना चाहते हैं। कभी इसे इस्लाम विरोधी कहा जाता है, कभी सेकुलरिज्म के खिलाफ बताया जाता है। इसी मानसिकता के चलते बिहार विधानसभा से लेकर संसद तक बार-बार विरोध देखने को मिलता है।

मदरसे तक इस पर फतवा जारी कर चुके हैं कि वंदे मातरम् कहना हराम है। सवाल उठता है, क्या इस धरती को मां कहना हराम है या वह मानसिकता हराम है जो राष्ट्रभक्ति को मजहबी चश्मे से तौलती है।

-डॉ. मयंक चतुर्वेदी

भारत जैसे उत्कट आध्यात्मिक और सांस्कृतिक राष्ट्र में यदि किसी शब्द ने सबसे अधिक ऊर्जा, सबसे अधिक प्रेरणा और सबसे अधिक एकता का संचार किया है, तो वह है वंदे मातरम्। किंतु विडंबना यह है कि इसी भूमि पर जन्मे कुछ लोग आज इस राष्ट्रीय गीत को स्वीकार करने में भी हिचकते हैं।

यह विरोध वास्तव में कहना चाहिए कि उस भावना का अस्वीकार है जिसने भारत को स्वतंत्रता के पथ पर आगे बढ़ाया और उसके नागरिकों में मातृभूमि के प्रति समर्पण की चेतना भरी।

भारतीय संस्कृति में भूमि को माता मानना किसी धर्म-ग्रंथ का उपदेश नहीं है, यह तो सहस्राब्दियों से चली आ रही जीवनशैली है। जो धरती हमें अन्न देती है, जल देती है, जीवन देती है उसे मां कहना स्वाभाविक है। किंतु आज यही सरल, स्वाभाविक भावना कुछ लोगों को अपने मजहबी चश्मे से देखकर भारी लगती है। यह सोच देखा जाए तो सिर्फ तर्कहीन होने तक सीमित नहीं है, इससे राष्ट्र की सामूहिक चेतना तो भी भारी ठेस पहुंचती है।

एक दृष्टि यदि इसके इतिहास पर डालें तो 1870 के दशक में बंकिमचंद्र चट्टोपाध्याय ने जब वंदे मातरम् की रचना की, तब वे शायद स्वयं भी नहीं जानते थे कि उनकी यह कविता एक दिन भारतीय स्वाधीनता के आह्वान का कारण बन जाएगी। सात नवंबर 1875 को 'बंगदर्शन' में प्रकाशित इस गीत को उन्होंने बाद में अपने ऐतिहासिक उपन्यास आनंदमठ में स्थान दिया।

यह गीत साहित्य तक सीमित नहीं रहा, ये सीधे तौर पर मातृभूमि की आराधना है, प्रकृति का उत्सव है और भारतीय अस्मिता का घोष है। इसीलिए ही संविधान सभा ने 1950 में इसे राष्ट्रीय गीत के रूप में स्वीकार करके इसे राष्ट्र चेतना के केंद्र में स्थायी स्थान दिया है। इस एतिहासिक तथ्य को भी नहीं भूलना चाहिए कि 1905 के बंगाल विभाजन ने वंदे मातरम् को वह शक्ति दी, जिसने इसे आंदोलन की धड़कन बना दिया। छात्र, युवा, स्त्रियां, किसान सब इस गीत को गाते हुए ब्रिटिश शासन के विरुद्ध खड़े हुए।

अरविंदो घोष, बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक, यहां तक कि क्रांतिकारी दलों ने भी इसे अपना प्रेरणामंत्र बनाया। कहना होगा कि परतंत्रता के अंधेरे में यही गीत सूर्य सा चमका और भारतीयों को साहस देता रहा। ब्रिटिश सत्ता को डर था कि यह गीत जनांदोलन को विश्वज्वाला बना देगा इसलिए स्कूलों से लेकर सार्वजनिक स्थलों तक इसके गायन पर प्रतिबंध लगाए गए। किंतु क्या साम्राज्य की ताकत एक गीत की शक्ति को रोक सकी नहीं। जितना दमन हुआ, उतनी ही तेज इसके स्वर उठे।

वर्ष 1907 में मैडम भीकाजी कामा ने जर्मनी के स्टटगार्ट में भारत का पहला तिरंगा फहराया। तिरंगे पर लिखा था वंदे मातरम्। वह क्षण तत्कालीन समय में प्रतीकात्मक नहीं रहा था, वह तो भारत की अंतरराष्ट्रीय घोषणा थी कि इस राष्ट्र की चेतना पुकार रही है, वह दबी नहीं है, वह जागृत है और अपनी स्वाधीनता तक अनवरत वह संघर्ष करती रहेगी। किंतु दुर्भाग्य जब पूरी दुनिया में वंदे मातरम् भारतीय स्वाधीनता का पर्याय बन चुका था, तभी 1908 में मुस्लिम लीग ने इसे इस्लाम विरोधी बताकर विरोध शुरू किया। तर्क यह दिया गया कि गीत के कुछ छंद देवी-उपासना की ओर संकेत करते हैं।

यह विरोध आगे बढ़ा और 1937 में कांग्रेस ने जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में एक समिति बनाकर गीत की समीक्षा करवाई। मौलाना आजाद ने स्पष्ट कहा कि पहले दो पद किसी मजहबी भावना को नहीं ठेस पहुंचाते। परिणामस्वरूप गीत का संक्षिप्त दो पदों वाला स्वरूप स्वीकार किया गया। किंतु प्रश्न यह है क्या किसी धार्मिक भावना के नाम पर राष्ट्र की भावना को सीमित किया जा सकता है क्या मातृभूमि को माता कहना किसी भी मजहब की कसौटी पर अपराध है

समय बदला, सत्ता बदली, बहसें बदलीं, पर मानसिकता वही रही। आज भी कुछ राजनेता और संगठन इस गीत का विरोध केवल राजनीतिक या सांप्रदायिक पहचान के नाम पर सेक्युलकर चश्मे से करना चाहते हैं। कभी इसे इस्लाम विरोधी कहा जाता है, कभी सेकुलरिज्म के खिलाफ बताया जाता है। इसी मानसिकता के चलते बिहार विधानसभा से लेकर संसद तक बार-बार विरोध देखने को मिलता है।

मदरसे तक इस पर फतवा जारी कर चुके हैं कि वंदे मातरम् कहना हराम है। सवाल उठता है, क्या इस धरती को मां कहना हराम है या वह मानसिकता हराम है जो राष्ट्रभक्ति को मजहबी चश्मे से तौलती है।

कहना होगा कि आज 150 साल बाद भी वंदे मातरम् सिर्फ एक कविता नहीं है, यह भारतीयता की जागृत चेतना है, जिसमें संपूर्ण भारत का कण-कण समाया हुआ है। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, नेताजी सुभाषचंद्र बोस न जाने कितने ही वीरों के कंठों में यह गीत गाया जाता रहा है। यह वह धुन है जिसने एक परतंत्र देश को स्वतंत्रता की राह दिखाई है। यह उन्हें गहराई से समझना होगा जो इसका विरोध करते हैं कि वंदे मातरम् कहने का अर्थ किसी देवी की पूजा करना नहीं है, यह मातृभूमि को प्रणाम करना है। क्या कोई भी धर्म अपनी धरती का सम्मान करने से रोकता है नहीं किंतु यदि कोई व्यक्ति इस सरल सम्मान को भी मजहब की दीवारों के भीतर बंद कर देता है, तो वह राष्ट्र की साझा चेतना से कट जाना है। किसी को यह नहीं भूलना चाहिए कि भारत एक ऐसा देश है, जहाँ मंदिरों से लेकर हर जगह एक ही मिट्टी की खुशबू है। जब वही मिट्टी जीवन का आधार देती है, तो उसे मां कहना सांस्कृतिक कृतज्ञता है, धार्मिक अनुष्ठान नहीं। धार्मिक स्वतंत्रता भारत की विशिष्ट पहचान है, पर राष्ट्रगीत का विरोध धार्मिक स्वतंत्रता नहीं, राष्ट्रचेतना से विमुखता है। ऐसे में आज संसद में हो रही चर्चाएँ सिर्फ इतिहास का पुनरावलोकन नहीं है, यह भावी पीढ़ियों को यह स्मरण दिलाने का अवसर हैं कि देश से प्रेम ही सच्चा राष्ट्रधर्म है। जिसमें कि वंदे मातरम् का विरोध करना इतिहास का भी अपमान है और उन लाखों बलिदानियों का भी, जिन्होंने इसके स्वरों के साथ फांसी के फंदे को हंसते हुए चूमा है। यह गीत हमें जोड़ता है, प्रेरित करता है और यह स्मृति दिलाता है कि हम उस महान भूमि की संतान हैं, जो इस भूमि को मां कहता है। जब यह गीत अपनी 150वीं वर्षगांठ मना रहा है, तब यह हर भारतीय का कर्तव्य है कि वह अपनी व्यक्तिगत या मजहबी सीमाओं से ऊपर उठकर इसके भाव से स्वयं को जोड़े। क्योंकि वंदे मातरम् एक सीमित स्वर से कहीं अधिक व्यापक, एक शाश्वत नाद है, जिसने इस देश को आत्मगौरव और स्वतंत्रता का मार्ग दिखाया है। यही हमारी पहचान है, यही हमारी श्रद्धा। वंदे मातरम्। भारत माता की जय!

(लेखक, फिल्म सेंसर बोर्ड एडवाइजरी कमेटी के पूर्व सदस्य एवं वरिष्ठ पत्रकार हैं।)

लोगों के अधिकारों की सुरक्षा के हों सकारात्मक प्रयास

रमेश सर्राफ धमोरा

हम 10 दिसंबर को मानवाधिकारों का उत्सव मनाते हैं। उस दिन की स्मृति में जब संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1948 में मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को अपनाया था। यह घोषणा हमारे समाजों के मानवाधिकार ढांचे की रीढ़ है, जहां हममें से प्रत्येक को बिना किसी भेदभाव के शांति और सुरक्षा के साथ रहने और फलने-फूलने का अधिकार है। 1950 में संयुक्त राष्ट्र ने हर वर्ष की 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस मनाना तय किया था। 75 वर्ष पहले पारित हुआ विश्व मानवाधिकार घोषणा पत्र एक मील का पत्थर हैं, जिसने समृद्धि, प्रतिष्ठा व शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के प्रति मानव की आकांक्षा प्रतिबिंबित की है। आज यही घोषणा पत्र संयुक्त राष्ट्र संघ का एक बुनियादी भाग है। 10 दिसंबर 2025 को दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण वैश्विक प्रतिज्ञाओं में से एक मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा की 77वीं वर्षगांठ है। 2025 में मानवाधिकार दिवस की थीम हमारी रोजमर्रा की अनिवार्यताएं, तीन सरल सत्यों पर जोर देती हैं। मानवाधिकार सकारात्मक हैं, मानवाधिकार आवश्यक हैं और मानवाधिकार प्राप्य हैं।

मानव अधिकार वे मूल अधिकार हैं जो इस धरती पर प्रत्येक व्यक्ति के पास हैं। मानवाधिकार मौलिक अधिकार और स्वतंत्रता हैं। मानवाधिकारों में जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार, गुलामी और यातना से मुक्ति, राय और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, काम और शिक्षा का अधिकार और बहुत कुछ शामिल हैं। बिना किसी भेदभाव के हर कोई इन अधिकारों का हकदार है। भारत का स्वतंत्रता आंदोलन मानवाधिकारों के लिए प्रेरणा का एक बड़ा स्रोत रहा है। कुछ अधिकार ऐसे होते हैं जो व्यक्ति को जन्मजात मिलते हैं। उन अधिकारों का व्यक्ति के आयु, प्रजातीय मूल, निवास-स्थान, भाषा, धर्म पर कोई असर नहीं पड़ता।

देश के विशाल आकार व विविधता तथा सम्प्रभुता सम्पन्न धर्म-निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणतंत्र के रूप में इसकी प्रतिष्ठा तथा एक भूतपूर्व औपनिवेशिक राष्ट्र के रूप में इसके इतिहास के परिणामस्वरूप भारत में मानवाधिकारों की परिस्थिति एक प्रकार से जटिल हो गई है। भारत का संविधान मौलिक अधिकार प्रदान करता है जिसमें धर्म की स्वतंत्रता भी अंतर्भुक्त है।

संविधान की धाराओं में बोलने की आजादी के साथ-साथ कार्यपालिका और न्यायपालिका का विभाजन तथा देश के अन्दर एवं बाहर आने-जाने की भी आजादी दी गई है।

भारतीय परिदृश्य में यह समझ पाना थोड़ा मुश्किल है कि क्या वाकई में मनुष्य के लिए चिन्हित किये गए मानवाधिकारों की सार्थकता है।

भारत में 28 सितम्बर 1993 से मानव अधिकार कानून अमल में आया। 12 अक्टूबर 1993 में सरकार ने राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन किया। आयोग के कार्यक्षेत्र में नागरिक और राजनीतिक के साथ आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार भी आते हैं। जैसे बाल मजदूरी, स्वास्थ्य, भोजन, बाल विवाह, महिला अधिकार, हिरासत और मुठभेड़ में होने वाली मौत, अल्पसंख्यकों और अनुसूचित जाति और जनजाति के अधिकार। पूरे विश्व में इस बात को अनुभव किया गया है और इसीलिए मानवीय मूल्यों की अवहेलना होने पर वे सक्रिय हो जाते हैं। इसके लिए हमारे संविधान में भी उल्लेख किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 39, 43, 45 देश में मानवाधिकारों की रक्षा करने के लिए सुनिश्चित हैं।

कहने में मानवाधिकार शब्द बहुत बड़ा है। क्योंकि मानवाधिकारों से हर व्यक्ति का हित जुड़ा होता है। आज के दौर में कोई भी मानव को उनके वास्तविक अधिकार नहीं देना चाहता है। हमारे देश के संविधान में मानव को बहुत सारे अधिकार दिये गये हैं। मगर उन पर अमल नहीं हो पाता है। मानव अधिकारों की रक्षा के लिए बनाये गये कानून महज कागजों में सिमट कर रह जाते हैं।

इतिहास गवाह है कि भारत ने कभी भी संस्कृति, धर्म या अन्य कारकों के आधार पर दूसरों को अपने अधीन करने की कोशिश नहीं की है। भारत एक ऐसा देश है जिसके मूल में मानवाधिकार की अवधारणा है। भारत के लोग मानवाधिकारों का सम्मान करते हैं और उनकी रक्षा करने का संकल्प भी लेते हैं। भारत विश्व स्तर पर आज भी मानवाधिकार का समर्थन करता रहा है। मानवाधिकार दिवस की नींव विश्व युद्ध की विभीषिका से झुलस रहे लोगों के दर्द को समझ कर और उसको महसूस कर रखी गई थी। किसी भी इंसान की जिन्दगी, आजादी, बराबरी और सम्मान के अधिकार का नाम ही मानवाधिकार है। भारतीय संविधान इन अधिकारों की न सिर्फ गारंटी देता है, बल्कि इसे तोड़ने वाले को अदालत सजा भी देती है।

पूरी दुनिया में मानवता के खिलाफ हो रहे जुल्मों-सितम को रोकने, उसके खिलाफ संघर्ष को नई परवाज देने में इस दिवस की महत्वपूर्ण भूमिका है। हर शख्स को बराबरी का अधिकार देना लोकतंत्र का अहम घटक है। यही वजह है कि आज ज्यादातर सरकार इस अधिकार को कायम करने की कोशिश कर रही है। इंसानी अधिकार हमारे अस्तित्व और दुनिया में आत्मसम्मान से रहने की गारंटी होते हैं। हमारी भौतिक और आत्मिक सुरक्षा बरकरार रखते हुए लगातार तरक्की में अहम होते हैं। इसके अंतर्गत भोजन का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, शोषण से रक्षा का अधिकार, प्रवास का अधिकार, बाल शोषण, उत्पीड़न पर रोक, महिला हिंसा, असमानता, धार्मिक हिंसा पर रोक जैसे कई मजबूत कानून बनाए गए हैं। यही वजह है कि हर लोकतांत्रिक देश मानवाधिकार अधिकारों की सशक्त पैरवी करते नजर आते हैं।

इस दुनिया में जो भी मानव जन्म लेता है उसके साथ उसके कुछ अधिकार भी वजूद में आते हैं। कुछ अधिकार हमें परिवार देता है तो कुछ समाज, कुछ अधिकार हमारा मुल्क देता है, तो कुछ दुनिया लेकिन आज भी दुनिया में बहुत से लोग ऐसे हैं जो या तो अपने अधिकारों से अंजान हैं या उनके अधिकारों का हनन किया जा रहा है। हर तबके, हर शहर और दुनिया के कोने-कोने में किसी न किसी वजह से लोगों को बराबरी के हक से महरूम रखने का सिलसिला बदस्तूर जारी है। इतिहास गवाह है कि दुनिया में हुई बड़ी से बड़ी क्रांति के पीछे अधिकारों का हनन ही अहम वजह रही है। हमेशा ही अपने अधिकारों के लिए इंसान को लंबी जंग लडनी पड़ी है। दुनिया में तमाम जगह लोगों ने अपन हक की लड़ाई में लाखों कुर्बानियां दी हैं और आज भी बहुत से लोग अपने अधिकारों की जंग लड़ रहे हैं।

मानवाधिकारों की रक्षा के लिए कानून बनाये गए और उनको लागू करने या करवाने के लिए प्रयास भी हो रहे हैं। समाज में मानवाधिकारों के होने वाले उल्लंघन के प्रति अगर मानव ही जागरूक नहीं है तो फिर इनका औचित्य क्या है? देखें तो पता चलेगा की कितने मानवाधिकारों का हनन मानव के द्वारा ही किया जा रहा है। मानव के द्वारा मानव के दर्द को पहचानने और महसूस करने के लिए किसी खास दिन की जरूरत नहीं होती है। अगर हमारे मन में मानवता है ही नहीं तो फिर हम सालभर ये मानवाधिकार का झंडा उठा कर घूमते रहें कुछ भी नहीं किया जा सकता है।

(लेखक, हिन्दुस्थान समाचार से संबद्ध हैं।)

बच्चों का पालन-पोषण और शिक्षा-दीक्षा देना होता जा रहा चुनौती भरा

गिरीश्वर मिश्र

भारतीय समाज में प्राचीन काल से बच्चों की निराली छवि संजोई जाती रही है। बाल गोपाल की नटखट लीलाओं का आकर्षण अब भी है। कई घरों में लड्डू गोपाल की पूजा भी होती है। वैसे भी बच्चों की उपस्थिति, उनके हाव-भाव, किलकारी, खेल-कूद में भावनाओं की जिस ऊष्मा से भर देने वाले होते हैं वह अलौकिक यानी ईश्वरीय ही होती है। निश्छल, स्वाभाविक और सहज बच्चे मन के सच्चे होते हैं। पर आम जन जो संतान की चाहत रखते हैं वे समझदार हो गए हैं और परिवार का आकार सीमित रखने की कोशिश करते हैं। शिक्षित प्रौढ़ अधिक सचेत हैं और वे सीमित परिवार की ओर अग्रसर हो रहे हैं। इस बदलाव का प्रमुख कारण संयुक्त परिवारों का टूटना, अपने मूल स्थान से विस्थापन और तेजी से बढ़ती मँहगाई का अनिवार्य दबाव है। साथ ही वैश्वीकरण के दौर में आकांक्षाओं को भी पर लग गया है और नई-नई संभावनाओं के द्वार खुलते जा रहे हैं जो जीवन की वरीयताओं को उलट-पलट रहे हैं। परिवार ही सबसे पहले उनकी भेंट चढ़ रहा है। कई अत्याधुनिक लोग परिवार को वैकल्पिक मानने लगे हैं । कुल मिला कर आज के कठिन समय में मध्य और उच्च मध्य वर्ग के परिवारों में विशेष रूप से बच्चों का पालन-पोषण और शिक्षा-दीक्षा को अच्छी तरह से अंजाम देना चुनौती भरा होता जा रहा है।

देश के स्तर पर समस्याएं विराट हैं। आज विश्व की कुल जनसंख्या का छठाँ भाग भारत में रहता है। इसमें बच्चे अर्थात् 18 साल तक की आयु वाले लगभग 39 प्रतिशत हैं। एक अनुमान के हिसाब से भारत में 253 मिलियन किशोर हैं। देश में नि:संदेह आर्थिक प्रगति दर्ज हुई है पर उसके अनुपात में जीवन की गुणवत्ता सबके लिए ख़ास तौर पर बच्चों और स्त्रियों के लिए उतनी नहीं बढ़ी है जितनी अपेक्षित है । वस्तुत- भारत वर्ष में बच्चों की स्थिति गंभीर विचार का विषय हो कर भी प्राय- हाशिये पर ही रहती रही है हालांकि कुछ मामलों में प्रगति दर्ज हुई है। उदाहरण के लिए शिशु मृत्यु दर और स्कूल छोड़ने की दर घटी है। परंतु बाल विवाह, कुपोषण और गरीबी से अभी भी छुटकारा नहीं मिल सका है। गौर तलब है कि आज भी हज़ार बच्चों में 95 बच्चे अपना पाँचवाँ जन्म दिवस मनाने के पहले ही काल कवलित हो जाते हैं। आज भी 4 वर्ष से 14 वर्ष की आयु वर्ग के स्कूल जाने वाले बच्चों का एक बड़ा हिस्सा, आधे से कुछ कम, प्राइमरी शिक्षा पूरी नहीं कर पाता । भारत के आधे बच्चे आज भी कुपोषण के शिकार हो रहे हैं। एक अध्ययन के हिसाब से हर दो लड़कियों में एक कुपोषित मिलती है। तीन महीने तक की आयु के बच्चों में 74 प्रतिशत न्यून या अल्प पोषण पाते हैं। शहरी इलाकों में, खास तौर पर अनौपचारिक हलकों, में ग़रीबी निश्चित रूप से बाल-विकास के मार्ग में बहुत बड़ी बाधा है। आज भी श्वास रोग और डायरिया (उल्टी दस्त) शिशु मृत्यु का एक बड़ा कारण बना हुआ है। अन्य दक्षिण पूर्व एशियाई देशों की तुलना में बाल-विवाह यानी 18 वर्ष की उम्र के पहले विवाह की दर आज भी भारत में सबसे ज़्यादा है। इसी तरह देश के कुछ भागों में अभी भी पुत्र की पसंद पुत्रियों की अपेक्षा ज़्यादा है जिससे जेंडर से जुड़े भेद-भाव की गुंजाइश बढ़ती है ।

भारत की जनसंख्या का यह एक सुखद पहलू यह है कि उसमें युवा वर्ग का प्रतिनिधित्व अधिक है। भारत अब विश्व में एक युवा-प्रधान देश हो गया है। देश में किशोरों की संख्या पूरे विश्व में सर्वाधिक है। उनके शिक्षा, स्वास्थ्य और कौशल-संवर्धन की ख़ास जरूरत है। ये सामाजिक, राजनैतिक और आर्थिक सभी दृष्टियों से भारत के विकास के लिए निश्चित रूप से लाभकारी सिद्ध होने वाले हैं बशर्ते वे सुरक्षित रहें, उनका स्वास्थ्य ठीक रहे, तथा वे सुशिक्षित और कौशल युक्त बन सकें । किशोरियों पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है जिनके लिए कुपोषण और बाल-विवाह बड़ी मुसीबत है और उनको ज़्यादा प्रभावित होने की संभावना रहती है। किशोरियों के सशक्तीकरण के मार्ग में ये बड़ी बाधाएँ बनी हुई हैं। युवा वर्ग को प्रोत्साहित और विकास के मार्ग पर अग्रसर कराते हुए ही विकसित भारत-2047 की परिकल्पना साकार हो सकेगी। देश में बच्चों की सुरक्षा और उनके पालन-पोषण पर जोर देने वाली कई सरकारी नीतियां बनी हैं। इस सिलसिले में सरकार का 'मिशन वात्सल्य' बच्चों के स्वास्थ्य और बाल-कल्याण के लिए समर्पित है। कुछ संकेत सकारात्मक बदलाव बताते हैं पर स्वास्थ्य, शिक्षा और खुशहाली के प्रश्न अभी भी बरकरार हैं। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और और स्वास्थ्य की जरूरतें अभी भी संतोषजनक ढंग पूरी नहीं हो पा रही हैं। इसी तरह बाल-विवाह को रोकना आवश्यक है। पिछले दो दशकों में देश में निश्चित रूप से उल्लेखनीय प्रगति हुई है। अति गरीबी 21 प्रतिशत कम हुई है। इसी तरह अब 80 प्रतिशत बच्चों का जन्म स्वास्थ्य सुविधा केंद्रों पर होता है। तब भी ग्रामीण क्षेत्र, मलिन बस्ती, अनुसूचित जाति तथा जनजातियों की स्थिति चिंतनीय बनी हुई है ।विशेष रूप से वंचित समुदाय अनेक प्रकार के अभावों से ग्रस्त हैं। अच्छी स्वास्थ्य सुविधा की बड़ी कमी है। सभी क्षेत्रों में स्वच्छता और शुद्ध पेय जल की उपलब्धता सुनिश्चित किया जाना अभी भी एक चुनौती है। ऊपर से सूखा, बाढ़, भूकंप, भूस्खलन, जलवायु-परिवर्तन और शरणार्थी समुदायों का आना-जाना ऐसी आकस्मिक परिस्थितियाँ हैं जो विकास की गति को अचानक थाम लेती हैं।

अब वैश्विक स्तर पर इस बात पर अधिकांश देशों में सहमति बन गई है कि बच्चों के अधिकारों को सुरक्षित रखना बेहद जरूरी है। बाल श्रम और उनके साथ होने वाले अत्याचार बंद होने चाहिए। परंपरागत रूप से बच्चों की देख-रेख और सुरक्षा परिवार और समुदाय की जिम्मेदारी रही है। पितृसत्तात्मक परिवेश में अक्सर यह भुला दिया जाता है कि बच्चे भी 'व्यक्ति' हैं और उनके भी अधिकार हैं।अब स्पष्ट रूप से बच्चों के अधिकारों में जीवन का अधिकार, शिक्षा, सुरक्षा, भागीदारी, विकास, स्वास्थ्य, कल्याण, पहचान, अभिव्यक्ति, भेदभाव से मुक्ति और सुरक्षित वातावरण के अधिकार शामिल किए गए हैं । परंतु गरीबी, भूख, पेय जल की उपलब्धता, रोग, शिक्षा की कमी, बच्चों के साथ दुर्व्यवहार, बच्चों से श्रम कराना, बच्चों के प्रति हिंसा और शोषण, तथा बाल-विवाह आदि ऐसे विकट संकट हैं जो बच्चों के जीवन, सुरक्षा और विकास में भागीदारी को नकारात्मक रूप से प्रभावित कराते हैं। कानून बच्चों के साथ दुर्व्यवहार, उनका शोषण और भेदभाव करने के विरुद्ध संरक्षण देता है और उसके उल्लंघन के लिए दंड का भी प्रविधान करता है। फिर भी देश में वंचित वर्ग के बच्चे बड़ी संख्या में कुपोषण के शिकार हैं। उनके आहार में कार्बोहाइड्रेट की अधिकता और प्रोटीन की कमी भी एक बड़ा कारण है । इस का परिणाम होता है अवरुद्ध विकास। एक अनुमान के अनुसार 6.1 करोड़ बच्चे भूख और ख़राब स्वास्थ्य से पीड़ित हैं। स्वच्छता और संतुलित आहार के लिए क़ानून, जागरण और सामाजिक सुधार सबकी जरूरत है। कानूनों के बावजूद आज भी बाल-श्रम जारी है। मासूम बच्चे कई शिफ्ट में काम करते हैं और उनको आराम नहीं दिया जाता । उल्टे उन्हें मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना मिलती है। पौष्टिक भोजन और स्वच्छ पानी विकास की प्राथमिक आवश्यकता होती है।

संविधान के 86 वें संशोधन में 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए नि:शुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया है। बच्चों को जरूरत को ध्यान में रख कर नई शिक्षा नीति-2020 में भी कई प्राविधान किए गए हैं जो बच्चों की रुचि, प्रतिभा, मातृ भाषा और संस्कृति के आलोक में उनके समग्र विकास का लक्ष्य पाने के लिए अवसर पैदा कर रहे हैं। बच्चों के विकास के लिए कई ग़ैर सरकारी प्रयास, भी शुरू हुए हैं जो बच्चों के लिए प्राविधान, उनकी सुरक्षा और प्रतिभागिता सुनिश्चित करने की दृष्टि से काम कर रहे हैं। आम तौर पर भारतीय समाज में बच्चों के प्रति प्रेम के भाव प्रबल होते हैं। बच्चों से मिलना, उनसे बात करना और उनका कोमल स्पर्श प्रीतिकर होता है पर बदलती परिस्थितियों के दबाव के बीच बच्चों पर सकारात्मक रूप से ध्यान देना और उनकी अवस्था के अनुरूप अवसर उपलब्ध कराना परिवार, समुदाय और स्कूल जैसी संस्थाओं को पुनर्विचार के लिए आमंत्रित करता है। मीडिया की सकारात्मक भूमिका कैसे सुनिश्चित हो इस पर गंभीर विचार कर कदम उठाने की आवश्यकता है। बच्चे समाज के भविष्य को अनिवार्य रूप से गढ़ते हैं इसलिए उन पर ध्यान देना समाज के अस्तित्व का प्रश्न बन जाता है। बच्चों का पालन-पोषण दायित्व भी है और निर्माण का भी अवसर है।

(लेखक, महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा के पूर्व कुलपति हैं।)

एडिलेड टेस्ट में कमिंस की वापसी तय, हेज़लवुड एशेज से बाहर

एजेंसी

एडिलेड। ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस की करीब पांच महीने बाद टेस्ट क्रिकेट में वापसी तय मानी जा रही है। वह इंग्लैंड के खिलाफ होने वाले तीसरे एशेज टेस्ट में टीम की कप्तानी करते नजर आएंगे। हालांकि, ऑस्ट्रेलिया को बड़ा झटका लगा है क्योंकि तेज गेंदबाज जोश हेज़लवुड पूरे एशेज सीरीज से बाहर हो गए हैं।

टीम के मुख्य कोच एंड्रयू मैकडोनाल्ड ने मंगलवार को इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि हेज़लवुड अब इस गर्मी में इंग्लैंड के खिलाफ नहीं खेल पाएंगे। पिछले महीने शेफील्ड शील्ड के दौरान उन्हें हैमस्ट्रिंग में खिंचाव आया था और इसके बाद पिछले सप्ताह उनके अकिलीज़ में भी समस्या उभर आई, जिससे उनकी वापसी की उम्मीदें खत्म हो गईं। मैकडोनाल्ड ने कहा, 'उनके लिए यह बेहद निराशाजनक है। कुछ ऐसे झटके लगे जिनकी हमें उम्मीद नहीं थी। हमें लगा था कि वह इस सीरीज में अहम भूमिका निभाएंगे, लेकिन दुर्भाग्य से अब उन्हें यह मौका नहीं मिल पाएगा।' हेज़लवुड अब फरवरी में होने वाले टी20 वर्ल्ड कप को लक्ष्य बनाकर पूरी तरह फिट होने की कोशिश करेंगे। दूसरी ओर, पैट कमिंस के लिए सब कुछ योजना के अनुसार आगे बढ़ रहा है। उन्हें बुधवार को घोषित होने वाली 15 सदस्यीय टीम में शामिल किए जाने की पूरी संभावना है और वह एक बार फिर स्टीव स्मिथ से कप्तानी की जिम्मेदारी संभालेंगे। कमिंस ने जुलाई में वेस्टइंडीज दौरे के दौरान पीठ में दर्द महसूस करने के बाद से कोई मुकाबला नहीं खेला है, लेकिन उनकी रिकवरी उम्मीद से तेज रही है।

मैकडोनाल्ड ने बताया कि कमिंस ने ब्रिसबेन टेस्ट से पहले एलन बॉर्डर फील्ड पर कई स्पेल डालकर मैच जैसी परिस्थितियों का अभ्यास किया। उन्होंने कहा, 'हमने पहले भी लंबे ब्रेक के बाद पैट को इसी तरह तैयार किया है। उनकी फिटनेस और स्किल दोनों तैयार हैं। अगर अगले एक हफ्ते में कुछ अनहोनी नहीं होती, तो मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि पैट एडिलेड में टॉस करते नजर आएंगे। ' टीम को राहत की बात यह भी है कि बाएं हाथ के तेज गेंदबाज मिशेल स्टार्क, जो अब तक दो टेस्ट में 18 विकेट लेकर सीरीज के सबसे सफल गेंदबाज हैं, फिट हैं। हालांकि ब्रिसबेन टेस्ट के दौरान उन्हें बाईं ओर थोड़ी परेशानी थी, लेकिन कोच ने स्पष्ट किया कि वह एडिलेड टेस्ट के लिए पूरी तरह उपलब्ध रहेंगे। ऑस्ट्रेलियाई टीम प्रबंधन अंतिम तीन टेस्ट में तेज गेंदबाजों के वर्कलोड को लेकर सतर्क है। एडिलेड से मेलबर्न और फिर सिडनी के बीच चार-चार दिन के छोटे अंतराल को देखते हुए कुछ गेंदबाजों को आराम दिया जा सकता है। इस कारण माइकल नेसर, स्कॉट बोलैंड और ब्रेंडन डोगेट में से दो खिलाड़ी एडिलेड टेस्ट से बाहर हो सकते हैं, जिससे आगे के मुकाबलों के लिए आक्रमण को तरोताजा रखा जा सके।

प्रज्ञानानंद ने कैंडिडेट्स 2026 के लिए किया क्वालीफाई, भारत से एकमात्र पुरुष प्रतिनिधि

एजेंसी

नई दिल्ली। ग्रैंडमास्टर आर. प्रज्ञानानंद ने फिडे सर्किट 2025 का खिताब जीतकर कैंडिडेट्स टूर्नामेंट 2026 के लिए अपना स्थान पक्का कर लिया है। इसके साथ ही वह अगले साल होने वाले कैंडिडेट्स टूर्नामेंट में भारत की ओर से एकमात्र पुरुष खिलाड़ी होंगे। प्रज्ञानानंद का यह साल अब तक शानदार रहा है। उन्होंने विश्व शतरंज के कई प्रतिष्ठित टूर्नामेंट्स में बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए टाटा स्टील मास्टर्स, सुपरबेट चेस क्लासिक रोमानिया, उजचेस कप मास्टर्स और लंदन चेस क्लासिक ओपन जैसे खिताब अपने नाम किए। इसके अलावा उन्होंने स्टेपान अवाग्यान मेमोरियल में दूसरा स्थान हासिल किया, जबकि सिनक्वेफील्ड कप में 12वें स्थान पर रहे। हाल ही में समाप्त हुए फाइड वर्ल्ड कप में भी प्रज्ञानानंद ने चौथे राउंड तक का सफर तय किया, जहां से उन्हें बाहर होना पड़ा। इसके बावजूद पूरे सीजन में उनके निरंतर प्रदर्शन ने उन्हें फाइड सर्किट रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंचा दिया, जिसका सीधा लाभ कैंडिडेट्स 2026 के रूप में मिला।

दूसरे वनडे में स्लो ओवर रेट के चलते भारतीय टीम पर 10 प्रतिशत जुर्माना

नई दिल्ली। रायपुर में 3 दिसंबर को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेले गए दूसरे वनडे मैच में स्लो ओवर-रेट बनाए रखने के कारण भारतीय टीम पर जुर्माना लगाया गया है। आईसीसी ने टीम इंडिया पर मैच फीस का 10 प्रतिशत जुर्माना लगाया है। एमिरेट्स आईसीसी एलीट पैनल के मैच रेफरी रिची रिचर्डसन ने यह सजा सुनाई, जब केएल राहुल की अगुवाई वाली भारतीय टीम समय भत्तों को ध्यान में रखने के बाद तय लक्ष्य से दो ओवर पीछे पाई गई। आईसीसी खिलाड़ियों और सहयोगी स्टाफ के आचार संहिता के अनुच्छेद 2.22 के अनुसार न्यूनतम ओवर-रेट उल्लंघन के मामले में तय समय में प्रत्येक ओवर पूरा न कर पाने पर टीम के खिलाड़ियों पर उनकी मैच फीस का पांच प्रतिशत जुर्माना लगाया जाता है। इसी आधार पर दो ओवर कम रहने पर कुल 10 प्रतिशत जुर्माना लगाया गया। भारतीय कप्तान केएल राहुल ने इस आरोप को स्वीकार कर लिया और प्रस्तावित सजा मान ली, जिसके चलते औपचारिक सुनवाई की आवश्यकता नहीं पड़ी। यह आरोप ऑन-फील्ड अंपायर रॉड टकर और रोहन पंडित, तीसरे अंपायर सैम नोगाजस्की तथा चौथे अंपायर जयरामन मदनगोपाल द्वारा लगाया गया।

बांगर ने फिनिशर की भूमिका के लिए जितेश शर्मा का समर्थन किया, सैमसन इस स्थान पर सबसे सही खिलाड़ी

नई दिल्ली। भारतीय टीम में टी20 फॉर्मेट के लिए बल्लेबाजी क्रम को लेकर लगातार चर्चाएं चल रही हैं। इसी बीच भारत के पूर्व क्रिकेटर और मशहूर बैटिंग कोच संजय बांगर ने संजू सैमसन और जितेश शर्मा की भूमिकाओं को लेकर बड़ा बयान दिया है। बांगर का मानना है कि संजू सैमसन एक बेहतरीन बल्लेबाज हैं, लेकिन उनकी असली ताकत टॉप ऑर्डर में बल्लेबाजी करना है। वहीं निचले क्रम पर बड़े शॉट खेलने और पारी को फिनिश करने के मामले में जितेश शर्मा कहीं बेहतर साबित होते हैं। ऐसे में दक्षिण अफ्रीका ञ्ज20ढ्ढ सीरीज में उन्हें प्राथमिकता मिल सकती है। संजय बांगर ने कहा कि भारतीय टीम मैनेजमेंट ने संजू सैमसन को कई मौकों पर ओपनर और टॉप ऑर्डर में आजमाया है। शुभमन गिल की अनुपस्थिति में बांग्लादेश और दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सैमसन ने शतक जमाकर अपनी क्षमता साबित भी की। हालांकि, ञ्ज20 क्रिकेट में उनका सर्वश्रेष्ठ उपयोग वहीं हो सकता है जहां उन्हें नई गेंद मिले और वे आक्रामक शुरुआत कर सकें। बांगर के अनुसार, मिडिल ऑर्डर में पहले से ही तिलक वर्मा, शिवम दुबे और हार्दिक पांड्या जैसे मजबूत विकल्प मौजूद हैं। ऐसे में सैमसन को नंबर 4 से 6 के स्लॉट में फिट करना मुश्किल हो जाता है।

दक्षिण अफ्रीकी दिग्गज खिलाड़ी की वनडे में होगी वापसी, वर्ल्ड कप 2027 को लेकर बड़ा फैसला

नई दिल्ली। दक्षिण अफ्रीका के हार्ड-हिटिंग बल्लेबाज डेविड मिलर ने अपनी ODI वापसी, कोच शुक्रि कॉनराड के साथ बातचीत और वर्ल्ड कप 2027 में खेलने की उम्मीदों पर खुलकर बात की है। भारतीय टीम के खिलाफ टी20 सीरीज से पहले मिलर का यह बयान चर्चा में है। मिलर ने बताया कि उन्होंने अब तक हेड कोच शुक्रि कॉनराड के साथ ODI कमबैक पर विस्तृत बातचीत नहीं की है, लेकिन अब वह इस प्रक्रिया को शुरू करना चाहते हैं। उन्होंने कहा, 'मैंने अभी तक शुक्रि से ज्यादा बातचीत नहीं की है, लेकिन अब जब मैं टीम के साथ हूं, तो ये बातचीत शुरू होगी। वर्ल्ड कप 2027 करीब है और मैं अपने अनुभव से योगदान दे सकता हूं।' उन्होंने कहा कि टीम में कई नए खिलाड़ी आए हैं और चयन को लेकर कोई गारंटी नहीं होती, लेकिन वह अपनी भूमिका को लेकर स्पष्ट बातचीत करना चाहते हैं। 36 वर्षीय मिलर ने साफ कहा कि वह घरेलू धरती पर होने वाले ODI वर्ल्ड कप 2027 में खेलना चाहते हैं। उन्होंने कहा, 'चयन की कोई गारंटी नहीं होती, लेकिन आने वाले महीनों में बातचीत आगे बढ़ेगी और देखा जाएगा कि चीजें कहां जा रही हैं। ' मिलर की पिछली ODI पारी शानदार रही थी, जहां उन्होंने न्यूज़ीलैंड के खिलाफ 67 गेंदों पर नाबाद 100 लगाया था। इंजरी और नए खिलाड़ियों के आने से वह टीम से बाहर रहे, लेकिन अब वह अपनी फिटनेस पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं।

6ठे पैरा नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में काशी की सुमेधा पाठक का शानदार प्रदर्शन, कांस्य पदक जीतकर बढ़ाया मान

एजेंसी

नई दिल्ली/वाराणसी। काशी की बेटी सुमेधा पाठक ने एक बार फिर अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन से पूरे वाराणसी का गौरव बढ़ाया है। दिल्ली स्थित डॉ. करणी सिंह शूटिंग रेंज में आयोजित 6th पैरा नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में सुमेधा ने लगातार दूसरा पदक जीतते हुए नई उपलब्धि हासिल की।

मिक्स टीम इवेंट में रजत पदकः मिक्स इवेंट में उत्तर प्रदेश की जोड़ी सुमेधा पाठक और आकाश ने शानदार प्रदर्शन करते हुए रजत पदक जीता। इस स्पर्धा का स्वर्ण (गोल्ड) और कांस्य दोनों ही पदक राजस्थान की टीमों ने हासिल किए। सुमेधा ने कहा कि यह उपलब्धि बाबा विश्वनाथ जी के आशीर्वाद और काशीवासियों के समर्थन से संभव हुई है।

व्यक्तिगत स्पर्धा में कांस्य पदक

इससे पहले व्यक्तिगत शूटिंग स्पर्धा में भी सुमेधा ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए कांस्य पदक जीता था।

स्वर्ण पदकः सृष्टि अरोड़ा (राजस्थान)
रजत पदकः भक्ति शर्मा (दिल्ली)
क्वालिफिकेशन स्कोर
भक्ति शर्मा – 568 अंक
सुमेधा पाठक – 565 अंक
सृष्टि अरोड़ा – 559 अंक

इन शानदार अंकों के साथ सुमेधा ने एक बार फिर अपने कौशल को सिद्ध किया और काशी का परचम राष्ट्रीय मंच पर लहराया।

मुरादाबाद के कुणाल अरोड़ा ने नेशनल पैरा रैंकिंग टेबल टेनिस चैंपियनशिप में जीता स्वर्ण पदक

एजेंसी

मुरादाबाद। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद निवासी कुणाल अरोड़ा ने गुजरात में हुई यूटीटी सेकंड नेशनल पैरा रैंकिंग टेबल टेनिस चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतकर पीतल नगरी का नाम रोशन किया है।

कुणाल अरोड़ा के पिता यशपाल अरोड़ा ने बताया कि 2 से 4 दिसंबर के बीच गुजरात में यूटीटी सेकंड नेशनल पैरा रैंकिंग टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2025-26 हुई थी। इसमें कुणाल ने अपनी मेन्स केटेगरी 8 में खेलते हुए सिंगल के ग्रुप मैच में सबसे पहले टंडेल (गुजरात) को एक तरफा मुकाबले में 3-0 के स्कोर से हराया । ग्रुप के दूसरे मैच में चंदर परकश (हरियाणा) को भी 3-0 के स्कोर से हराने के बाद अपने ग्रुप का प्री क्वार्टर क्लियर करते हुए क्वार्टर फाइनल में विजय (तमिलनाडू) को भी 3-0 के स्कोर से पराजित करते हुए सेमी फाइनल में स्थान बनाया। कुणाल अरोड़ा ने सेमीफाइनल मैच में गजानन परमार (महाराष्ट्र) को हरा कर जीत हासिल करते हुए फाइनल में स्थान बनाया।

फाइनल मैच में कुणाल अरोड़ा का मुकाबला डॉ अजय (कर्नाटक) के खिलाड़ी से हुआ जिसमें कुणाल ने एक तरफा मुकाबले में 3-0 से हराकर स्वर्ण पदक जीता। कुणाल अरोड़ा ने स्वर्ण पदक हासिल करने के बाद अपनी केटेगरी में इंडिया में नंबर एक खिलाड़ी भी बनने का रिकॉर्ड कायम रखा।

परिवार एवं अपने कोच को दिया श्रेय

कुणाल अरोड़ा ने अपनी जीत का श्रेय हमेशा की तरह अपने परिवार एवं कोच को दिया। 32 राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय पदक जीत चुके हैं कुणाल अरोड़ा पूर्व में भी कुणाल अरोड़ा कई बार नेशनल रैंकिंग चैंपियनशिप का फाइनल का ख़िताब जीतकर नंबर एक पर रह चुके है । कुणाल अरोड़ा के अब तक राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय 32 पदक हो चुके है । कुणाल के माता पिता यशपाल अरोड़ा एवं सोनिया अरोड़ा यही आशीर्वाद देते है इसी तरह अपने शहर और देश का नाम रोशन करता रहे।

मोनाल कप में रॉयल स्ट्राइकर्स और सचिवालय ए ने अपने-अपने मैच जीते

एजेंसी

देहरादून। सचिवालय रॉयल स्ट्राइकर्स और सचिवालय ए की टीम ने मोनाल कप 2025 में खेले गए अपने-अपने मुकाबलों में जीत दर्ज की। यहां महाराणा प्रताप क्रिकेट ग्राउंड में हुए पहले मैच में रॉयल स्ट्राइकर्स ने सचिवालय बुल्स को, जबकि दूसरे मैच में सचिवालय ए ने सचिवालय पैंथर्स को मात दी। दोनों मैचों में खिलाड़ियों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया।

पहला मैच सचिवालय रॉयल स्ट्राइकर्स और बुल्स के बीच खेला गया। रॉयल स्ट्राइकर्स की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवरों में 03 विकेट पर 191 रनों का बड़ा स्कोर बनाया। टीम के बल्लेबाज पुष्पेंद्र लटवाल ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए 119 रन की शतकीय पारी खेली। बुल्स के खिलाड़ी सिकंदर चौहान ने 02 विकेट लिए। लक्ष्य का पीछा करने उतरी सचिवालय बुल्स की टीम 175 रनों पर ऑल आउट हो गई। टीम के लिए नरेंद्र सिंह ने सबसे ज्यादा 51 रन बनाए। स्ट्राइकर्स की ओर से नीरज गिरी ने 03 विकेट लिए। सचिवालय रॉयल स्ट्राइकर्स ने यह मैच 16 रन से जीत लिया। पुष्पेंद्र लटवाल को मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार दिया गया। दिन का दूसरा मैच सचिवालय ए एवं सचिवालय पैंथर्स के बीच खेला गया। पैंथर्स की टीम ने पहले खेलते हुए 20 ओवरों में 154 रन बनाए। टीम के लिए सौरभ उनियाल ने 46 रन बनाए। सचिवालय ए की ओर से टीएच खान ने 04 विकेट और

टिकराज ने 03 विकेट लिए। लक्ष्य का पीछा करने उतरी सचिवालय ए की टीम ने 03 विकेट खोकर मैच 18 ओवरों में जीत लिया। टीएच खान ने 67, सागर कुमार ने 69 रन बनाए। इस तरह सचिवालय ए ने यह मैच 07 विकेट से जीत लिया। टीएच खान को मैन ऑफ द मैच चुना गया।

वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे टेस्ट से बाहर हुए टॉम ब्लंडेल, मिचेल हे का डेब्यू तय

एजेंसी

वेलिंगटन। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम को वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे टेस्ट से पहले एक और बड़ा झटका लगा है। विकेटकीपर-बल्लेबाज़ टॉम ब्लंडेल हैमस्ट्रिंग चोट के कारण दूसरे टेस्ट से बाहर हो गए हैं। ब्लंडेल को यह चोट पिछले हफ्ते क्राइस्टचर्च में खेले गए पहले टेस्ट के दौरान बल्लेबाजी करते समय लगी थी। ब्लंडेल के बाहर होने के बाद 25 वर्षीय विकेटकीपर-बल्लेबाज़ मिचेल हे का टेस्ट डेब्यू तय माना जा रहा है। हे बुधवार (10 दिसंबर) से बेसिन रिजर्व में शुरू होने वाले दूसरे टेस्ट में न्यूजीलैंड की ओर से पहली बार टेस्ट क्रिकेट में उतरेंगे।

इससे पहले न्यूजीलैंड को एक साथ तीन और खिलाड़ियों के चोटिल होने का सामना करना पड़ा था। तेज़ गेंदबाज़ मैट हेनरी (काफ इंजरी), नाथन स्मिथ (साइड इंजरी) और ऑलराउंडर मिचेल सेंटनर (ग्रोइन इंजरी) सीरीज के बाकी मैचों से बाहर हो चुके हैं। उनके स्थान पर न्यूजीलैंड क्रिकेट ने ऑलराउंडर

क्रिस्टियन क्लार्क और तेज़ गेंदबाज़ माइकल रे को टीम में शामिल किया है। मिचेल हे अब तक न्यूजीलैंड के लिए व्हाइट-बॉल क्रिकेट में 19 अंतरराष्ट्रीय मैच खेल चुके हैं, जिसमें 12 टी20 और 7 वनडे शामिल हैं। फर्स्ट क्लास क्रिकेट में कैंटरबरी के लिए खेले गए 29 मैचों में उन्होंने 48.58 की शानदार औसत से 1895 रन बनाए हैं। इस दौरान उनके नाम 17 अर्धशतक और 146 रन का एक शतक भी दर्ज है। उधर, काइल जैमीसन रेड-बॉल क्रिकेट में वापसी की योजना के तहत टीम के सपोर्ट स्टाफ के साथ काम कर रहे हैं और हाल ही में उन्होंने प्लंकेट शील्ड में कैंटरबरी के लिए सेंट्रल स्टैग्स के खिलाफ मुकाबला खेला था। वहीं, ग्रोइन स्ट्रेन से उबर चुके ग्लेन फिलिप्स ने ओटागो के लिए प्रतियोगिता के शुरुआती दो मुकाबलों में 130 रन बनाए और 9 विकेट झटके। फिलिप्स को दूसरे टेस्ट के लिए चुनी गई 14 सदस्यीय टीम में शामिल किया गया है। मिचेल हे और नए गेंदबाज़ों को लेकर हेड कोच रॉब वॉल्टर ने एक बयान में कहा, 'मिच एक युवा खिलाड़ी हैं जिन्होंने पहले ही व्हाइट-बॉल क्रिकेट में अच्छी भूमिका निभाई है। कैंटरबरी के लिए उनका फर्स्ट क्लास रिकॉर्ड भी बेहतरीन रहा है। टेस्ट टीम में उनका आना उनके करियर का खास पल है और हम उन्हें खेलते देखने को लेकर काफी उत्साहित हैं। ' क्रिस्टियन क्लार्क और माइकल रे पर बात करते हुए वॉल्टर ने कहा, 'दोनों खिलाड़ी लंबे समय से हमारी नजर में हैं और घरेलू क्रिकेट में लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं।

साई में करीब 1100 से ज्यादा पद खाली, यौन उत्पीड़न शिकायतों का कोई समेकित डेटाबेस नहीं: खेल मंत्री

एजेंसी

नई दिल्ली। केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने स्वीकार किया कि भारतीय खेल प्राधिकरण (साई) में 1,100 से अधिक पद लंबे समय से खाली पड़े हैं। लोकसभा में सांसद अदूर प्रकाश के एक प्रश्न के उत्तर में मांडविया ने बताया, 'साई में कुल 1,191 पद रिक्त हैं। इनमें से कुछ पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। ' इससे पहले अगस्त में आई संसदीय स्थायी समिति (खेल) की रिपोर्ट में कहा गया था कि साई के स्वीकृत पदों में से करीब 45 प्रतिशत खाली हैं। समिति ने साई को 'गंभीर रूप से कम संसाधनों और स्टाफ की कमी से जूझ रहा संगठन' बताया था। समिति की रिपोर्ट में कहा गया कि इन कमियों को ठेके पर नियुक्तियों के ज़रिये संभालना केवल एक अस्थायी (एडहॉक) व्यवस्था हो सकती है। रिपोर्ट में स्टाफ की भारी कमी और कम फंडिंग पर 'गंभीर चिंता' जताई गई थी। इस मुद्दे पर खेल सचिव और साई के प्रतिनिधियों की राय 6 जून को हुई बैठक में भी सुनी गई थी। हालांकि, समिति ने रिक्त पदों को भरने के लिए शुरू की गई भर्ती प्रक्रिया की सराहना की, लेकिन छह महीने के भीतर इसे पूरा करने और मंत्रालय से कार्रवाई रिपोर्ट सौंपने को कहा। वित्त वर्ष के लिए युवा मामले एवं खेल मंत्रालय को 3,794 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है, जिसमें से 830 करोड़ रुपये साई के लिए निर्धारित किए गए हैं। इस पर मंत्री ने लोकसभा में कहा, 'साई को बजट आवंटन उनके द्वारा दिए गए प्रस्तावों के आधार पर किया जाता है। वर्ष के दौरान यदि अतिरिक्त आवश्यकता होती है, तो संशोधित अनुमान चरण में इसकी समीक्षा कर पूरक अनुदान के माध्यम से विचार किया जाता है। 'एक अन्य प्रश्न के उत्तर में मनसुख मांडविया ने माना कि खिलाड़ियों द्वारा दर्ज कराई गई यौन उत्पीड़न शिकायतों का कोई समेकित या समर्पित डेटाबेस सरकार के पास नहीं है।

सरकार का फोकस युवाओं के कौशल, नेतृत्व और मानसिक स्वास्थ्य पर : मांडविया

एजेंसी

नई दिल्ली। केंद्र सरकार युवाओं के कौशल विकास, नेतृत्व क्षमता और मानसिक स्वास्थ्य को मजबूत करने के लिए व्यापक कार्यक्रमों और योजनाओं पर काम कर रही है। यह जानकारी युवा मामले और खेल मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने लोकसभा में एक लिखित जवाब में दी। मंत्री ने बताया कि युवा कार्यक्रमों का क्रियान्वयन 'मेरा युवा भारत' और 'नेशनल सर्विस स्कीम' के माध्यम से किया जा रहा है। ये दोनों प्लेटफॉर्म युवाओं को लीडरशिप डेवलपमेंट, स्किल एन्हांसमेंट, नागरिक सहभागिता और अनुभवात्मक सीख के अवसर प्रदान करते हैं।

माई भारत के प्रमुख कार्यक्रम

वित्त वर्ष 2023-24 और 2024-25 के दौरान कई गतिविधियां आयोजित की गईं, जिनमें विकसित भारत एमबेस्डर - युवा कनेक्ट, विकसित भारतञ्ज2047 डिक्लेमेशन कॉन्टेस्ट, नेबरहुड यूथ पार्लियामेंट, और विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग / यूथ पार्लियामेंट प्रमुख हैं। माई भारत पोर्टल के माध्यम से 18-29 आयु वर्ग के युवाओं को पुलिस, डाक सेवा, जन औषधि केंद्र और साइबर सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में अनुभवात्मक प्रशिक्षण (ईएलपी) उपलब्ध कराया जा रहा है। 2025-26 की वार्षिक कार्य योजना के तहत वोकशनल ट्रेनिंग युवाओं के सॉफ्ट स्किल्स और जीवन कौशल को बढ़ाने पर केंद्रित है। राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान (आरजीएनआईवाईडी भी नेतृत्व, लाइफ स्किल्स और क्षमता निर्माण पर प्रशिक्षण आयोजित करता है।

रोजगार व कौशल विकास के लिए राष्ट्रीय योजनाएं

सरकार पीएमईजीपी, एमजीएनआरईजीएस, डीडीयू-जीकेवाई, आरएसईटीआई, डीएवाई-एनयूएलएम और पीएमएमवाई जैसी योजनाओं के माध्यम से रोजगार सृजन और कौशल विकास को बढ़ावा दे रही है। स्किल इंडिया मिशन के तहत कौशल, री-स्किल और अप-स्किल प्रशिक्षण दिया जा रहा है। बजट 2024-25 में घोषित प्रधानमंत्री पैकेज में 5 वर्ष में 4.1 करोड़ युवाओं को रोजगार और कौशल अवसर उपलब्ध कराने का लक्ष्य है। नेशनल करियर सर्विस (एनसीएस) पोर्टल जॉब मैचिंग, करियर काउंसलिंग और प्रशिक्षण संबंधी जानकारी प्रदान करता है, जबकि एसपायर योजना ग्रामीण युवाओं और महिलाओं के लिए कृषि क्षेत्र में रोजगार को बढ़ावा देती है। एनएसएस और माई भारत मानसिक स्वास्थ्य और युवा कल्याण के लिए योग दिवस, खेल प्रतियोगिताएं, ध्यान सत्र और स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करते हैं एनएसएस आयुष्मान भारत और टेली-मानस जैसे कार्यक्रमों की भी जागरूकता फैलाता है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में पूरे देश में ड्रग एडिक्शन और सब्सटेंस एब्यूज़ पर जागरूकता अभियान चलाया गया।

इफआई चिल्ड्रन क्लासिक सिल्वर में टीम इंडिया ने जीता स्वर्ण पदक

एजेंसी

मुंबई। अंतरराष्ट्रीय घुड़सवारी महासंघ (एफईआई) के चिल्ड्रन क्लासिक - सिल्वर टूर में टीम इंडिया ने शानदार प्रदर्शन करते हुए टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक अपने नाम किया। ज़ोन-9 के देशों के सवारों के बीच हुए इस मुकाबले में भारतीय टीम शीर्ष स्थान पर रही। भारतीय टीम में स्टेस्या पांड्या, श्रेष्ठ मंटेना, हर्षवर्धन सिंह गुलिया और पृथ्वीव कृष्णा शामिल थे। सभी खिलाड़ियों ने संतुलित और सटीक राइडिंग का प्रदर्शन करते हुए संयुक्त रूप से टीम को स्वर्ण पदक दिलाया।एमेच्योर राइडर्स क्लब (एआरसी) की सवार स्टेस्या पांड्या ने अपने घोड़े कूगर पर सवारी करते हुए टीम की जीत में अहम योगदान दिया। उनका प्रदर्शन नियंत्रित, तकनीकी रूप से मजबूत और आत्मविश्वास से भरा रहा। इस उपलब्धि के बाद स्टेस्या की एफईआई जंपिंग चिल्ड्रन क्लासिक्स 2025 फाइनल (सिल्वर टूर) की ओवरऑल व्यक्तिगत रैंकिंग में 12वां स्थान हो गया है। एफईआई चिल्ड्रन क्लासिक को युवा सवारों के विकास के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक महत्वपूर्ण मंच माना जाता है, जहां उन्हें वैश्विक मानकों के अनुरूप शो जंपिंग का अनुभव मिलता है। अपनी उपलब्धि पर प्रतिक्रिया देते हुए स्टेस्या पांड्या ने कहा, 'यह खिताब जीतकर मैं बेहद खुश हूं, लेकिन इससे भी अधिक खुशी इस बात की है कि भारत को वैश्विक मंच पर पहचान मिल रही है। इक्वेस्ट्रियन खेल तेजी से बढ़ रहा है और भारतीय सवारों को अंतरराष्ट्रीय सफलता के लगातार अवसर मिल रहे हैं। एआरसी के विश्वस्तरीय ऑल-वेदर एरीना में प्रशिक्षण का अवसर मेरे लिए बेहद लाभकारी रहा है, जिसने मुझे देश और विदेश में उच्च स्तर पर प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार किया। ' स्टेस्या का प्रदर्शन एक बार फिर यह दर्शाता है कि एआरसी राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर की प्रतिभाओं को तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। 1942 में स्थापित एमेच्योर राइडर्स क्लब (एआरसी), मुंबई के महालक्ष्मी रेसकोर्स स्थित भारत के सबसे पुराने और बड़े निजी नागरिक घुड़सवारी क्लबों में से एक है। क्लब में पोलो, शो जंपिंग और ड्रेसेज सहित घुड़सवारी खेलों की सभी विधाओं में पेशेवर प्रशिक्षण दिया जाता है। एआरसी में करीब 150 घोड़े हैं और यह पिछले 75 वर्षों से अधिक समय से इक्वेस्ट्रियन खेल के विकास में अग्रणी भूमिका निभा रहा है।

अनीश गिरी ग्लोबल चेस लीग में करेंगे अल्पाइन एसजी पाइपर्स का प्रतिनिधित्व

एजेंसी

नई दिल्ली। मुंबई के प्रतिष्ठित रॉयल ओपेरा हाउस में 13 से 24 दिसंबर तक पहली बार आयोजित होने जा रही ग्लोबल चेस लीग में अल्पाइन एसजी पाइपर्स सीज़न तीन के लिए पूरी मजबूती के साथ उतरने को तैयार है। यह टीम अनुभवी अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ियों और उभरती युवा प्रतिभाओं के बेहतरीन संतुलन के साथ खिताब की दावेदारी पेश करेगी। इस सीज़न टीम के प्रमुख अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ियों में 31 वर्षीय डच ग्रैंडमास्टर अनीश गिरी शामिल हैं, जिन्हें विश्व शतरंज के सबसे सम्मानित और रणनीतिक दिमागों में गिना जाता है। एक बार फिर अल्पाइन एसजी पाइपर्स का प्रतिनिधित्व करते हुए भारत लौटने पर उत्साह व्यक्त करते हुए अनीश गिरी ने कहा, 'हाल के वर्षों में मैं कई बार भारत आया हूं, विशेषकर तब से जब देश के विभिन्न शहरों में लगातार प्रतिष्ठित शतरंज प्रतियोगिताओं का आयोजन हो रहा है। भारत में खेलते समय हमेशा अपनापन और गर्मजोशी का अनुभव होता है। यहां के दर्शकों का खेल के प्रति जुनून खिलाड़ियों के लिए इसे और भी विशेष बना देता है। ' वर्तमान में क्लासिकल प्रारूप में विश्व रैंकिंग में आठवें स्थान पर काबिज अनीश गिरी के लिए ग्लोबल चेस लीग का मंच नया नहीं है। लीग के रैपिड प्रारूप की विशेषताओं पर बात करते हुए उन्होंने कहा, 'रैपिड शतरंज में गहरी ओपनिंग तैयारी का महत्व क्लासिकल प्रारूप की तुलना में कम होता है।

सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी: ग्रुप स्टेज रोमांचक मोड़ पर, सुपर लीग के 4 स्थानों के लिए 10 टीमों में रेस

एजेंसी

पुणे। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के ग्रुप चरण का अंतिम दौर खेला जाएगा और इसी के साथ सुपर लीग के लिए बची चार जगहों की जंग और तेज हो गई है। कुल दस टीमें अब भी क्वालीफाई करने की दौड़ में बनी हुई हैं।

मुंबई, आंध्र, झारखंड और राजस्थान ने पहले ही बनाया सुपर लीग में स्थान

डिफेंडिंग चैंपियन मुंबई और आंध्र (ग्रुप ए), साथ ही झारखंड और राजस्थान (ग्रुप डी) ने सुपर लीग चरण में प्रवेश कर लिया है। आठ टीमों का यह दौर शुक्रवार से पुणे में शुरू होगा।

ग्रुप बी- हैदराबाद मजबूत, छह टीमें अब भी दावेदार

कोलकाता में खेले जा रहे ग्रुप-बी में मुकाबला सबसे दिलचस्प है। ग्रुप में छह टीमें शीर्ष दो स्थानों के लिए जूझ रही हैं। ग्रुप में शीर्ष पर चल रही हैदराबाद की टीम पांच जीत के साथ क्वालीफाई करने के बेहद करीब है। उसका सामना कमजोर प्रदर्शन करने वाली चंडीगढ़ टीम से होगा, जिसने छह में से केवल दो मैच जीते हैं।

रजत पाटीदार की कप्तानी वाली मध्य प्रदेश और गोवा दोनों के चार-चार जीत क्रमशः जम्मू-कश्मीर और महाराष्ट्र के खिलाफ जीत हासिल कर सुपर लीग में जगह पक्की करने की कोशिश करेंगे।

उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और जम्मू-कश्मीर (तीन जीत) के पास क्वालीफाई करने की उम्मीद तो है, लेकिन वह बहुत कम है। बिहार छह मैचों में बिना जीत के एलिट डिविजन में सबसे नीचे है और उसे सर्विसेज, हिमाचल प्रदेश और त्रिपुरा की तरह ही

रेलिगेशन से बचने का दबाव झेलना होगा।

ग्रुप सी - अंतिम मैच बना नॉकआउट जैसा

हैदराबाद में खेले जा रहे ग्रुप-सी में स्थिति साफ है। पंजाब, गुजरात, हरियाणा और बंगाल सभी चार-चार जीत के साथ बराबरी पर हैं। हरियाणा बनाम बंगाल और पंजाब बनाम गुजरात–ये दोनों मुकाबले शीर्ष दो स्थानों का फैसला करेंगे। हालांकि, टीम इंडिया के उभरते धाकड़ ओपनर अभिषेक शर्मा के उपलब्ध न होने की संभावना पंजाब के लिए बड़ी चिंता है।

ग्रुप ए - मुंबई और आंध्र के लिए सिर्फ शीर्ष स्थान की जंग

लखनऊ के एकाना अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम में मुंबई का सामना विदर्भ से और आंध्र का मुकाबला ओडिशा से होगा। दोनों टीमें पहले ही सुपर लीग के लिए क्वालीफाई कर चुकी हैं और अब मुकाबला केवल ग्रुप में शीर्ष पर रहने का है। केरल, जिसने आंध्र के खिलाफ महत्वपूर्ण मैच में निराशाजनक बल्लेबाजी की थी, अब अंतिम मैच जीतकर सम्मानजनक विदाई चाहेगा। टीम के कप्तान संजू सैमसन राष्ट्रीय टीम के लिए रवाना हो चुके हैं।

ग्रुप डी - झारखंड बनाम राजस्थान, दो अजेय दिग्गजों की टक्कर

इशान किशन की अगुवाई वाली झारखंड और राजस्थान दोनों अब तक अजेय अहमदाबाद में आमने-सामने होंगे। वहीं तीन बार की चैंपियन तमिलनाडु की हालत खराब है। टीम ग्रुप में सातवें स्थान पर है और अंतिम मैच में उसका लक्ष्य सिर्फ आखिरी स्थान से बचना होगा। यह याद दिलाता है कि टी20 क्रिकेट में लगातार प्रदर्शन कितना चुनौतीपूर्ण है।

रुपया 10 पैसे कमजोर

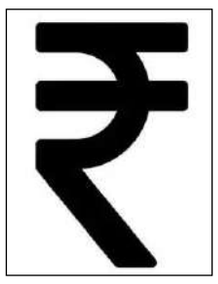

एजेंसी

मुंबई। अंतरबैंकिंग मुद्रा बाजार में रुपया 9.75 पैसे टूट गया और कारोबार की समाप्ति पर एक डॉलर 90.05 रुपये का बोला गया। भारतीय मुद्रा पिछले कारोबारी दिवस पर 5.75 पैसे गिरकर 89.9525 रुपये प्रति डॉलर पर रही थी। रुपया आज 11.75 पैसे फिसलकर 90.07 रुपये प्रति डॉलर पर खुला। और टूटता हुआ एक समय यह 90.26 रुपये प्रति डॉलर तक कमजोर हो गया था। बाद में काफी हद तक वापसी करते हुए 90.05 रुपये प्रति डॉलर पर बंद हुआ। घरेलू शेयर बाजारों की गिरावट से भी रुपये पर दबाव रहा।

आरबीआई ने जारी किया डॉलर/रुपया स्वैप बोली का विवरण

मुंबई। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने पिछले सप्ताह घोषित डॉलर/रुपया स्वैप बोली का विवरण जारी किया। केंद्रीय बैंक ने बताया कि बोली 16 दिसंबर को सुबह 10.30 से 11.30 तक लगायी जा सकेगी। इसके तहत वाणिज्यिक बैंक आरबीआई को डॉलर बेचेंगे और तीन साल बाद एक प्रीमियम दर पर वह उन्हें वापस कर दिया जायेगा। जो बैंक बाद में जितना ज्यादा प्रीमियम देने की पेशकश करेगा उसकी बोली को पहले शामिल किया जायेगा। पहले चरण में 18 दिसंबर 2025 को वाणिज्यिक बैंक आरबीआई के नेस्ट्रो खाते में डॉलर देंगे। बदले में आरबीआई उनके चालू खाते में रुपया जमा करा देगा। दूसरे चरण के तहत 18 दिसंबर 2026 वे प्रीमियम दर पर पैसे देकर डॉलर वापस लेंगे। केंद्रीय बैंक ने कुल पांच अरब डॉलर के स्वैप का प्रस्ताव किया है। वाणिज्यिक बैंक कम से कम एक करोड़ डॉलर के लिए बोली लगायेंगे। उससे ऊपर 10 लाख के गुणक में मात्रा बढ़ाने का विकल्प होगा।

चावल, चीनी, दालें मजबूत; गेहूं नरम; खाद्य तेलों में घट-बढ़

नई दिल्ली। घरेलू थोक जिंस बाजारों में चावल के औसत भाव बढ़ गये। चावल के अलावा चीनी और दालों में भी तेजी रही जबकि गेहूं टूट गया। वहीं, खाद्य तेलों में उतार-चढ़ाव देखा गया। औसत दर्जे के चावल की औसत कीमत 127 रुपये बढ़कर 3,858.67 रुपये प्रति क्विंटल पर पहुंच गयी। गेहूं चार रुपये सस्ता हुआ और 2,858.82 रुपये प्रति क्विंटल के भाव बिका। आटा 23 रुपये प्रति क्विंटल गिर गया। दाल-दलहनों में बढ़त रही। तुअर दाल 205 रुपये प्रति क्विंटल महंगी हो गयी। मसूर दाल की कीमत 167 रुपये और चना दाल की 133 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ी। मूंग दाल में 115 रुपये और उड़द दाल में 36 रुपये प्रति क्विंटल की तेजी रही।विदेशों में बुरसा मलेशिया डेरिवेटिव एक्सचेंज में पाम ऑयल का फरवरी वायदा 58 रिंगिट फिसलकर 4,094 रिंगिट प्रति टन रह गया। वहीं, जनवरी का अमेरिकी सोया तेल वायदा भी 0.72 प्रतिशत गिरकर में 51.32 डॉलर के भाव बोला गया। स्थानीय बाजारों में पाम ऑयल औसतन 76 रुपये प्रति क्विंटल सस्ता हुआ। सोया तेल 71 रुपये और सूरजमुखी तेल 66 रुपये प्रति क्विंटल की गिरावट में रहा। वनस्पति 112 रुपये और मूंगफली तेल 70 रुपये महंगा हुआ। सरसों तेल की औसत 31 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ गयी। मीठे के बाजार में आज गुड़ की औसत कीमत 107 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ गयी। चीनी भी 16 रुपये प्रति क्विंटल महंगी हुई।

यात्री वाहनों की खुदरा बिक्री नवंबर में 19.7 प्रतिशत बढ़ी, दुपहिया में तीन फीसदी की गिरावट

नई दिल्ली। देश में यात्री वाहनों की खुदरा बिक्री नवंबर में सालाना 19.71 प्रतिशत बढ़कर 3,94,152 पर पहुंच गयी जबकि दुपहिया वाहनों की बिक्री 25,46,184 इकाई रही जो एक साल पहले के मुकाबले 3.10 प्रतिशत कम है। यात्री वाहनों में कारों, उपयोगी वाहनों और वैनों को शामिल किया जाता है। वाहन डीलरों के संगठन फाडा ने खुदरा बिक्री के आंकड़े जारी करते हुए बताया कि पिछले साल दिवाली और धनतेरस अक्टूबर से अंत में था और इस अवसर पर की गयी खरीदारी का काफी बड़े हिस्से का पंजीकरण नवंबर में हुआ था। पिछले साल के मजबूत आंकड़ों के परिप्रेक्ष्य में इस साल यात्री वाहनों की बिक्री में वृद्धि काफी बड़ी है क्योंकि यह त्योहारी मांग के बाद के महीने में आयी है। फाडा के अध्यक्ष सी.एस. विग्नेश्वर ने कहा कि ये आंकड़े ग्राहकों के विश्वास और देश के वाहन बाजार की ढांचागत मजबूती का प्रमाण हैं। साथ ही वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) की दरों में की गयी कटौती का भी असर रहा। नवंबर में वाहनों की कुल खुदरा बिक्री 2.14 प्रतिशत बढ़कर 33,00,832 इकाई पर पहुंच गयी। तिपहिया वाहनों की बिक्री 23.67 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 1,33,951 इकाई और ट्रैक्टरों की 56.55 प्रतिशत बढ़कर 1,26,033 इकाई हो गयी। वाणिज्यिक वाहनों की बिक्री 19.94 प्रतिशत बढ़ी जबकि वाणिज्यिक इक्विपमेंट्स में 16.51 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गयी।

प्रवासी राजस्थानी दिवस : 421 एमओयू से राजस्थान में 1 लाख करोड़ का निवेश, विकास की नई उड़ान

एजेंसी

जयपुर। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान सरकार आगामी 10 दिसंबर को 'प्रवासी राजस्थानी दिवस' (पीआरडी) के दौरान ऊर्जा, कृषि, पर्यटन, शिक्षा और कौशल विकास, स्वास्थ्य, खनन और अन्य प्रमुख क्षेत्रों में 421 एमओयू के माध्यम से 1 लाख करोड़ रुपये के निवेश को धरातल पर लाने जा रही है। उद्योग एवं वाणिज्य आयुक्त सुरेश कुमार ओला ने बताया कि यह मील का पत्थर राजस्थान के मज़बूत निवेश ट्रैक रिकॉर्ड पर आधारित है, जिसमें 7 लाख करोड़ रुपये के एमओयू पहले ही पीआरडी– 2025 से पहले ही ज़मीनी स्तर पर काम शुरू कर चुके हैं, जो निवेश और इनोवेशन के लिए एक प्रमुख डेस्टिनेशन के रूप में राज्य की प्रतिष्ठा को और मज़बूत करता है। ओला ने बताया कि राजस्थान निर्णायक क्रियान्वयन के माध्यम से विकास के एक नए युग में प्रवेश कर रहा है। प्रवासी राजस्थानी दिवस– 2025 के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में 1 लाख करोड़ रुपये के निवेश का प्रतिनिधित्व करने वाले 421 एमओयू की शुरुआत, इरादे को प्रभाव में बदलने की हमारी प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है। हमारी प्राथमिकता इन एमओयू के पीछे के इरादों को ज़मीनी स्तर पर वास्तविक परियोजनाओं में बदलना, रोज़गार पैदा करना और ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर और सेवाएं प्रदान करना है जो दैनिक जीवन को बेहतर बनाएं। पीआरडी– 2025 से पहले ही 7 लाख करोड़ रुपये के एमओयू की शुरुआत हो चुकी है, हम सिर्फ़ समझौते साइन नहीं कर रहे हैं, हम परिणाम दे रहे हैं। ओला ने वैश्विक राजस्थानी समुदाय और निवेशकों को इस यात्रा का हिस्सा बनने और राजस्थान के भविष्य को फिर से आकार देने में हमारी मदद करने के लिए आमंत्रित किया है। इस गति को और तेज़ करने के लिए राज्य 13 दूरदर्शी नीतियां भी पेश कर रहा है, जिन्हें औद्योगिक विकास, तकनीकी प्रगति और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इनमें औद्योगिक नीति, एनआरआर नीति, राजस्थान व्यापार संवर्धन नीति, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग नीति, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर (जीसीसी) नीति, सेमीकंडक्टर नीति, एयरोस्पेस और रक्षा नीति, नई पर्यटन नीति, ग्रीन ग्रोथ क्रेडिट नीति, कृषि और खाद्य प्रसंस्करण नीति, आईटी आउटसोर्सिंग, वन और कृषि-वानिकी नीति, खेल नीति और वाहन स्क्रैपेज नीति शामिल हैं। ये सभी पहलें मिलकर राजस्थान को इनोवेशन, ग्लोबल ट्रेड और ग्रीन ग्रोथ के हब के रूप में स्थापित करने का लक्ष्य रखती हैं, जिससे विभिन्न क्षेत्रों में निवेशकों और उद्यमियों के लिए नए अवसर पैदा होंगे।

बीएसई ने इंडिगो से मांगा स्पष्टीकरण, शेयर आठ प्रतिशत लुढ़का

एजेंसी

मुंबई। शेयर बाजार बीएसई ने विमानन नियामक डीजीसीए द्वारा विमान सेवा कंपनी इंडिगो को कारण बताओ नोटिस की खबरों के संबंध में एयरलाइंस से स्पष्टीकरण मांगा है। बीएसई ने बताया कि एक वेबसाइट की खबर का लिंक देते हुए कहा कि इसमें कहा गया है कि नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने इंडिगो के मुख्य कार्यकारी अधिकारी पीटर एलबर्स को कारण बताओ नोटिस का जवाब देने के लिए और समय दिया है तथा इसमें विफल रहने पर कार्रवाई की चेतावनी दी है। शेयर बाजार ने इस खबर पर एयरलाइंस से जवाब मांगा है। इस बीच, बीएसई में इंडिगो का शेयर आज 444.75 रुपये (8.28 प्रतिशत) गिरकर 4,926.55 रुपये रह गया। कंपनी के शेयर में इस महीने 16.54 प्रतिशत की गिरावट आ चुकी है। नवंबर के अंतिम कारोबारी दिवस पर एयरलाइंस का शेयर 5902.70 रुपये पर बंद हुआ था। इस प्रकार, यह 976.15 रुपये टूट चुका है।

योगी सरकार की आबकारी नीति से निवेश को रफ्तार, रोजगार सृजन के खुले नए आयाम

एजेंसी

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार की पारदर्शी और निवेशोन्मुखी आबकारी नीति ने वर्ष 2025 में प्रदेश की राजस्व प्रणाली को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। एथेनॉल उत्पादन और बिक्री में दर्ज हुई उल्लेखनीय वृद्धि ने न केवल औद्योगिक गतिविधियों को तेज किया है, बल्कि प्रदेश को राष्ट्रीय एथेनॉल उत्पादन के क्षेत्र में भी शीर्ष श्रेणी में स्थापित किया है। उत्पादन में रिकॉर्ड बढ़ोतरी, बिक्री और निवेश प्रस्तावों में तेजी इस बात का संकेत है कि राज्य की अर्थव्यवस्था नए दौर में प्रवेश कर रही है। उत्तर प्रदेश में नवंबर 2025 तक 141.8 करोड़ लीटर एथेनॉल का उत्पादन हुआ, जो अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। योगी आदित्यनाथ सरकार के संरचनात्मक सुधार, तकनीकी अनुकूलता और 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' से शराब, बीयर, वाइन व अल्कोहल आधारित उद्योगों में वृद्धि हुई है। प्रदेश में 105.25 करोड़ लीटर और प्रदेश से बाहर 40.96 करोड़ लीटर एथेनॉल

बिक्री ने उत्तर प्रदेश को एथेनॉल सप्लाई का भरोसेमंद केंद्र बनाया है। उत्तर प्रदेश देश के अग्रणी एथेनॉल उत्पादक प्रदेशों में स्थापित हो चुका है। इससे न केवल उद्योगों को प्रोत्साहन मिला, बल्कि ग्रामीण स्तर पर भी आर्थिक गतिविधियां तेज हुईं।

उत्तर प्रदेश में अल्कोहल आधारित उद्योग के क्षेत्र में बड़े कॉरपोरेट समूहों से लेकर मध्यम सेक्टर उद्योगों तक के निवेशक यूपी में अपने परियोजनाओं को विस्तार दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश के आबकारी आयुक्त डॉ. आदर्श सिंह ने बताया कि इंवेस्ट यूपी के अंतर्गत अब तक 125 समझौते साइन हुए हैं, जिसके तहत 3,07,35 करोड़ रुपए के निवेश की प्रक्रिया चल रही है। वहीं 43 रेडी-टू-लॉन्च प्रोजेक्ट हैं जिनके लिए जमीन आवंटित हो चुकी है। इसके माध्यम से 6898.88 करोड़ रुपए के निवेश की प्रक्रिया चल रही है। इनवेस्ट यूपी के तहत वर्तमान में 19 प्रोजेक्ट संचालित हैं इसमें 2900 करोड़ से ज्यादा का निवेश हो चुका है। इन परियोजनाओं ने 4800 से अधिक रोजगार भी सृजित किए हैं। गैर एमओयू के तहत 28 प्रोजेक्ट संचालित हैं जिसमे 2752 करोड़ रुपए का निवेश हुआ है।

एयर इंडिया के सीईओ ने अपने स्टाफ से संकट में फंसे इंडिगो यात्रियों की मदद करने को कहा

एजेंसी

नई दिल्ली। देश की सबसे बड़ी विमानन कंपनी इंडिगो की फ्लाइट्स में बड़े पैमाने पर रुकावटों, यात्रियों की परेशानी और एविएशन इकोसिस्टम पर इसके चलते पड़े दबाव के बीच एयर इंडिया के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) ने अपने स्टाफ से इंडिगो यात्रियों की मदद करने की अपील की है। टाटा की अगुवाई वाले एयर इंडिया के सीईओ कैंपबेल विल्सन ने कर्मचारियों को एक अंदरूनी मैसेज लिखा, जिसमें उनके प्रयासों की तारीफ की और उनसे यात्रियों और इंडस्ट्री के साथियों की मदद करते रहने की अपील की। विल्सन ने एयरलाइंस के कर्मचारियों को लिखे अपने नोट में कहा, 'आप में से कई लोगों के लिए ये कुछ दिन बहुत बिजी रहे हैं, मैं ट्रैवलर्स और कलीग्स को सपोर्ट करने के लिए आप जो कोशिश कर रहे हैं, उसके लिए आपकी बहुत तारीफ करना चाहता हूं। 'उन्होंने अपने मैसेज में इस बात पर ज़ोर दिया कि इस मुश्किल समय में एयर इंडिया के क्रू और ग्राउंड टीमों

के आगे आने की कई कहानियों ने उन्हें बहुत प्रभावित किया है। सीईओ ने अपने कर्मचारियों से कहा कि वे न सिर्फ एयर इंडिया के कस्टमर्स के साथ, बल्कि दूसरी एयरलाइंस के वर्कर्स के साथ भी अच्छा व्यवहार करें। उन्होंने आगे लिखा, 'कृपया हमारी इंडस्ट्री के साथियों के साथ भी थोड़ी दया दिखाएं। चाहे कॉम्पिटिटर हो या सर्विस पार्टनर, हमारी यूनिफॉर्म का रंग कुछ भी हो, हम सभी इंसान हैं और हमारा एक ही मकसद है कि यात्रियों को सुरक्षित उनकी मंजिल तक पहुंचने में मदद करें। ' देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो के यात्रियों को पिछले कुछ दिनों से काफी दिक्कत हो रही है। इंडिगो का संकट आज 7वें दिन भी जारी है, 400 से ज्यादा फ्लाइट कैंसिल हो चुकी हैं। पिछले सात दिन में एयरलाइन की 5,000 से ज्यादा उड़ानें रद्द हो चुकी है। इस पर सरकार ने भी कड़ा रुख दिखाया है।

इंडिगो संकट का देशभर के होटल कारोबार पर पड़ा बुरा असर

एजेंसी

नई दिल्ली। इंडिगो संकट के कारण पिछले एक हफ्ते में देश के प्रमुख शहरों में होटल उद्योग को सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है और मौजूदा अनिश्चितताओं के कारण लोगों में हवाई यात्रा को लेकर भरोसा कम हुआ है। होटल कारोबार से जुड़े लोगों ने इस तरह के विचार व्यक्त किये हैं।

नाइल हॉस्पिटैलिटी ग्रुप के क्लस्टर महाप्रबंधक मनुज बहल ने कहा, 'पिछले एक हफ़्ते में कारोबार को बहुत बड़ा झटका लगा है। होटलों की बुकिंग में 20 प्रतिशत से ज़्यादा की गिरावट आयी है। लोग होटल इसलिये बुक नहीं कर रहे हैं क्योंकि हवाई यात्रा को लेकर उनका भरोसा कम हुआ है।' गौरतलब है कि नाइल हॉस्पिटैलिटी ग्रुप उत्तर भारत में शादी समारोह के लिए एक लोकप्रिय स्थल उदयपुर में हॉवर्ड जॉनसन और रमाडा एनकोर होटल चलाता है। राष्ट्रीय राजधानी के होटलों का हाल भी अलग नहीं है। होटलों में सिर्फ निजी बुकिंग ही रद्द नहीं हो रही, बल्कि कारोबारी समारोह और सम्मेलन रद्द हो गए हो गये हैं, क्योंकि इनमें शामिल होने वाले लोग यात्रा नहीं कर पा रहे हैं। लुटियंस दिल्ली में स्थित ली मेरिडियन की उपाध्यक्ष एवं महाबंधक मीना भाटिया ने कहा, 'हालात को संभालना थोड़ा मुश्किल हो गया है, क्योंकि यह देश में सबसे ज्यादा यात्रा करने वाले समय में हुआ है। ' वहीं, नयी दिल्ली के द सूर्या होटल के उपाध्यक्ष संचालन गिरीश बिंद्रा ने कहा, 'हमें दिक्कतें हुईं क्योंकि जिन मेहमानों को चेक आउट करके जाना था, वे जा नहीं पाए और जिन्होंने कमरे बुक किए थे, वे यात्रा नहीं कर पाए।' उन्होंने कहा कि जैसे ही हवाई टिकटों के दाम बहुत ज़्यादा बढ़ गए, जिन मेहमानों को चेक आउट करना था, उन्होंने कुछ और

दिनों तक वहीं रुकने का फैसला किया। ' उन्होंने कहा, 'हम एयरलाइनों की तरह ही होटल किराये बढ़ा सकते थे, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया।' नयी दिल्ली के ओखला स्थित क्राउन प्लाजा टुडे होटल के महाप्रबंधक रितेश शर्मा ने कहा, 'वित्तीय असर से ज़्यादा, इंडिगो मुद्दे का हमारे व्यवसाय पूर्वानुमान और परिचालन समय-सारिणी पर बुरा असर पड़ा है, क्योंकि बुकिंग और समारोह आखिरी समय पर रद्द हो गए।' उन्होंने बताया, 'कमरों और समारोहों के आखिरी समय पर रद्द होने के मामलों में काफी बढ़ोतरी हुई है।' हालांकि इसका असर दिल्ली के सभी होटलों पर पड़ा, लेकिन इसका असर हर होटल के कारोबार के हिसाब से अलग-अलग पड़ा। नयी दिल्ली के द्वारका स्थित रेडिसन ब्लू होटल के महाप्रबंधक राकेश सेठी ने कहा, ' बैठकें, प्रोत्साहन, सम्मेलन और प्रदर्शनियाँ (एमआईसीई) केंद्रित होटल होने के नाते, हम पर कुछ कमरों के रद्द के मामलों का हल्का असर पड़ा।' उन्होंने बताया कि होटल ने उन मेहमानों के लिए रद्द होने जुड़े सभी चार्ज माफ कर दिए हैं, जिन्होंने फ्लाइट में रुकावटों के कारण अपनी बुकिंग रद्द की थी।

रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर एकीकृत सौर विनिर्माण सुविधा करेगी स्थापित

एजेंसी

नई दिल्ली। उद्योगपति अनिल अंबानी के नेतृत्व वाली रिलायंस समूह की इकाई रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर भारत के सबसे उन्नत, पूर्णतः एकीकृत सौर विनिर्माण परिवेश में से एक की स्थापना करने जा रही है, जिसमें इन्गोट, वेफर्स, सेल और मॉड्यूल शामिल होंगे। रिलायंस समूह ने एक बयान में कहा कि उसकी ब्रांच रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के निवेशकों के समक्ष यह प्रस्ताव पेश की गई है। यह विनिर्माण सुविधा अगली पीढ़ी की प्रौद्योगिकी से लैस होगी, जिसमें इनगॉट्स, वेफर्स, सेल्स और मॉड्यूल शामिल हैं। कंपनी के मुताबिक यह आयात निर्भरता को कम करने और भारत की स्वच्छ ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए एक एकीकृत मंच होगा। ये सुविधा मांग-आपूर्ति के बीच के बड़े अंतर को पाटेगी, क्योंकि भारत को 2030 तक प्रतिवर्ष 55-60 गीगावाट सौर मॉड्यूल की जरूरत होगी, जबकि 'अपस्ट्रीम' क्षमता अब भी काफी कम है। रिलायंस समूह की एक अन्य कंपनी रिलायंस पावर ने अपने निवेशक प्रस्तुतिकरण में बताया कि रिलायंस एनयू एनर्जीज साधारण सौर ऊर्जा से हाइब्रिड एवं ठोस, चौबीसों घंटे (आरटीसी) नवीकरणीय ऊर्जा की ओर बदलाव को बल दे रही है। भारत का स्थापित स्थिर भंडारण आधार वर्तमान में एक गीगावाट से भी कम है, जो 2032 तक बढ़कर 250 गीगावाट हो जाएगा। दरअसल घरेलू विनिर्माण वर्तमान में अपेक्षित मांग का 10 फीसदी से भी कम पूरा कर पाता है।

गिरावट के साथ बंद हुआ घरेलू शेयर बाजार, सेंसेक्स 610 अंक लुढ़का

एजेंसी

नई दिल्ली। लगातार दो दिनों की बढ़त के बाद हफ्ते के पहले कारोबारी दिन शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी में भारी गिरावट दर्ज हुई है। विदेशी निवेशकों की लगातार बिकवाली के बीच निवेशकों ने मुनाफावसूली की। इससे सेंसेक्स 610 अंक लुढ़क गया, जबकि निफ्टी 26,000 के नीचे आ गया। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) का सेंसेक्स 609.68 अंक यानी 0.71 फीसदी लुढ़ककर 85,102.69 के स्तर पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान एक समय बीएसई सेंसेक्स 836.78 अंक टूटकर 84,875.59 पर आ गया था। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) का 50 शेयरों वाला निफ्टी भी 225.90 अंक यानी

0.86 फीसदी फिसलकर 25,960.55 के स्तर पर आ गया। कारोबार के दौरान एक समय यह 294.2 अंक टूटकर 25,892.25 के निचले स्तर पर आ गया था।30 शेयरों पर आधारित मानक सूचकांक सेंसेक्स के शेयर में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, इटर्नल, ट्रेंट, टाटा स्टील, बजाज फाइनेंस, अदाणी पोर्ट्स, बजाज फिनसर्व, भारतीय स्टेट बैंक, पावरग्रिड, एशियन पेंट्स, टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स, टाइटन, एनटीपीसी, कोटक महिंद्रा बैंक, लार्सन एंड टूब्रो और भारती एयरटेल में उल्लेखनीय गिरावट हुई। वहीं, टेक महिंद्रा, एचसीएल टेक्नोलॉजीज, रिलायंस इंडस्ट्रीज और एचडीएफसी बैंक के शेयर बढ़त के साथ बंद हुए।विश्लेषकों ने कहा कि इस हफ्ते अमेरिकी फेडरल रिजर्व के नीतिगत निर्णय आने से पहले निवेशकों ने रक्षात्मक रुख अपनाया, जिससे धारणा और कमजोर हुई। ऊंचे स्तर पर मुनाफावसूली और विदेशी निवेशकों की बिकवाली जारी रहने से बाजार पर दबाव बढ़ गया था। इसके अलावा यूरोपीय शेयर बाजार मिलेजुले रुख के साथ कारोबार कर रहे थे। वैश्विक तेल मानक ब्रेंट क्रूड 0.61 फीसदी गिरकर 63.37 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल के भाव पर था। 30 शेयरों वाला बीएसई का सेंसेक्स 447.05 अंक यानी 0.52 फीसदी बढ़कर 85,712.37 अंक पर बंद हुआ था। 50 शेयरों वाला एनएसई का निफ्टी 152.70 अंक यानी 0.59 फीसदी चढ़कर 26,186.45 पर बंद हुआ था।

आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी का आईपीओ 12 दिसंबर को खुलेगा, मूल्य दायरा 2,061-2,165 रुपये प्रति शेयर

एजेंसी

मुंबई। देश के सबसे बड़े निजी क्षेत्र के आईसीआईसीआई बैंक की अनुषंगी कंपनी आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एसेट मैनेजमेंट कंपनी (एएमसी) का आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) 12 दिसंबर को खुलेगा। निवेशक इसमें 16 दिसंबर तक बोली लगा सकते हैं। कंपनी ने इसके लिए मूल्य का दायरा (प्राइस बैंड) 2,061-2,165 रुपये प्रति शेयर तय किया है। कंपनी ने जारी बयान में बताया कि उसका 10,602 करोड़ रुपये का आईपीओ बोली के लिए 12 दिसंबर को खुलेगा और 16 दिसंबर को बंद होगा। इसके लिए बड़े (एंकर) निवेशक 11 दिसंबर को बोली लगा सकते हैं। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एसेट मैनेजमेंट कंपनी ने कहा कि इसके लिए मूल?य का दायरा (प्राइस बैंड) 2,061-2,165 रुपये प्रति शेयर तय किया गया है। इसमें न्यूनतम 6 इक्विटी शेयर्स के लिए और उसके

बाद 6 इक्विटी शेयर्स के मल्टीपल में बोली लगाई जा सकती है।कंपनी ने कहा कि यह निर्गम पूरी तरह से प्रवर्तक द्वारा 4.89 करोड़ से अधिक शेयर की बिक्र पेशकश (ओएफएस) पर आधारित है। इसलिए कंपनी को इस प्रस्ताव से कोई पूंजी प्राप्त नहीं होगी और प्राप्त राशि विक्रयकर्ता शेयरधारक को जाएगी। कंपनी ने कहा कि निर्गम आकार का आधा हिस्सा योग्य संस्थागत खरीदारों के लिए, 35 फीसदी खुदरा निवेशकों के लिए और शेष 15 फीसदी गैर-संस्थागत निवेशकों के लिए आरक्षित है।बैंक ने बताया कि इस खरीद का उपयोग मुख्य रूप से कंपनी द्वारा स्टॉक-आधारित मुआवजा दिए जाने की स्थिति में बैंक की बहुलांश हिस्सेदारी को बनाए रखने के लिए किया जाएगा। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी का शेयर 19 दिसंबर को शेयर बाजार में सूचीबद्ध हो सकता है। इससे कंपनी का बाजार मूल्यांकन 1.07 लाख करोड़ रुपये (करीब 11.86 अरब डॉलर) आंका गया है।

घर में पकने वाली थाली की कीमत एक साल में 13फीसदी घटी

एजेंसी

नई दिल्ली। सब्जियों और दालों के भाव घटने से घर में पकने वाली शाकाहारी और मांसाहारी थाली एक साल में 13 फीसदी तक सस्ती हो गई। क्रिसिल रेटिंग के अनुसार, नवंबर में शाकाहारी थाली की कीमत 28.4 रुपये रह गई जो नवंबर, 2024 में 32.7 रुपये थी। इसी दौरान मांसाहारी थाली का दाम 61.5 रुपये से घटकर 53.8 रुपये पर आ गया। क्रिसिल के अनुसार, मासिक आधार पर अक्तूबर में मांसाहारी थाली की कीमत 54.4 रुपये और शाकाहारी थाली की कीमत 27.80 रुपये रही थी। घर पर थाली बनाने की औसत लागत की गणना उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम भारत में कीमतों के आधार पर की जाती है। आलू व टमाटर की कीमतों में क्रमशः 5 और फीसदी की वृद्धि हुई। इससे थालियों की कुल लागत में वृद्धि हुई। अन्य प्रमुख वस्तुओं की कीमतें लगभग स्थिर रहीं। अधिक आपूर्ति के कारण टमाटर की कीमतों में पिछले वर्ष की तुलना में 17 फीसदी की गिरावट आई। उच्च आधार के कारण आलू के दाम इस दौरान 29 फीसदी घट गए। पिछले रबी सीजन से अधिक स्टॉक की उपलब्धता और कमजोर निर्यात के कारण प्याज की कीमतों में 53 फीसदी की कमी आई है। स्टॉक में वृद्धि से चालू वित्त वर्ष में दालों की कीमतों में 17 फीसदी की गिरावट आई है। इसकी वजह आयात में तेजी है।

'भारत-ईयू मुक्त व्यापार समझौता जल्द पूरा होने की उम्मीद', गोयल बोले- पूरी निष्ठा से कर रहे काम

एजेंसी

नई दिल्ली। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और यूरोपीय संघ समग्र तथा संतुलित मुक्त व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने के लिए पूरी निष्ठा के साथ काम कर रहे हैं। ऐसा समझौता एकतरफा नहीं हो सकता है। सभी दौर की बातचीत में दोनों पक्षों के हितों के बारे में चर्चा होती है, जिससे समझौता निष्पक्ष और संतुलित रह सके।

ईयू के व्यापार आयुक्त के साथ मंत्री ने की चर्चा

मंत्री ने नई दिल्ली में यूरोपीय संघ के व्यापार आयुक्त मारोस सेफकोविक के साथ प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) को जल्द अंतिम रूप देने के लिए चर्चा की। मारोस व्यापार वार्ता के लिए यूरोपीय संघ के अधिकारियों के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे हैं। मंत्री गोयल ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के माध्यम से बताया कि यह बैठक निर्णायक रही है। हमने वार्ता को आगे बढ़ाने के लिए लंबित मुद्दों को सुलझाने के तरीकों पर विचार-विमर्श किया।

'एफटीए की दिशा में निरंतर सहयोग की आशा'

उन्होंने कहा कि पारस्परिक रूप से लाभकारी एफटीए की दिशा में निरंतर सहयोग की आशा है। दरअसल, कुछ क्षेत्रों में अब भी मतभेद हैं। इनमें इस्पात, कार्बन कर, ऑटोमोबाइल और गैर-टैरिफ बाधाएं शामिल हैं, जिन्हें दूर करने की जरूरत है। ईयू विशेष रूप से भारत में ऑटोमोबाइल, चिकित्सा उपकरणों, शराब, स्पिरिट्स और मांस जैसे उत्पादों पर शुल्क कटौती चाहता है।

आठ साल के लंबे अंतराल के बाद भारत-ईयू की वार्ता

भारत और 27 देशों के ईयू समूह ने आठ साल के लंबे अंतराल के बाद जून 2022 में व्यापक एफटीए, निवेश संरक्षण समझौते और भौगोलिक संकेत पर समझौतों के लिए बातचीत फिर से शुरू की थी। 2024-25 में ईयू भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार था, जिसके साथ द्विपक्षीय व्यापार 1.36 लाख करोड़ रुपये। यह समझौता दोनों अर्थव्यवस्थाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। जून 2022 में, भारत और 27 देशों के यूरोपीय संघ समूह ने आठ वर्षों से अधिक के अंतराल के बाद एक व्यापक मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए), एक निवेश संरक्षण समझौते और भौगोलिक संकेतों पर एक समझौते के लिए बातचीत फिर से शुरू की।

म्यामांर में साइबर अपराध के आरोपी 1178 चीनी नागरिकों को वापस भेजा गया

एजेंसी

बीजिंग। चीन के जन सुरक्षा मंत्रालय ने कहा कि इस महीने की शुरुआत से म्यांमार के म्यावाडी में टेलीकॉम धोखाधड़ी के मामलों में शामिल कुल 1,178 चीनी नागरिकों को वापस लाया गया है। मंत्रालय ने अपने आधिकारिक वीचैट अकाउंट पर एक बयान में कहा कि एक दिसंबर से संदिग्धों को चीनी पुलिस की निगरानी में थाईलैंड के रास्ते समूहों में सौंपा गया है। यह हस्तांतरण 14 नवंबर को चीन, कंबोडिया, लाओस, म्यांमार, थाईलैंड और वियतनाम के बीच हुई एक मंत्री स्तरीय बैठक के बाद हुआ। बैठक में शामिल देशों ने सहयोग को गहरा करने और सीमा पार टेलीकॉम धोखाधड़ी पर मिलकर कार्रवाई शुरू करने पर सहमति जताई थी।

चीन, म्यांमार और थाईलैंड के पुलिस बलों ने हाल ही में म्यावाडी इलाके पर ध्यान केंद्रित करते हुए अभियान का एक और दौर शुरू किया, जहां म्यांमार ने ठगी के कई ठिकानों को खाली कराया और संदिग्धों के समूह को हिरासत में लिया। चीनी मंत्रालय के अनुसार, 20 फरवरी से अब तक टेलीकॉम ठगी के शक में 6,600 से ज़्यादा चीनी नागरिकों को चीन वापस भेजा गया है। मंत्रालय ने कहा कि सीमा पार टेलीकॉम धोखाधड़ी के खिलाफ बहु-देशीय कार्रवाई जारी है और चीन आपराधिक नेटवर्क को खत्म करने एवं सार्वजनिक सुरक्षा के लिए कानून-प्रवर्तन सहयोग को मजबूत करना जारी रखेगा।

रोमानिया में सिउकू ने जीता बोखारेस्ट के महापौर का चुनाव

बुखारेस्ट। रोमानिया की नेशनल लिबरल पार्टी के सिप्रियन सिउकू ने बुखारेस्ट के महापौर के लिए हुए चुनाव में जीत दर्ज करते हुए राजधानी का सबसे बड़ा पद हासिल कर लिया। रोमानिया के स्थायी चुनावी प्राधिकरण के के अनुसार सभी 1,289 मतदान केंद्रों की गिनती पूरी होने के बाद श्री सिउकू को 36.16 प्रतिशत वोट मिले। बुखारेस्ट के 589,000 से ज़्यादा निवासियों ने वोट डाले, जो पंजीकृत मतदाताओं का 32.71 प्रतिशत था। श्री सिउकू ने 2000 में राजनीति में कदम रखा था और बाद में स्थानीय प्रशासन में शामिल हो गये थे शुरू में उन्होंने स्थानीय पार्षद के तौर पर काम किया। वह 2020 से बुखारेस्ट के सेक्टर 6 के पार्षद हैं। मई में पूर्व महापौर निकुसोर डैन के राष्ट्रपति चुने जाने के बाद यह की सीट खाली हो गई थी। श्री सिउकू 2028 तक इस पद पर रहेंगे।

काली मिर्च निर्यात में वियतनाम का दबदबा: 11 महीने में सवा दो लाख टन से अधिक का निर्यात

हनोई। वैश्विक काली मिर्च निर्यात बाजार पर वियतनाम का दबदबा लगातार मजबूत होता जा रहा है। वियतनाम ने इस वर्ष के पहले 11 महीनों में 1.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक मूल्य की कुल 2,25,009 टन काली मिर्च का निर्यात करके अपनी नंबर वन की पोजीशन को बरकरार रखा है। वियतनाम ने इस अवधि के दौरान कुल 2,25,009 टन काली मिर्च का निर्यात किया, जिसमें 1,92,899 टन काली मिर्च और 32,110 टन सफेद मिर्च शामिल थी। देश को काली मिर्च से लगभग 1.25 बिलियन अमेरिकी डॉलर और सफेद मिर्च से 262 मिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक की आय हुई। रिपोर्ट के अनुसार, संयुक्त राज्य अमेरिका वियतनामी काली मिर्च के लिए सबसे बड़ा बाजार बना हुआ है, जो कुल निर्यात का 21.7 प्रतिशत (48,849 टन) है। वियतनाम अपनी आधुनिक कृषि तकनीक और प्रतिस्पर्धी कीमतों के कारण काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक बना हुआ है, जिसका वैश्विक निर्यात में हिस्सा लगभग 35 से 45 प्रतिशत है। अन्य शीर्ष निर्यातकों में ब्राजील करीब एक लाख टन और इंडोनेशिया अधिकतम 70 टन शामिल हैं। ये तीनों देश मिलकर वैश्विक आपूर्ति के एक बड़े हिस्से को नियंत्रित करते हैं। इस प्रतिस्पर्धा के बावजूद, भारत भी काली मिर्च के निर्यात में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है।

आम पाकिस्तानी अपने देश की पुलिस को मानता है भ्रष्ट : इंटरनेशनल सर्वे

इस्लामाबाद । पाकिस्तान के विभिन्न विभाग भ्रष्टाचार के गहरे जाल में फंसे हैं। इनमें से पुलिस सबसे ज्यादा भ्रष्ट है। भ्रष्टाचार के मामले में दूसरा नंबर निविदा का है, फिर प्रोक्योरमेंट सेक्टर का, और न्यायपालिका चौथे नंबर पर आती है। यानी सत्ता के लगभग हर उस सेक्टर में भ्रष्टाचार का बोलबाला है जिससे आवाम को राहत की उम्मीद होती है। विभिन्न प्रांतों के बाशिंदों की सोच विभिन्न सेक्टर्स को लेकर कुछ खास उत्साहजनक नहीं है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने मंगलवार को जारी सालाना सर्वे रिपोर्ट में ये अहम जानकारी दी। टीआई की एक प्रेस रिलीज के मुताबिक, 'नेशनल करप्शन परसेप्शन सर्वे' का मकसद जरूरी गवर्नेंस मुद्दों पर जनता की धारणा को समझना था। सर्वे में शामिल 4,000 लोगों (हर प्रांत से 1,000) में से 24 फीसदी का मानना था कि पुलिस विभाग सबसे भ्रष्ट है, जिसमें पंजाब प्रांत सबसे आगे है, यहां 34 फीसदी लोगों ने माना कि सरकारी महकमों में भ्रष्टाचार व्याप्त है। इसके बाद बलूचिस्तान में 22 फीसदी, सिंध में 21 फीसदी और खैबर पख्तूनख्वा में 20 फीसदी थी। पुलिस के बाद टेंडर और प्रोक्योरमेंट (खरीद) सेक्टर था, जहां 16 फीसदी लोगों ने माना कि ये सेक्टर भ्रष्ट है। बलूचिस्तान में 23 प्रतिशत, केपी में 18 प्रतिशत, सिंध में 14 फीसदी और पंजाब में 9 फीसदी लोगों का कहना था कि इन सेक्टर्स में भ्रष्टाचार का बोलबाला है। प्रेस रिलीज के मुताबिक, सर्वे से यह भी पता चला कि लगभग 77 फीसदी लोगों को सरकार की भ्रष्टाचार विरोधी कोशिशों पर भरोसा न के बराबर है।

यूरोप में कॉर्पोरेट की कोशिशें नाकाम, कर्मचारियों में बढ़ रही है मानसिक थकान

एजेंसी

बिल्बाओ। यूरोप में काम के कारण हुई थकान (बर्नआउट) पूरे महाद्वीप में एक मानसिक स्वास्थ्य संकट को जन्म दे रही है। कार्यस्थल पर सुरक्षा एवं स्वास्थ्य के लिये यूरोपीय एजेंसी के एक सर्वेक्षण में यह खुलासा हुआ है।

इस सर्वेक्षण के अनुसार, यूरोप के 30 देशों में करीब 50 प्रतिशत कर्मचारियों का मानना है कि उनके ऊपर काम का भार ज़रूरत से ज़्यादा है, जबकि 34 प्रतिशत का मानना है कि उनकी मेहनत को अहमियत नहीं दी जाती। करीब 16 प्रतिशत ने काम के दौरान उत्पीड़न का दावा किया है। इस दबाव की वजह से शोधकर्ताओं ने एक 'प्रचलित विरोधाभास' की पहचान की है। कर्मचारियों के अच्छे मानसिक स्वास्थ्य पर किये गये

अच्छे खासे निवेश के बावजूद स्थिति सुधर नहीं रही है। यूरोपियन कंपनियों ने 2023 में 'वर्कप्लेस वेलनेस' पहल पर लगभग 16.9 अरब यूरो खर्च किये। कंपनियों ने माइंडफुलनेस क्लास और कोचिंग पर खर्चा किया, जो लगभग 29फीसदी कर्मचारियों के लिये उपलब्ध हैं।यूरोपीय ट्रेड यूनियन इंस्टीट्यूट (ईटीयूआई) और अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन के विशेषज्ञों का कहना है कि ये कार्यक्रम इसलिये काम नहीं करते क्योंकि ये 'संरचनात्मक मनोसामाजिक' जोखिम का समाधान नहीं करते। यानि ये कार्यक्रम नौकरी से होने वाले तनाव, लंबी शिफ्ट, काम को पहचान न मिलना, नौकरी की असुरक्षा और मानसिक उत्पीड़न पर काम नहीं करते।सकारात्मक मानसिकता विषय के शोधकर्ता जोलांता बर्क के अनुसार, मौजूदा तरीका अक्सर 'बहुत ज़्यादा आसान, बहुत ज़्यादा मैकेनिकल होता है, और हमें नतीजे नहीं मिल रहे हैं। 'विशेषज्ञों का कहना है कि कर्मचारियों की बेहतरी के लिये कंपनियों को हर आयाम को ध्यान में रखते हुए एक दीर्घकालिक योजना बनाने की ज़रूरत है जो सिर्फ़ एड-हॉक एचआर कार्यक्रम से आगे बढ़कर काम करे। मानसिक रूप से स्वस्थ कार्यालय बनाने के लिये व्यवसाय की प्रक्रिया को फिर से सोचना होगा। इसमें भर्ती, पदोन्नति, काम की समीक्षा और प्रबंधन का तरीका शामिल है।

कुछ कंपनियां बड़े सुधारों के साथ प्रयोग कर रही हैं। मिसाल के तौर पर, ब्रिटेन, जर्मनी और आइसलैंड में हफ्ते में सिर्फ चार-दिन काम करवाने का प्रयोग किया गया। शुरुआती शोध से पता चलता है कि इससे मानसिक थकान कम हो सकती है। स्वीडन जैसे देशों में काम के भार और धमकाने को लेकर नियम हैं, जबकि फ्रांस और पुर्तगाल ने 'राइट-टू-डिसकनेक्ट' कानून लागू किये हैं, जिसके तहत कोई कंपनी शिफ्ट खत्म होने के बाद काम के लिये कर्मचारी से संपर्क नहीं कर सकती।

अमेरिका से सुरक्षा गारंटी और सीमाई मुद्दों पर अब भी असहमति : जेलेंस्की

एजेंसी

लंदन। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने कहा है कि वाशिंगटन के साथ शांति-योजना को लेकर चल रही वार्ताओं में कई अहम मुद्दे अब भी अनसुलझे हैं। डाउनिंग स्ट्रीट पहुंचने से कुछ देर पहले दिए बयान में उन्होंने स्पष्ट किया कि अमेरिकी प्रस्ताव में शामिल 'संवेदनशील बिंदुओं' पर और चर्चा की आवश्यकता है, जिनमें सुरक्षा गारंटियों से लेकर पूर्वी यूक्रेन के इलाकों का नियंत्रण प्रमुख है। जेलेंस्की ने कहा कि डोनबास क्षेत्र–जिसमें डोनेत्स्क और लुहांस्क आते हैं–के भविष्य पर यूक्रेन, अमेरिका और रूस की राय अभी भी एक जैसी नहीं है। उनके अनुसार, 'तीनों देशों की दृष्टि अलग-अलग है और डोनबास पर कोई साझा रुख तय नहीं हो पाया है। ' उन्होंने यह भी दोहराया कि कीव अपने पश्चिमी सहयोगियों, विशेषकर अमेरिका, के साथ एक अलग सुरक्षा गारंटी व्यवस्था चाहता है। ज़ेलेंस्की ने पूछा, 'हर यूक्रेनी का एक ही सवाल है–अगर रूस दोबारा युद्ध छेड़ता है, तो हमारे साझेदार क्या करेंगे? ' राष्ट्रपति ने कहा कि सुरक्षा गारंटियों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा यूरोप से जुड़ा है, इसलिए यूरोपीय देशों के साथ यूक्रेन की संभावित ईयू सदस्यता पर गंभीर बातचीत होनी चाहिए। उन्होंने यह भी संकेत दिया कि वह अमेरिका की यात्रा के लिए तैयार हैं। ज़ेलेंस्की ने कहा, 'अगर अमेरिकी राष्ट्रपति तैयार हैं, तो मैं तुरंत वहां जाने को तैयार हूं।

ओली ने देउवा से मुलाकात करके चुनावी गठबंधन बनाने का रखा प्रस्ताव

एजेंसी

काठमांडू। अगले साल होने वाले संसदीय चुनावों के लिए नेकपा-एमाले के अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेपाली कांग्रेस के साथ चुनावी गठबंधन करने की कोशिशों में लग गए हैं। जेनजी आंदोलन के चलते सत्ता गंवाने से पहले ओली नेपाली कांग्रेस के समर्थन से प्रधानमंत्री थे।

आंदोलन के बाद पहली बार ओली ने कांग्रेस अध्यक्ष शेरबहादुर देउवा से महाराजगंज स्थित उनके निवास पर जाकर मुलाक़ात की थी। इस मुलाक़ात में ओली ने भविष्य में राजनीतिक सहयोग जारी रखने और राष्ट्रीय सभा चुनाव से लेकर प्रतिनिधि सभा के चुनाव तक में मिलकर लड़ने का प्रस्ताव रखा। ओली और देउवा दंपत्ति के बीच हुई बातचीत के बारे में आधिकारिक रूप से तस्वीर जारी करते हुए वर्तमान राजनीतिक हालात और भविष्य की राजनीति पर चर्चा होने की बात कही गई है। हालांकि, इस मुलाक़ात के तुरंत बाद ही रविवार को कांग्रेस ने संसद पुनर्स्थापना की मांग करते हुए सर्वोच्च अदालत में रिट दायर कर

दी। इससे पहले एमाले ने इसी विषय में रिट दायर की थी।

विघटित प्रतिनिधि सभा में कांग्रेस के प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरे ने बताया कि देउवा-ओली मुलाक़ात के बाद ही रिट दायर करने पर सहमति बनी थी। एमाले के मुख्य सचेतक महेश बर्तौला ने भी पुष्टि की कि दोनों नेताओं के बीच रिट दायर करने पर चर्चा हुई थी। घिमिरे के अनुसार सहमति के आधार पर ही कांग्रेस संसद पुनर्स्थापना की मांग लेकर अदालत गई है। कांग्रेस अध्यक्ष और एमाले अध्यक्ष के बीच की मुलाक़ात के बाद ही यह घटनाक्रम आगे बढ़ा है। उधर एमाले के बरतौला ने कहा कि इस मुलाकात के दौरान जनवरी में प्रस्तावित राष्ट्रीय सभा और मार्च में होने वाले प्रतिनिधि सभा चुनाव में गठबंधन बना कर जाने का प्रस्ताव ओली के तरफ से रखा गया जिस पर देउवा भी सकारात्मक रहे।

जेनजी आंदोलन के कारण कांग्रेस-एमाले गठबंधन के प्रधानमंत्री ओली ने इस्तीफ़ा दिया था। इसके बाद नियुक्त प्रधानमंत्री सुशीला कार्की ने प्रतिनिधि सभा भंग करने की सिफारिश की, जिसे राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल ने मंजूर करते हुए 5 मार्च के लिए चुनाव की तिथि तय की थी।

गोवा नाइट क्लब अग्निकांड में मारे गए चार नेपाली नागरिकों के शवों को नेपाल लाने की तैयारी

एजेंसी

काठमांडू। भारत के गोवा स्थित एक नाइट क्लब में लगी भीषण आग में चार नेपाली नागरिकों की मृत्यु हो गई है। नई दिल्ली स्थित नेपाली दूतावास इन शवों को नेपाल भेजने के लिए गोवा सरकार से समन्वय कर रहा है।

भारत में नेपाल के राजदूत दूतावास डॉ. शंकर शर्मा ने टेलीफोन पर बताया कि भारत के विदेश मंत्रालय के जरिए गोवा सरकार की तरफ से चार नेपाली नागरिकों के मौत की जानकारी मिली है। उन्होंने बताया कि आवश्यक कानूनी प्रक्रिया के बाद सभी शवों को नेपाल भेजने की तैयारी की जाएगी। नेपाली दूतावास के मुताबिक चार मृतकों में अब तक 2 की पूरी पहचान हो पाई है। अभी भी दो शवों के नाम का तो पता चला है, लेकिन उनके घर का पता ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है।

भारत में नेपाल के राजदूत डॉ. शर्मा ने बताया कि मृतकों में चूर्ण बहादुर पुन तथा विवेक कटवाल दोनों ही झापा जिले के हैं। ऐसे ही मृतक नेपाली नागरिकों के सुदीप और सबीन के घर के पता नहीं चल पाया है। नेपाल में गृह मंत्रालय से इस बारे में जानकारी एकत्रित करने का प्रयास चल रहा है। गोवा के अरपोरा क्षेत्र में स्थित नाइट क्लब में शनिवार मध्य रात को आग लगने से कुल 25 लोगों की जान गई थी। गोवा के मुख्यमंत्री

प्रमोद सावंत ने मृतकों के परिजनों को पांच लाख रुपये तथा घायलों को पचास-पचास हजार रुपये राहत राशि देने की घोषणा की है।

टोक्यो डकैती के मास्टरमाइंड ने सोशल मीडिया से की थी अपराधियों की भर्ती : जाँच एजेंसियाँ

एजेंसी

टोक्यो। जापान की राजधानी टोक्यो में डकैतियों के मामले में पकड़े गए चार संदिग्ध मास्टरमाइंडों ने अपने गिरोह में युवा और नए अपराधियों को शामिल करने के लिए बाकायदा सोशल मीडिया में विज्ञापन दिया था। पुलिस ने यह जानकारी दी । स्थानीय मीडिया के अनुसार पिछले साल हुई सिलसिलेवार डकैतियों की जांच में पता चला है कि इन संदिग्धों ने सोशल मीडिया 'एक्स' (पूर्व में ट्विटर) अकाउंट का इस्तेमाल कर अपने गिरोह में अपराधियों की भर्ती की थी।

स्थानीय मीडिया के अनुसार टोक्यो पुलिस विभाग को इस हाई-प्रोफाइल मामले में जब्त हुए स्मार्टफोन की गहन जांच से यह बात पता चली। जाँच एजेंसियों ने पाया कि चारों संदिग्धों ने पिछले साल अगस्त के अंत से अक्टूबर के अंत के बीच यह भर्तियां की थीं और उस समय डकैतियों की घटनाएं चरम पर थीं। पुलिस ने बताया इन लोगों ने कई

बार 'एक्स' अकाउंट खरीदे और इनका उपयोग 'डार्क पार्ट-टाइम जॉब्स' (यामी बाइटो) पोस्ट करके गिरोह में भर्ती के लिए किया। इनमें लोगों को प्रलोभन दिया जाता कि अपराध में शामिल होने वाले को उसी दिन भुगतान कर दिया जायेगा। वे इन विज्ञापनों में धोखाधड़ी, डकैती और चोरी सहित कई उपलब्ध 'अवैध' नौकरियों की जानकारी देते थे।

पुलिस का मानना है कि इन संदिग्धों ने एक 'टोक्योरयू' नाम से एक गुप्त आपराधिक समूह बनाया। इस समूह ने 'इस हाथ दे और उस हाथ ले' के उसूल और बड़े भुगतान के वादे पर सोशल मीडिया से नए लोगों की भर्ती की।पुलिस को यह भी पता चला है कि डकैतियों में शामिल सदस्य, अपने गुर्गों को चुनने के लिए अत्यधिक एन्क्रिप्टेड (सुरक्षित) संचार ऐप 'सिग्नल' पर एक ग्रुप चैट का उपयोग करते थे। इस चैट में वे भर्ती के तरीकों और आवश्यक कौशल पर जानकारी का आदान-प्रदान करते थे। पुलिस ने हिरोटो फुकुची (26) सहित चार संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। इन लोगों पर पिछले साल अक्टूबर में चिबा प्रान्त में एक 51 वर्षीय महिला के घर में घुसकर मारपीट करने और डकैती डालने का संदेह है। जाँच से पता चला है कि पिछले साल अगस्त के अंत से टोक्यो क्षेत्र में डकैती और सेंधमारी के लगभग 30 मामले ऐसे थे जिन्हें इस प्रकार भर्ती किए गए अपराधियों ने अंजाम दिया। इनमें योकोहामा में 75 वर्षीय पीड़ित हिरोहारू गोटो की घातक डकैती का मामला भी शामिल है। अब तक, इन मामलों में 50 से अधिक अपराधियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, लेकिन यह पहली बार है कि इन डकैती मामलों के पीछे के मास्टरमाइंड लोगों को पकड़ा गया है।

बांग्लादेश में बढ़ी राजनीतिक हलचल

एजेंसी

ढाका। बांग्लादेश में फरवरी 2026 के चुनाव को लेकर जमात-ए-इस्लामी ने चुनाव आयोग से जल्द शेड्यूल जारी करने की मांग की। 10 दिसंबर को सीईसी का संबोधन हो सकता है। बांग्लादेश में साल 2026 में होने वाले आम चुनाव को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है।कट्टरपंथी पार्टी जमात-ए-इस्लामी ने चुनाव आयोग पर दबाव बढ़ाते हुए तुरंत शेड्यूल जारी करने की मांग की है। इस बीच, सूचना मिली है कि 10 दिसंबर को आयोग बड़ी घोषणा कर सकता है। देश की राजनीतिक पार्टियों में चुनाव टाइमलाइन को लेकर असमंजस बना हुआ है। बांग्लादेश में फरवरी 2026 में होने वाले आम चुनाव से पहले राजनीतिक तनाव लगातार बढ़ रहा है। कट्टरपंथी इस्लामी संगठन जमात-ए-इस्लामी ने चुनाव आयोग से जल्द इलेक्शन शेड्यूल जारी करने की मांग की। जमात के प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि रमजान शुरू होने से पहले चुनाव कराने के लिए बहुत कम समय बचा है, इसलिए आयोग को तुरंत कदम उठाने चाहिए।

पानी विवाद पर ट्रंप ने मेक्सिको को नए शुल्क लगाने की धमकी दी

एजेंसी

वाशिंगटन। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मेक्सिको को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर वह 1944 में हस्ताक्षरित द्विपक्षीय संधि के आधार पर पानी की आपूर्ति नहीं करता है, तो उसके सामानों पर अतिरिक्त पाँच फीसदी आयात शुल्क लगाए जाएँगे।

श्री ट्रंप ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि मेक्सिको के इस संधि का लगातार उल्लंघन करने से टेक्सास की फसलों और पशुधन को गंभीर नुक़सान हो रहा है। उन्होंने कहा, 'मेक्सिको अभी भी पिछले पांच बरसों में हमारी संधि का पालन करने में विफल रहने के कारण अमेरिका को मेक्सिको से 31 दिसंबर से पहले 2,00,000 एकड़-फीट (24.66 करोड़ घन मीटर) पानी जारी करने की ज़रूरत है, और बाक़ी पानी जल्द ही आना चाहिए। '

श्री ट्रंप ने कहा कि उन्होंने 'इस पानी को फ़ौरन (तुरंत) जारी न किए जाने पर मेक्सिको पर पांच प्रतिशत शुल्क लगाने के दस्तावेज़ों को अधिकृत कर दिया है। ' गौरतलब है कि सन 1944 की जल संधि, को अमेरिका का 8,00,000 एकड़-फीट (98.64 करोड़ घन मीटर) से अधिक पानी का क़र्ज़दार है।

कोलोराडो और तिजुआना नदियों और रियो ग्रांडे के पानी के उपयोग पर संधि के नाम से भी जाना जाता है। इसके अनुसार अमेरिका को कोलोराडो नदी से मेक्सिको को सालाना 15 लाख एकड़-फीट (1.85 अरब घन मीटर) पानी भेजना होता है, जबकि मेक्सिको को पांच वर्षीय चक्रों में रियो ग्रांडे से अमेरिका को 17.5 लाख एकड़-फीट (2.2 अरब घन मीटर) पानी पहुँचाना अनिवार्य है। श्री ट्रंप ने इससे पहले भी 10 अप्रैल को इस मामले पर मेक्सिको को प्रतिबंधों और शुल्कों की धमकी दी थी। इसके बाद अप्रैल के अंत में दोनों पक्षों ने प्रगति की घोषणा की थी।

जापान में 7.6 तीव्रता के भूकंप के बाद 3 मीटर ऊंची सुनामी की चेतावनी

एजेंसी

टोक्यो। उत्तर-पूर्वी जापान रात तब दहल उठा, जब 7.6 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप आने के तुरंत बाद तटीय इलाकों में 3 मीटर तक ऊंची सुनामी की आशंका जताई गई। जापान मौसम विज्ञान एजेंसी (जेएमए) ने देर रात 11:15 बजे आए भूकंप के बाद होक्काइदो, आओमोरी और इवाते प्रांतों के लिए सुनामी की चेतावनी जारी की। एजेंसी के अनुसार, भूकंप का केंद्र आओमोरी तट से लगभग 80 किलोमीटर दूर समुद्र में 50 किलोमीटर की गहराई पर था। झटके इतने तेज थे कि आओमोरी प्रांत में भूकंपीय तीव्रता 'अप्पर 6' दर्ज की गई। यह ऐसा स्तर है जिसमें खड़े रहना भी मुश्किल हो जाता है और भारी फर्नीचर तक गिर सकता है।

कई तटीय क्षेत्रों में लहरें तेज

जेएमए ने बताया कि आओमोरी के मुत्सु ओगावारा और होक्काइदो के उराकावा बंदरगाह पर 20 से 50 सेंटीमीटर ऊंची सुनामी लहरें देखी गईं। देर रात जारी अपडेट में आओमोरी, इवाते और होक्काइदो के कई शहरों में भी 20-40 सेंटीमीटर ऊंची लहरें दर्ज होने की पुष्टि हुई।

30,000 से अधिक लोगों को निकाला गया

भूकंप के बाद आपातकालीन चेतावनियां जारी होने पर इवाते, मियागी और आओमोरी के कई शहरों में करीब 30,000 से ज्यादा निवासियों को सुरक्षित स्थानों पर जाने के निर्देश दिए गए। कई लोग घरों से बाहर सड़क पर आ गए, जबकि सोशल मीडिया पर हिलते फर्नीचर और कंपन के वीडियो सामने आए।

प्रधानमंत्री ने राहत कार्यों की निगरानी तेज की

जापान की प्रधानमंत्री साने ताकाइची ने कहा कि सरकार 'जन जीवन को सर्वोच्च प्राथमिकता' देते हुए बचाव और राहत कार्यों में पूरी क्षमता से जुटी है। सरकारी प्रवक्ताओं के अनुसार, प्रभावित क्षेत्रों में नुकसान और हताहतों की जानकारी जुटाई जा रही है। अब तक आओमोरी शहर में दो स्थानों पर आग लगने की खबरें मिली हैं। ईस्ट जापान रेलवे ने सुरक्षा कारणों से कुछ ट्रेन सेवाएं रोक दीं। तोहोकू इलेक्ट्रिक पावर कंपनी के अनुसार, कुछ इलाकों में बिजली आपूर्ति बाधित हुई है, हालांकि क्षेत्र के किसी भी परमाणु संयंत्र में कोई अनियमितता नहीं पाई गई।

म्यांमार में 3.7 तीव्रता का भूकंप

एजेंसी

नेपीडॉ (म्यांमार)। भारत के पड़ोसी देश म्यांमार में मध्य रात्रि को भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 3.7 दर्ज की गई है। भारत के राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र (एनसीएस) के मुताबिक, 09 दिसंबर 2025 को म्?यांमार में मध्य रात्रि एक बजकर 21 मिनट (भारतीय समयानुसार)

पर 3.7 तीव्रता का भूकंप दर्ज किया गया। भूकंप का केंद्र जमीन से 30 किमी की गहराई पर था। इससे पहले दो बार भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। पहले सुबह 10 बजकर 18 मिनट पर 3.8 तीव्रता का भूकंप दर्ज किया गया था। भूकंप का केंद्र जमीन से 80 किमी की गहराई पर था। इसके बाद दोपहर 3 बजकर 46 मिनट पर 3.5 तीव्रता का भूकंप आया था। भूकंप का केंद्र जमीन से 10 किमी की गहराई पर था। उल्लेखनीय है कि म्यांमार चार टेक्टोनिक प्लेटों (भारतीय, यूरेशियन, सुंडा, बर्मा) के बीच स्थित होने के कारण भूकंप और सुनामी के प्रति अत्यधिक संवेदनशील है।

बेनिन के राष्ट्रपति टैलोन का आश्वासन, तख्तापलट की कोशिश के बाद हालात 'पूरी तरह काबू में'

एजेंसी

कोतोनौ। बेनिन के राष्ट्रपति पैट्रिस टैलोन ने देश में सरकार पलटने की कोशिशों को नाकाम करने के बाद लोगों को भरोसा देते हुए कहा है कि हालात 'पूरी तरह से काबू में' है। सरकार के अनुसार, तख्तापलट की साजिश रचने वालों और सरकारी फौजों रिपब्लिकन गार्ड के बीच खनी झड़पों के बाद कोतोनौ में सूकून लौट आया है। इस काम में नाइजीरिया की फौज ने भी बेनिन की मदद की। दोनों पक्षों में हुयी गोलीबारी में कई लोग हताहत हुए। सरकारी रिपोर्ट के अनुसार, मारे गए लोगों में राष्ट्रपति के सैन्य चीफ-ऑफ-स्टाफ जनरल बर्टिन बादा की पत्नी भी शामिल थीं, जबकि जनरल बादा खुद एक हमले में गंभीर से जख्मी हो गए थे।

राज्य टेलीविजन पर 'मिलिट्री कमेटी फॉर रिफाउंडेशन' नामक फौजियों के दस्ते ने रविवार को ऐलान करते हुए कहा था कि उन्होंने राष्ट्रपति टैलोन को हटा दिया है। आठ सैनिकों ने राष्ट्रपति को हटाने, सरकारी संस्थानों को निलंबित करने और प्रशासन को भंग करने का दावा करते हुए अपनी इजारेदारी पेश की। उन्होंने लेफ्टिनेंट कर्नल पास्कल तिगरी को अपनी समिति का प्रमुख नियुक्त किया था। विद्रोहियों ने अपने कदम को सही ठहराने के लिए उत्तरी बेनिन में बिगड़ती सुरक्षा, मृत सैन्यकर्मियों की उपेक्षा, स्वास्थ्य देखभाल में कटौती, बढ़ते करों और सैनिकों के परिवारों के प्रति सरकार की कथित उदासीनता का हवाला दिया। गौरतलब है कि इस मुल्क की राजधानी पोर्टो-नोवो है, जबकि कोतोनौ देश का सबसे बड़ा शहर और प्रशासनिक केंद्र है। साठ के दशक में फ्रांस से आजादी हासिल

करने के बाद से बेनिन में यदा-कदा तख्तापलट हुए हैं, लेकिन पिछले बीस वर्षों से देश में निर्बाध लोकतांत्रिक शासन रहा है। बेनिन की आबादी लगभग एक करोड़ चालीस लाख है। राष्ट्रपति टैलोन ने राष्ट्र को टेलीविजन पर संबोधित करते हुए नागरिकों को स्थिति नियंत्रण में होने का आश्वासन दिया और उनसे सामान्य गतिविधियाँ फिर से शुरू करने का आग्रह किया। अधिकारियों ने तख्तापलट के संबंध में चौदह व्यक्तियों की गिरफ्तारी की सूचना दी, हालांकि लेफ्टिनेंट कर्नल तिगरी का ठिकाना अभी भी अज्ञात है। श्री टैलोन ने पीड़ितों और अभी भी विद्रोहियों के पास बंदी बनाए गए लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की।

अफ्रीकी संघ ने तख्तापलट के प्रयास की निंदा करते हुए शासन में किसी भी सैन्य हस्तक्षेप को अपने सिद्धांतों का गंभीर उल्लंघन बताया। इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्ट अफ्रीकन स्टेट्स (इकोवास) ने बेनिन के लिए समर्थन का वादा किया है। इन्होंने एक क्षेत्रीय फौजी दस्ते की तैनाती पर हामी भरी जिसमें नाइजीरिया, सिएरा लियोन, आइवरी कोस्ट और घाना की सेनाएं होंगी। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने भी तख्तापलट की आलोचना करते हुए कहा कि यह क्षेत्रीय स्थिरता के लिए खतरा पैदा करता है।

page 1 and 8_page 1 Mar 25 final ds.qxd 12/10/2025 12:20 AM Page 2

भूमि का मृदा परीक्षण

कृषि में मृदा परीक्षण या भूमि की जाँच एक मृदा के किसी नमूने की रासायनिक जांच है जिससे भूमि में उपलब्ध पोषक तत्वों की मात्रा के बारे में जानकारी मिलती है। इस परीक्षण का उद्देश्य भूमि की उर्वरकता मापना तथा यह पता करना है कि उस भूमि में कौन से तत्वों की कमी है।

मृदा पोषक तत्वों का भंडार है तथा पौधों को सीधे खडा रहने के लिए सहारा देती है। पौधों को अपना जीवन चक्र पूरा करने के लिए 16 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। ये तत्व है मुख्य तत्व

कार्बन, हाइडोजन, आक्सीजन, नत्रजन, फास्फोरस, पोठाश, कैल्सिशयम, मैग्नीशियम।

जस्ता, मैग्नीज, ताँबा, लौह, बोरोन, मोलिबडेनम व क्लोरीन।

इन सभी तत्वों का संतुलित मात्रा में प्रयोग करने से ही उपयुक्त पैदावार ली जा सकती है।

यदि किसी भंडार से केवल निष्कासन ही होता रहे और उसमें निष्कासित मात्रा की पूर्ति न की जाय जो कुछ समय बाद वह भंडार खाली हो जाता है। ठीक यही दशा हमारे मृदा की है। लगातार फसल उत्पादन में वृद्वि एवं बडती सघन खेती के परिणाम स्वरूप पोषक तत्वों का ह्रास भी बड रहा है। परंतु उर्वरकों एवं रासायनिक खादों द्वारा उनकी पूर्ति पूरी तरह से नहीं हो पा रही है। जिससे हमारी भूमि की उर्वरा शक्ति क्षीण होती जा रही है।

मृदा की उर्वरा शक्ति की जांच करके फसल व किस्म विशेष के लिए पोषक तत्वों की संतुलित मात्रा की सिफारिश करना तथा यह मार्गदर्शन करना कि उर्वरक व खाद का प्रयोग कब और कैसे करें।

मृदा में लवणता, क्षारीयता तथा अमलीयता की समस्या की पहचान व जांच के आधार पर भूमि सुधारकों की मात्रा व प्रकार की सिफारिश कर भूमि को फिर से कृषि योढय बनाने में योगदान करना।

फलों के बाग लगाने के लिए भूमि की उपयुक्तता का पता लगाना।

किसी गांव, विकास खंड, तहसील, जिला, राज्य की मृदाओं की उर्वरा शक्ति को मानचित्र पर प्रदर्शित करना तथा उर्वरकों की आवश्यकता का पता लगाना। इस प्रकार की सूचना प्रदान कर उर्वरक निर्माण, वितरण एवं उपयोग में सहायता करना।

मृदा परिक्षण के लिए सबसे पहले मृदा का नमूना लिया जाता है। इसके लिए जरूरी है की मृदा का नमूना पूरे क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करे। यदि मृदा का नमूना ठीक डंग से नहीं लिया गया हो और वह मृदा का सही प्रतिनिधित्व न कर रहा हो तो भले ही मृदा परिक्षण में कितनी ही सावधानियां क्यों न बरती जाएं, उसकी सिफारिश सही नहीं हो सकती। अत खेत की मृदा का नमूना पूरी सावधानी से लेना चाहिए।

नमूना लेने के लिए निह्न सामान की आवश्यकता होती है जो किसी भी किसान के पास उपलब्ध होता है। नमूना लेने के लिए सभी सामान साफ होने चाहिए जिससे मृदा दूषित न हो।

खुरपी, फावडा, लकडी, या प्लास्टिक की खुरचनी

ट्रे, या प्लास्टिक की थैली।

पेन, धागा, मृदा का नमूना, सूचना पत्रक

मृदा का नमूना लेने की विधि

जिस जमीन का नमूना लेना हो उस क्षेत्र पर 10-15 जगहों पर निशान लगा लें।

चुनी गई जगह की उपरी सतह पर यदि कूडा करकट या घास इत्यादी हो तो उसे हटा दें।

खुरपी या फावडे से 15 सेमी गहरा गड्ढा बनाएं। इसके एक तरफ से 2-3 सेमी मोटी परत उपर से नीचे तक उतार कर साफ बाल्टी या ट्रे में डाल दें। इसी प्रकार शेष चुनी गई 10-15 जगहों से भी उप नमूने इकट्ठा कर लें। अब पूरी मृदा को अच्छी तरह हाथ से मिला लें तथा साफ कपडे या टब में डालकर डेर बनालें। अंगुली से इस डेर को चार बराबर भागों में बांट दें। आमने सामने के दो बराबर भागों को वापिस अच्छी तरह से मिला लें। यह प्रक्रिया तब तक दोहराएं जब तक लगभग आधा किलो मृदा न रह जाए। इस प्रकार से एकत्र किया गया नमूना पूरे क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करेगा। नमूने को साफ प्लास्टिक की थैली में डाल दें। अगर मृदा गीली हो तो इसे छाया में सूखा लें। इस नमूने के साथ नमूना सूचना पत्रक जिसमें किसान का नाम व पूरा पता, खेत की पहचान, नमूना लेने कि तिथि, जमीन का ढलान, सिंचाई का उपलब्ध स्रोत, पानी निकास, अगली ली जाने वाली फसल का नाम, पिछले तीन साल की फसलों का ब्यौरा व कोई अन्य समस्या आदि का विवरण, कपड़े की थैली में रखकर इसका मुँह बांधकर कृषि विकास प्रयोगशाला में परिक्षण हेतु भेज देवें। मृदा का नमूना इस तरह से लेना चाहिए जिससे वह पूरे खेत की मृदा का प्रतिनिधित्व करें। जब एक ही खेत में फसल की बडवार में या जमीन के गडन में, रंग व डलान में अंतर हो या फसल अलग-अलग बोयी जानी हो या प्रबंध में अंतर हो तो हर भाग से अलग नमूने लेने चाहिए। यदि उपरोक्त सभी स्थिति खेत में एक जैसी हो तब एक ही नमूना लिया जा सकता है। ध्यान रहे कि एक तमूना ज्यादा से ज्यादा दो हैक्टेयर से लिया जा सकता है।

मृदा का नमूना खाद के डेर, पेडों, मेडों, डलानों व रास्तों के पास से तथा ऐसी जगहों से जो खेत का प्रतिनिधित्व नहीं करती है न लें।

मृदा के नमूने को दूषित न होने दें। इसके लिए साफ औजारों से नमूना एकत्र करें तथा साफ थैली में डालें। अेसी थैली काम में न लाएं जो खाद एवं अन्य रसायनों के लिए प्रयोग में लाई गई हो।

मृदा का नमूना बुआई से लगभग एक माह पूर्व कृषि विकास प्रयोगशाला में भेज दें जिससे समय पर मृदा की जांच रिर्पोट मिल जाएं एवं उसके अनुसार उर्वरक एवं सुधारकों का उपयोग किया जा सके।

यदि खडी फसल में पोषक तत्वों की कमी के लक्षण दिखाई दें और मृदा का नमूना लेना हो तो फसल की कतारों के बीच से नमूना लेना चाहिए।

जिस खेत मे कंपोस्ट, खाद, चूना, जिप्सम तथा अन्य कोई भूमि सुधारक तत्काल डाला गया हो तो उस खेत से नमूना न लें।

मृदा के नमूने के साथ सूचना पत्र अवश्य डालें जिस पर साफ अक्षरों में नमूना संबधित सूचना एवं किसान का पूरा पता लिखा हो।

▶▶ सूक्ष्म तत्वों की जांच के लिए नमूना लेते समय अतिरिक्त सावधानियां

धातु से बने औजारों या बर्तनों को काम में नहीं लाएं क्योंकि इनमें लौह, जस्ता व तांबा होता है। जहां तक संभव हो, प्लास्टिक या लकडी के औजार काम में लें।

यदि मृदा खोदने के लिए फावडा या खुरपी ही काम में लेनी पडे तो वे साफ होनी चाहिए। इसके लिए गडडा बना लें व एक तरफ की परत लकडी के चौडे फट्टे या प्लास्टिक की फट्टी से खुरचकर मृदा बाहर निकाल दें। फिर इस प्लास्टिक या लकडी के फट्टे से 2-3 सेमी मोटी परत उपर से नीचे तक 15 सेमी और पूर्व बताई गई विधि के अनुसार 10-15 जगहों से मृदा एकत्र करके मृदा का नमूना तैयार कर सूचना पत्रक सहित कृषि विकास प्रयोगशाला में भेज दें।

क्या है मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, तथा यह योजना क्यों आवश्यक है

▶▶मृदा स्वास्थ्य कार्ड क्या है?

खेत की मिट्टी में पौधों की समुचित वृद्धि एवं विकास हेतु आवश्यक पोषक तत्वों की उपलब्ध मात्राओं का रासायनिक परीक्षणों द्वारा आंकलन करना, साथ ही विभिन्न मृदा विकार, जैसे- मृदा की लवणीयता, क्षारीयता एवं अम्लीयता आदि की जांच करना मृदा परीक्षण कहलाता है।

मृदा परीक्षण के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान में श्रीगंगानगर जिले के सूरतगढ़ से राष्ट्रीय मृदा स्वास्थ्य कार्ड (एनएसएचसी) योजना की शुरुआत की।

▶▶मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना क्यों आवश्यक है-

कुछ राज्यों में किसानों को उनकी मिट्टी के बारे में रिपोर्ट पहले से दी जा रही थी, जो कि शिक्षित किसान ही प्राप्त करते थे, अशिक्षित किसानों को इस बारे में जानकारी नहीं थी,

उन्हें यह पता नहीं होता था कि इसके लिए क्या दृष्टिकोण होना चाहिए और क्या करना चाहिए। इसलिए सरकार ने सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम लॉन्च किया। इस योजना के द्वारा किसानों को मिट्टी की प्रकृति की जानकारी के साथ कितनी मात्रा में खाद एवं उर्वरक की प्रयोग करें, यह भी जानकारी प्रदान की जाती है।

▶▶ मृदा स्वास्थ्य कार्ड सोइल हेल्थ कार्ड योजना के लाभ इस प्रकार हैं-

01. मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के तहत किसानों की मिट्टी की पूरी तरह से जाँच की जाएगी और उन्हें इसकी रिपोर्ट दी जाएगी। जिससे किसान यह निश्चय कर सकेंगे कि किस फ़सल को विकसित करना चाहिए और किसे छोड़ देना चाहिए।

02. अथॉरिटी नियमित आधार पर मिट्टी की जाँच करेगी। जैसे लवणीयता क्षारीयता और अम्लीयता की पूरी जाँच होगी। हर 3 वर्ष में किसानों को इसकी एक रिपोर्ट दी जाएगी।

यदि किसी कारणवश मिट्टी में बदलाव होते हैं तो किसान को चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमेशा उनकी मिट्टी के बारे में डेटा को अपडेट किया जायेगा।

03. सरकार का यह कार्य बिना रुके मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए उपायों की सूची बनाता रहेगा। यहाँ तक कि विशेषज्ञ किसानों को सुधारात्मक उपाय देने में सहायता भी करेंगे।

04. नियमित रूप से मिट्टी की जाँच होने से किसानों को लम्बे समय तक मिट्टी को स्वस्थ रखने का रिकॉर्ड पाने में मदद मिलेगी। इसके अनुसार वे इसका अध्ययन कर अलग मिट्टी के मैनेजमेंट के तरीकों के परिणामों का मुल्यांकन कर सकेंगे।

05. यह कार्ड बहुत ही मददगार और प्रभावशाली है।

06. मृदा स्वास्थ्य कार्ड किसानों को उनकी मिट्टी में होने वाली कमी भी बतायेगा, जिससे वे यह समझ सकेंगे कि किस फ़सल का निवेश करना चाहिए, और वे यह भी बतायेंगे कि मिट्टी को किस खाद की जरुरत है जिससे अंत में फ़सल की उपज की वृद्धि हो सके।

07. मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का मुख्य उद्देश्य पर्टिकुलर मिट्टी के प्रकार को खोजना है और विशेषज्ञों द्वारा इसमें जो सुधार की आवश्यकता है उसे उपलब्ध कराना है। साथ ही उसमे यदि कुछ कमी है तो उसकी पूर्ति करना है।

▶▶मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का कार्य इस प्रकार है-

सबसे पहले औथौरिटी विभिन्न मिट्टी के सैंपल को इकठ्ठा करेगी। इसके बाद वे इसे लैब में परिक्षण के लिए भेजेगी, और लैब के अंदर विशेषज्ञ इसकी जाँच करेंगे। जाँच के बाद, विशेषज्ञ जाँच के परिणाम का विशलेषण करेंगे। इसके बाद वे विभिन्न मिट्टी के नमूने (सैंपल) की ताकत और कमजोरी की सूची बनायेंगे यदि मिट्टी में कुछ कमी है तो उसके सुधार के लिए सुझाव देंगे और उसकी एक सूची बनायेंगे इसके बाद सरकार किसानों के लिए सोइल कार्ड में फोर्मेटेड तरीके से पूरी जानकारी डाल देगी। यह जानकारी ऐसे तरीके से दी जाएगी जिससे किसान इसे अच्छी तरह एवं सरलता से समझ सकें।

मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना में शामिल कुछ तथ्य

सोइल हेल्थ कार्ड योजना में मिट्टी के नमूने का निरीक्षण किया जाएगा। निरीक्षण करने के बाद सोइल हेल्थ कार्ड में रिपोर्ट तैयार की जाएगी जिससे जिसमें निम्न जानकारी होंगी-

01. मिट्टी का स्वास्थ्य

02. मिट्टी की कार्यात्मक विशेषताएं।

03. मिट्टी में पानी और विभिन्न पोषक तत्वों की उपस्थिति

04. यदि मिट्टी में अतिरिक्त गुण पाए जाते हैं, तो कार्ड में उनकी अलग सूची दी जाएगी।

05. कुछ सुधारात्मक उपाय, जिससे किसान अपनी मिट्टी की खामियों को सुधारने के लिए उपयोग कर सकेगा।

* किसान भाइयों, इस वेब www.soilhealth.dac.gov.in के माध्यम से मृदा नमूनों के पंजीकरण, मृदा नमूनों के परीक्षण परिणामों को दर्ज करने और उर्वरक सिफारिशों के साथ मृदा स्वास्थ्य कार्ड (एसएचसी) को बना सकते हैं।

अमरूद के कीट-रोग

फल मक्खी- यह मक्खी बरसात के फलों को हानि पहुंचाती है। यह फल के अंदर अण्डे देती है जिनमें मेगट पैदा होकर गूदे को फल के अंदर खाते है।

नियंत्रण- ग्रसित फलों को नष्ट करें तथा 0.02 प्रतिशत डायजिनान या 0.05 प्रतिशत से 0.1 % मेलाथियान का छिड़काव करें।

मिलीबग- ये कीड़े नये प्ररोहों पर चिपके रहते है तथा रस चूसते हैं, जिससे फूल पैदा नहीं होते है।

नियंत्रण- 1 भाग निकोटीन सल्फेट, 600 भाग पानी में घोलकर छिड़कें । तथा अधिक ग्रसित शाखाओं की काटछाट कर नष्ट कर दें व मेटासिस्टाक्स 0.05 प्रतिशत का छिड़काव करें।

छाल खाने वाली इल्ली- यह पौधे की शाखाओं में छेद बनाकर छिलका खाती है। प्रभावित प्ररोहों पर काले जाले बन जाते हैं। इन जालों में कीड़ों का मल पदार्थ इकट्ठा होता है। ये इल्लियां इन्ही जालों के अंदर हानि पहुंचाती है।

नियंत्रण- छिद्रों में पेट्रोलियम या 40 प्रतिशत फार्मलीन डालें चाहिए या पेराडाइक्लोरोबेंजीन का चूर्ण छिद्रों में भरकर उनको चिकनी मिट्टी से बंद कर लें।

सूखा रोग- अमरुद उत्पादन में यह सबसे बड़ी समस्या है। इसमें शाखाओं ऊपर से सूखनी शुरू होती है तथा पूरी सूख जाती है तथा बाद में पूरा पौधा सूख जाता है। यह एक कवक द्वारा पैदा होता है। यह वर्षा ऋतु में सबसे अधिक देखा जाता है।

नियंत्रण- प्रभावित भागों को काटकर तुरंत नष्ट कर दें जिससे आसपास के पौधे में यह न फैल सके। पौधे के तनों पर बार्डो पेस्टिंग करें व रिडोमिल 0.2 प्रतिशत दवाई थाले में ड्रेचिंग करें।

फलों का सडना- यह फायटोप्थोरा पेरासिटिका कवक द्वारा होता है। यह अधिक आर्द्रता के कारण पहले फलों पर पानी भरे धब्बे दिखाई पड़ते हैं तथा बाद में पूरे पर फैलकर उसे गला देते हैं।

नियंत्रण- 2-2-50 बोर्डोमिश्रण का छिड़काव करें या डाइथेन जेड 78 0.2 प्रतिशत का पौधों पर छिड़काव करें।

बोर्डेक्स मिश्रण (1%) कैसे बनाए ?

बोर्डेक्स मिश्रण (1%) बनाने के लिए आवश्यक सामान

कॉपर सलफेट (26.6ब्र), बिना बुझा चुना (कैल्शियम ऑक्साइड), जूट बैग, मलमल कपड़े की छलनी या बारीक छलनी , मिट्टी/ प्लास्टिक / लकड़ी की टंकी एवं लकड़ी की छड़ी 7

1.कॉपर सलफेट- 10.0 किलो ग्राम

2.बिना बुझा चूना 5.0 किलो (घोल का पी. एच 7 (pH 7) करने के लिए आवश्यक है)

3.पानी 1000 लीटर

विधि

पानी की आधी मात्रा में कॉपर सलफेट को रात भर भीगो के रखे (टाट की बोरी से मिश्रण को हिलाना कॉपर सलफेट को घुलने में सहायक होता है)7 चूने को भुझावे, शेष आधे पानी में मिलावे एवं बारीक छलनी से छाने दोनों घोल साथ साथ एक चलनी से एक टंकी / स्प्रे टैंक में डाले तथा इस दौरान लकड़ी की छड़ी से लगातार हिलाते रहे

बोर्डेक्स मिश्रण को जाँच करने की विधि

किसानो को इस बात का ध्यान रखना होगा की बोर्डेक्स मिश्रण में कॉपर की अधिकता नहीं होनी चाहिए क्योकि यह पौधो के लिए विषाक्त होती है इस की जाँच के लिए किसान लोहे की कील / चाकू को घोल में कुछ समय के लिए डुबोए किसान को यह ध्यान देना होगा की अगर कॉपर अधिक होगा तो कील / चाकू भूरे / लाल रंग का हो जाएगा कॉपर अधिक होने की स्थिति में किसान को घोल में चूना और अधिक मिलाना चाहिए, जब तक की चाकू/ कील से भूरा / लाल रंग हट नहीं जाता है इस की जाँच की लिए किसान बाजार में उपलब्ध पी. एच. पेपर का भी उपयोग कर सकते है

किसान के ध्यान रखने योग्य बातें

किसानो को बोर्डेक्स मिश्रण का घोल तैयार करने के तुरंत बाद ही इसका उपयोग खेत या बगीचे में कर लेना चाहिए

कॉपर सलफेट का घोल तैयार करते समय किसानो लोहें / गैल्वेनाइज्ड बर्तन को काम में नहीं लेना चाहिए

किसानो को यह ध्यान रखना हो की वे बोर्डेक्स मिश्रण को किसी अन्य रसायन या पेस्टिसाइड के साथ में इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए

उकठा रोग- अमरुद में उकठा रोग का प्रकोप क्षारीय भूमि में जिसका पीएच 7.5 से 9.5 तक हो उसमें अधिक होता है। यह फफूंद के द्वारा फैलता है जिसमें विशेष रुप से फ्यूजेरियम स्पेसीज माक्रोफोमिना फासकोलिना और सेफालोस्पोरियम स्पेसीज प्रमुख है-

रोकथाम-

स्वस्थ पौधों को 0.1 प्रतिशत 8 क्यूनोलीन सल्फेट से इन्हेक्ट करें।

सभी सूखे पौधे और सूखी टहनी को निकाल दें।

मार्च, जून और सितम्बर माह में छटाई करके प्रत्येक पौधे के थाले में बाविस्टीन डाला जाये। रोगग्रसित भाग को काट के बेनोमाईल कार्बेंडाजिम के 20 ग्राम को पानी में घोल बना कर प्रति पौधा डाला जायें।

मुरझाये हुए पौधों में 0.5 प्रतिशत मेटासिस्टाक्स और जिंक सल्फेट के मिश्रण का छिड़काव करें।

किसानो को इस बात का ध्यान रखना होगा की बोर्डेक्स मिश्रण में कॉपर की अधिकता नहीं होनी चाहिए क्योकि यह पौधो के लिए विषाक्त होती है इस की जाँच के लिए किसान लोहे की कील / चाकू को घोल में कुछ समय के लिए डुबोए किसान को यह ध्यान देना होगा की अगर कॉपर अधिक होगा तो कील / चाकू भूरे / लाल रंग का हो जाएगा कॉपर अधिक होने की स्थिति में किसान को घोल में चूना और अधिक मिलाना चाहिए, जब तक की चाकू/ कील से भूरा / लाल रंग हट नहीं जाता है इस की जाँच की लिए किसान बाजार में उपलब्ध पी. एच. पेपर का भी उपयोग कर सकते है

रासायनिक खादों के विकल्प के लिए जैविक खाद

भारतीय कृषि में हरित क्रांति के बाद आधुनिक तकनीक का प्रयोग बढ़ने के साथ-साथ उसी अनुपात में पौध संरक्षण रसायनों व उर्वरकों का उपयोग भी अधिकाधिक होने लगा है। यद्यपि आज देश खाद्यानों के उत्पादन में आत्मनिर्भर हुआ है परन्तु आधुनिक तकनीक में इस्तेमाल होने वाले रसायनों से हमारी मृदा की संरचना तथा वातावरण में भाई असमानता व असंतुलन पैदा हो रहा है। अब हमारे देश में भी अन्य विकसित देशों की भांति कार्बनिक व प्राकृतिक खेती की आवश्यकता महसूस की जा रही है ।

जैविक खेती पूर्ण रूप से प्राकृतिक के वातावरण के साथ जुडी हुई है। यह खेती की एक ऐसी समूह पद्धति है जिसमें उर्वरकों एवं कीटनाशी रसायनों का प्रयोग नहीं किया जाता है। इसमें भूमि की उपजाऊ शक्ति को बनाये रखने के लिए घास-फूस से बनी कम्पोस्ट, शहरी कचरे व गंदे नाले से प्राप्त गली-सड़ी खाद, जीवाणु खाद तथा सूक्ष्म जीवाणुओं से निर्मित खाद, नीम के पौधे के विभिन्न उत्पाद तथा प्रक्रति में पाए जाने वाले अन्य पौधों के उत्पादों से पौध संरक्षण का काम लिया जाता अहि। रसायनों से होने वाले विभिन्न प्रकार के प्रदूषण को रोकने के लिए हमें जैविक संसाधनों पर निर्भर होना पड़ेगा। मैं विषय के दायरे में रह कर यहाँ सिर्फ रासायनिक खादों के विकल्प के बारे में ही बात करूँगा।।

रासायनिक खादों के विकल्प के लिए जैविक खादें

1. **देशी खाद/गोबर की खाद**
2. **हरी खाद**
3. **कचरे (शहरी व ग्रामीण की खाद/कम्पोस्ट**
4. **केंचुआ खाद**
5. **जीवाणु खाद आदि**

देशी खाद अधिकांश किसान गोबर को गौशाला से सीधे ही खेतों में फेक दिया जाता है या फिर खेतों के किनारे पर बिना गड्ढा बनाये ढेर लगा दिया जाता है जिससे गोबर में पाए जाने वाले अधिकांश तत्व वर्षा के पानी से बह जाते हैं फिर कुछ तत्व धूप की गर्मी से उड़ जाते हैं। दूसरी तरफ ये कच्चा गोबर फसलों में विभिन्न प्रकार की बीमारियों एवं कीटों का प्रकोप भी पैदा करता है। अगर किसान भाई इस खाद को गड्ढे में बनाएं तो इसमें विभिन्न पौध पोषण तत्वों की मात्रा दो से तीन गुणा ज्यादा होती है। गड्ढों/ टैंक या तो जमीन से नीचे या सतह के ऊपर बनाये जा सकते हैं। इन गड्ढों में तीन से चार मास के भीतर खाद बनकर तैयार हो जाती है। अच्छी खाद बनाने का ढंग व उसके उचित प्रयोग के बारे में निम्नलिखित बातें अवश्य ध्यान में रखें

सबसे पहले गौशाला से कुछ ही दूरी पर या अपने खेत के एक कोने पर एक या 2 मीटर लम्बा, 2 मीटर चौड़ा तथा के मीटर गहरा गड्ढा खोदें। उसके अंदर की तरफ की मिट्टी को अच्छी तरह से दबाएँ ताकि पानी का कम से कम रिसव हो। उसके बाद रोजाना गोबर और पशुओं के नीचे बिछाएं बचे घास-फूस को गड्ढे में डालते जाएं और जहाँ तक सम्भव हो सके पशुओं के मूत्र को भी उसी गड्ढे में गोबर के साथ-साथ अवश्य डालते रहें मूत्र में गोबर और मूत्र के कुल भाग का 95% पोटाश, 63% नाइट्रोजन और 50% गंधक जैसे तत्व होते हैं। पशुओं के बांधने का ऐसा तरीका भी अपनाया जा सकता हैं कि सभी पशुओं का मूत्र एक नाली से होता हुआ लगातार खाद के गड्ढे में गिरता रहे। यही मूत्र सूखे घास और गेंहू के भूसे के बिछावन में भी सोख लिया जा सकता है। पूरे बिछौने और गोबर को भी गड्ढे में डाला जा सकता है। जब यह गड्ढा भरते-भरते जमीन की सतह से लगभग डेढ़ फुट ऊपर तक भर जाए तो उसमें चार पांच बाल्टी पानी डालकर मिट्टी और गोबर के मिश्रित लेप को एक इंच मोटी तह जमा दें। ऐसा करने से गोबर की खाद में नमी अधिक बनी रहेगी और गलन-सड़न की प्रतिक्रियाएं तेजी से काम करेंगी और मक्खियों का प्रकोप भी कम होगा। चार-पांच मास के बाद खाद तैयार हो जायगी।

जब इस खाद का प्रकोप करना हो तो गड्ढे को फसल की बीजाई से एक महीना पहले खोलकर निरीक्षण करें। अगर खाद पूर्ण रूप से गली-सड़ी न हो तो उसे खेत में बीजाई के दो तीन सप्ताह पहले एक समान रूप से फैलाकर तथा हल चलाकर अच्छी तरह से मिट्टी में मिला दें ताकि सही अर्थ में पोषक तत्वों के भण्डार सिद्ध हो सकें। यदि खाद अच्छी तरह से गली-सड़ी हो तो बीजाई के केवल एक या दो पहले भी खेत में डाली जा सकती है। अति उत्तम गोबर की खाद बनानी हो तो गोबर को गड्ढे में भरते समय कुछ दिनों के अन्तराल पर सिंगल सुपर फास्फेट खाद का बुरकाव करते रहें क्योंकि ऐसा करने से खाद में फास्फोरस तत्व की मात्रा तो बढ़ती ही है साथ में नाइट्रोजन की होने वाली हानि पर भी रोक लग जाती है। यह ध्यान रखें कि केवल गोबर की खाद डालने से फसलों की आवश्यकता के सभी तत्व संतुलित मात्र में उपलब्ध नहीं होते हैं, विशेषकर फास्फोरस इत्यादि। फसलों की अधिकतम पैदावार लेने के लिए रासायनिक खादों का भी सही मात्रा में प्रयोग करें। परन्तु इसके लिए अपने खेती की मिट्टी का परीक्षण जरुर करवाएं।

हरी खाद मृदा के लगातार दोहन से उसमें उपस्थित पौधे की बढ़वार के लिए आवश्यक तत्व नष्ट होते जा रहे हैं। इनकी क्षतिपूर्ति हेतु व् मिट्टी की ऊपजाऊ शक्ति को बनाये रखने के लिए हरी खाद एक उत्तम विकल्प है। बिना गले-सड़े हरे पौधे (दलहनी एवं अन्य फसलों अथवा उनको भाग) को जब मृदा की नत्रजन या जीवांश की मात्रा बढ़ाने के लिए खेत में दबाया जाता है तो इस क्रिया को हरी खाद देना कहते है।

आदर्श हरी खाद फसल के गुण

हरी खाद के मुख्य चार गुण है

क) उगाने में न्यूनतम खर्च

ख) न्यूनतम सिंचाई, कम से कम पादप संरक्षण

ग) खरपतवारों को दबाते हुए जल्दी बढ़त प्राप्त करें तथा विपरीत परिस्थितियों में उगने की क्षमता हो।

घ) कम समय में अधिक मात्रा में वायुमंडलीय नत्रजन का स्थिरीकरण करती हो।

1. हरी खाद केवल नत्रजन व कार्बिनक पदार्थों का ही साधन नहीं है बल्कि नहीं है बल्कि इससे मिट्टी में कई अन्य आवश्यक पोषक तत्व भी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होते हैं।

2. हरी खाद के प्रयोग में मृदा में सुधार एवं मृदा भुरभुरी, वायु संचार में अच्छी, जलधारण क्षमता में वृद्धि, अम्लीयता/क्षारीयता में सुधार एवं मृदा क्षरण में भी कमी होती है।

3. हरी खाद के प्रयोग से मृदा में सूक्ष्मजीवों की संख्या एवं क्रियाशीलता बढ़ती है तथा मृदा की उर्वरा शक्ति एवं उत्पादन क्षमता भी बढ़ती है।

4. हरी खाद में मृदाजनित रोगों में भी कमी आती है।

5. इसके प्रयोग से रासायनिक उर्वरकों में कमी करके भी टिकाऊ खेती कर सकते हैं।

क) फलीदार फसल में पानी की काफी मात्रा होती है परन्तु अन्य फसलों में रेशा काफी होने की वजह से मुख्य फसल (जो हरी खाद के बाद लगानी हो) में नत्रजन की मात्रा काफी कम हो जाती है।

ख) क्योंकि हरी खाद वाली फसल के गलने के लिए नमी आवश्यकता पड़ती है अत: कई बार हरी खाद के पौधे नमी जमीन से लेते हैं जिसके कारण अगली फसल में सूखे वाली परिस्थितियां पैदा हो जाती है।

हरी खाद के व्यवहारिक प्रयोग

क) उन क्षेत्रों में जहाँ नत्रजन तत्व की काफी कमी हो।

ख) जिस क्षेत्र की मिट्टी में नमी की कमी कम हो।

ग) हरी खाद का प्रयोग कम वर्षा वाले क्षेत्र में न करें। इन क्षेत्रों में नमी का संरक्षण मुख्य फसल के लिए अत्यंत आवश्यक है।